JOTI JOURNAL
SUBJECT-INDEX
FEBRUARY-DECEMBER - 2015

From Editor's Desk		1
सम्पादकीय		23
सम्पादकीय		53
सम्पादकीय		63
सम्पादकीय		107
सम्पादकीय		139

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1.	Photographs	3
2.	Photographs	25
3.	Photographs	109
4.	Photographs	141
5.	Direction Issued by Hon'ble Apex Court for speedy disposal of cases under 138 N.I. Act, 1881	106
6.	Duty of the Court in sustaining the sanctity of the Code of Criminal Procedure	27
7.	Hon'ble Shri Justice Gulab Singh Solanki, Hon'ble Shri JusticeTarun Kumar Kaushal and Hon'ble Shri Justice Bhagwan Das Rathi demit office	111
8.	Second Judicial Governance programme jointly organized by State Court of Singapore and Civil Services College Singapore – An Overview	145
9.	Training Calender of MPSJA for the Academic Year 2015-2016 (March 2015 to January 2016)	19
10.	Tribute to Shri B.K. Shrivastava, first Director of the Academy (the then JOTI)	4
11.	Writ Jurisdiction	65
12.	अनुसंधान, जमानत, प्रसंज्ञान और प्रक्रिया अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संदर्भ में	151
13.	एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आपराधिक मामलों में जप्त संपत्ति की अभिरक्षा, विचारण पूर्व व पश्चात् व्ययन	124
14.	धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के बारे में	173
15.	म.प्र. विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 – एक विहंगम दृष्टि	161

16.	मृतक के अविवाहित होने पर गुणांक का चयन	137
17.	भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (धारा 18)	5
18.	विद्युत अधिनियम, 2013 अपराधों का शमन	55
19.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या एन.डी.पी.एस.एक्ट (भाग – 1 एवं 2)	91 & 113

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Section 3 – Whether suit filed by the Secretary on behalf of the plaintiff Public Trust without joining the other trustees as plaintiffs is maintainable? Held, Yes.		
धारा 3 – क्या लोक न्यास की ओर से सचिव द्वारा प्रस्तुत वाद अन्य न्यासियों को संयोजित किये बिना पेश किया गया, वह चलने योग्य है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ।	**62***	**131**
Sections 12 (1)(a) and 12(1)(f) – See Order 3 Rule 2 and Order 18 Rule 4 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 12(1) (ए) और 12(1)(एफ) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3 नियम 2 और आदेश 18 नियम 4।	**224**	**418**
Section – 13 (1) – The term 'tenant' used in section 13 (1) of the Act does not include sub-tenant.		
धारा 13(1) – शब्द 'किरायेदार' जो कि धारा 13 (1) अधिनियम में उपयोग किया गया है उसमें उप–किरायेदार शामिल नहीं होता है।	**1 (i)**	**1**
ADMINISTRATION OF JUSTICE		
न्याय प्रशासन		
Decision making process, attributes of a Judge.		
निर्णय लेने की प्रक्रिया, एक न्यायाधीश की विशेषताएं।	**2**	**3**
ADVOCATES ACT, 1961		
अभिभाषक अधिनियम, 1961		
Sections 35 and 36 – Strike or boycott or token strike by the lawyers – Held, it is violation of law laid down by the Apex Court in ***Ex-Capt. Harish Uppal v. Union of India and others, (2003) 2 SCC 45***.		

धाराएं 35 और 36 – अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल या बहिष्कार या सांकेतिक हड़ताल –
अभिनिर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्स. कैप्टन हरिश उप्पल विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अन्य, (2003) 2 एससीसी 45 में प्रतिपादित विधि का उल्लंघन है। **277** **493**

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996

Sections 2 (1) (e), 11, 34 and 42 – Which Court will have the jurisdiction to entertain and decide an application under section 34 of the Act, 1996?

The reference in this regard is answered by the Court.

धाराएं 2 (1) (इ), 11, 34 और 42 – धारा 34 माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 का आवेदन ग्रहण करने व निराकृत करने की अधिकारिता किस न्यायालय को होगी? इस रिफरेंस का उत्तर देकर न्यायालय कौन सी होगी यह स्पष्ट किया गया। **63*** **131**

Sections 2 (b), 5, 10, 11, 16 and 20 – (i) Arbitration clause contained in main agreement – Plea that main agreement was not concluded contract – Does not make arbitration clause null and void or incapable of being performed.

(ii) Arbitration agreement – Interpretation – Policy of least intervention to be adopted by court – Court has to make arbitration clause workable.

(iii) Arbitration clause – Is an agreement independent of main contract – Rationale behind concept of separability.

(iv) Arbitration clause – Ensuring its workability – Court can add obvious words.

(v) Seat of arbitration.

(vi) Seat of arbitration – Determination.

(vii) Arbitration – Jurisdictional Court.

धाराएं 2 (b), 5, 10, 11, 16 और 20 – (i) मुख्य अनुबंध में माध्यस्थ अनुच्छेद अन्तर्विष्ट – यह अभिवाक् या बचाव की मुख्य अनुबंध में संविदा समाप्त नहीं हुई थी (या संविदा पूर्ण नहीं हुई थी) – यह प्रतिरक्षा माध्यस्थम अनुच्छेद को शून्य और शून्यवत् नहीं बना देती है या पालन से असमर्थ या अयोग्य नहीं बनाती है।

(ii) माध्यस्थम अनुबंध – अर्थान्वयन किया जाना – न्यायालय द्वारा कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनाना चाहिए – न्यायालय को माध्यस्थम अनुच्छेद को व्यावहारिक या प्रचलन योग्य बनाना चाहिए।

(iii) माध्यस्थ अनुच्छेद – मुख्य संविदा से स्वतंत्र एक अनुबंध है – पृथक किये जाने की धारणा के तर्क से परे है।

(iv) माध्यस्थ अनुच्छेद – उसकी प्रचलन शीलता को सुनिश्चित करना – न्यायालय स्पष्ट शब्दों को जोड़ सकती है।

(v) माध्यस्थ की बैठक।

(vi) माध्यस्थ की बैठक – निर्धारण किया जाना।

(vii) माध्यस्थम – क्षेत्राधिकार रखने वाली न्यायालय। **3** **5**

Sections 5 and 34 – (i) When merits of an arbitral award can be looked into by the Court?

Held, when Court finds that the award is in conflict with the public policy of India then in certain specified circumstances, merits of award can be looked into.

(ii) When the award is said to be in conflict with the public policy of India? Explained.

(iii) What are the sub-heads of fundamental policy of India? Explained.

(vi) What are the sub-heads of patent illegality? Explained.

धाराएं 5 और 34 – (i) कब न्यायालय द्वारा माध्यस्थ अवार्ड के गुणदोषों को देखा जा सकता है? अभिनिर्धारित किया गया, जब न्यायालय यह पाती है कि अवार्ड भारत की लोकनीति के विरूद्ध है तब कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अवार्ड के गुणदोषों को देखा जा सकता है।

(ii) कब यह कहा जा सकता है कि अवार्ड भारत की लोकनीति के विरूद्ध है?

(iii) भारत की मूलभूत नीति के उपशीर्ष क्या है?

(iv) प्रत्यक्षतः अवैधता के उपशीर्ष क्या है? **117*** **215**

Sections 7 and 8 – (i) Non-arbitrable dispute referred to arbitrator – Effect of.

(ii) Contract with regard to arbitration – Should be in writing – It cannot be presumed.

धाराएं 7 और 8 – (i) माध्यस्थ द्वारा निपटारा योग्य न होने वाला विवाद माध्यस्थ को निर्देशित – प्रभाव।

(ii) माध्यस्थ के बारे में संविदा – लिखित में होना चाहिए – इसकी (माध्यस्थ अनुबंध की) उपधारणा नहीं की जा सकती। **64** **132**

Section 8 – If an application under section 8 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 is duly filed before the civil court, what should be the approach of the court?

धारा 8 – यदि सिविल न्यायालय के सामने धारा 8 माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन एक आवेदन सम्यक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब न्यायालय का उस पर क्या दृष्टिकोण होना चाहिये?

174* **315**

Sections 16, 34 (2) (b) and 34 (2) (b) (ii) – (i) Objection on jurisdiction of the tribunal – Taking after submission of the statement of defence.

(ii) Challenging the award on the ground that it is in conflict with public policy of India as provided under section 34 (2)(b)(ii).

धाराएं 16, 34 (2) (बी) और धारा 34 (2) (बी) (ii) – (i) अधिकरण के क्षेत्राधिकार की आपत्ति – प्रतिरक्षा का कथन प्रस्तुत कर देने के बाद ऐसी आपत्ति लेना।

(ii) अवार्ड को भारत की लोकनीति के विरूद्ध होने के आधार पर चुनौती देना जो की धारा 34 (2)(बी)(ii) के अधीन है। **65** **133**

Sections 16 and 34 (2) (b) (ii) – "Fundamental policy of Indian law" as a ground to set aside arbitral award in ***ONGC, (2003) 5 SCC 705*** elaborated.

धाराएं 16 और 34 (2)(बी) (ii) – ''भारतीय विधि की मूलभूत नीति'' के आधार पर माध्यस्थम अधिनिर्णय अपास्त करना, न्यायदृष्टांत ***ONGC, (2003) 5 एस.सी.सी. 705*** को सविस्तार प्रतिपादित किया।

4 **10**

Sections 31 (7) (a) and 37 (1) (b) – Word "sum" used in section 31 (7)(a) and 31 (7)(b).

धाराएं 31 (7) (ए) और 31 (7) (बी) – शब्द ''राशि'' जो की धारा 31 (7)(ए) और धारा 31 (7) (बी) में प्रयुक्त हुआ है। **66** **136**

Sections 34 and 37 – Award, setting aside of.

धाराएं 34 और 37 – अवार्ड का अपास्त किया जाना। **278** **494**

Sections 34 and 42 – Jurisdiction of civil court to entertain the application under section 34 of the Act of 1996.

धाराएं 34 और 42 – सिविल न्यायालय का धारा 34 अधिनियम, 1996 के अधीन आवेदन ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार। **175*** **316**

Section 34 (2) – Setting aside of an award – An arbitral award may be set aside only if one of the conditions specified in section 34 (2) of the Act is satisfied.

When the parties have arrived at a concluded contract and acted on the basis of those terms and conditions of the contract then substituting new terms in the contract by the arbitrator or by the court would be erroneous or illegal.

धारा 34 (2) – एक अवार्ड को अपास्त करना एक माध्यस्थ अवार्ड केवल धारा 34(2) अधिनियम में दर्शाई शर्तों में से कोई एक शर्त के (प्रमाणित या) संतुष्ट हो जाने पर ही अपास्त किया जा सकता है।

जहाँ पक्षकार एक concluded contract या अंतिम संविदा पर पहुंच जाते हैं और उसकी शर्तों एवं दशाओं के आधार पर कार्य करते है वहाँ माध्यस्थ द्वारा या न्यायालय द्वारा नई शर्तें संविदा में प्रतिस्थापित करना त्रुटिपूर्ण या अवैध होगा। **222** **417**

Section 34 (2) – Whether provision of section 14 of the Limitation Act, 1963 will apply on an application under section 34 of the Act of 1996? Held, Yes.

धारा 34 (2) – क्या धारा 14 परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान धारा 34 अधिनियम, 1996 के आवेदन पर लागू होंगे? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ। **223*** **417**

BAR COUNCIL OF INDIA (CONDUCT AND DISCIPLINE) RULES

भारतीय अधिवक्ता परिषद (आचरण और अनुशासन) नियम

Rules 4 and 5 – See sections 35 and 36 of the Advocates Act, 1961.

नियम 4 और 5 – देखें अभिभाषक अधिनियम, 1961 की धाराएं 35 और 36। **277** **493**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Sections 3 and 89 – See Muslim Law.

धाराएं 3 और 89 – देखें मुस्लिम विधि। **5** **13**

Section 9 – Maintainability of suit for recovery of money against sick company – The suit could lie and proceed with only after express consent of the BIFR (Board for Industrial and Financial Reconstruction).

धारा 9 – सिक या बीमार कंपनी के विरूद्ध धन वसूली के वाद की पोषणीयता – ऐसा वाद बोर्ड की अभिव्यक्त अनुमति से ही लाया जा सकता है। **67(i)** **137**

Section 9 – See section 8 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

धारा 9 – देखें माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8। **174*** **315**

Section 10 – Section 10 CPC, ingredients of.

Whether filing of written statement is ***sine qua non*** for deciding application under section 10 of CPC?

धारा 10 – धारा 10 सी.पी.सी. के तत्व ।

क्या धारा 10 सी.पी.सी. का आवेदन निराकृत करने के लिए लिखित कथन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक शर्त होती है? **1(ii) &(iii)** **1**

Section 11 – (i) Multiple suits – Disposal of by one common judgment – Decree, finality of – Principle of ***res judicata***, applicability of – Law explained.

(ii) Framing of issues – Duty of Court – Law explained – The obligation and duty to frame issues is solely cast on the Court which may, nevertheless, elicit suggestions from the litigants-adversaries before it.

(iii) Non-framing of issues, effect of.

धारा 11 – (i) कई वाद – एक कामन निर्णय द्वारा निराकृत– डिक्री की अंतिमता – पूर्व न्याय या रेसज्यूडिकेटा के सिंद्धात का लागू होना – विधि समझायी गई।

(ii) वाद पदों की रचना – न्यायालय का कर्त्तव्य – विधि समझायी गई – वाद पद विरचित करने का दायित्व और कर्त्तव्य केवल न्यायालय पर होता है वे अर्थात न्यायालय पक्षकारों से इस बारे में सुझाव ले सकते हैं।

(iii) वाद प्रश्न विरचित न करने का प्रभाव। **118*** **216**

Section 11 and Order 12 Rule 6 – Judgment on admission – Can an issue decided in the previous suit be made the basis for judgment on admission?

धारा 11 और आदेश 12 नियम 6 – स्वीकारोक्ति पर निर्णय – क्या एक विवाद्यक जो पूर्व वाद में निराकृत हो गया हो उसे स्वीकारोक्ति पर निर्णय के लिए आधार बनाया जा सकता है?

279* **495**

Section 79 and Order 1 Rule 9 – Whether Fish Farmers Development Agency, registered under Societies Registration Act, 1860 is a Government Department? Held, No.

If a relief is sought against the State or the Union of India, the State or Union of India must be impleaded as a party. If it is not so impleaded, the suit is not maintainable for want of necessary party. ***AIR 2010 SC 2617*** relied on.

धारा 79 आदेश 1 नियम 9 – क्या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड फिश फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी, एक शासकीय विभाग है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

यदि राज्य या भारत संघ के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा जाता है, तब राज्य या भारत संघ को एक पक्षकार के रूप में जोड़ा ही जाना चाहिए। यदि उन्हें पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाता है तब वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रचलनशील नहीं होता है। ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2617 पर विश्वास किया गया।

6(i) &(ii) **15**

Section 89 – See section 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 and sections 138 and 147 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

धारा 89 – देखें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और 147। **40** **87**

Sections 96, 100, 149, 151 & Orders 7 Rule 11 (c) and Order 41 Rule 33 – (i) Whether deficiency in court fees is curable at appellate stage? Held, Yes.

(ii) Powers of appellate court, scope of.

धाराएं 96, 100, 149, 151 और आदेश 7 नियम 11(सी) और आदेश 41 नियम 33 – (i) क्या न्यायालय शुल्क की अपर्याप्ता को अपील के स्तर पर सुधारा जा सकता है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ।

(ii) अपील न्यायालय की शक्तियों का विस्तार। **119*** **218**

Section 96 and Order 1 Rule 9 – Declaratory decree – Necessary party, who is.

Declaratory decree, non-prayer of appropriate consequential relief, effect of.

धारा 96 और आदेश 1 नियम 9 – घोषणात्मक आज्ञप्ति – आवश्यक पक्षकार कौन होते हैं।

घोषणात्मक आज्ञप्ति, उचित अनुषांगिक अनुतोष की प्रार्थना न करने का प्रभाव। **28(ii) &(iii)** **60**

Section 96 and Order 2 Rule 2 – Applicability of bar under Order 2 Rule 2 of C.P.C., conditions precedent therefor – Law explained.

Plaintiff put in possession under part-performance of contract for sale, filed first suit for permanent injunction restraining defendants from interfering with his possession over suit house – Plaintiff filed subsequent suit for specific performance of agreement for sale of suit house also – Held, cause of action and ingredients for claiming reliefs in both suits are different hence, bar under Order 2 Rule 2 CPC not attracted.

Sale of property to third person (subsequent purchaser) – Rights of person under contract for sale and proper form of decree for enforcement of – Explained.

First appeal – Powers of first appellate court, scope of.

धारा 96 और आदेश 2 नियम 2 – आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के अधीन वर्जन या बाधा के लागू होने की पूर्ववर्ती शर्त – विधि समझाई गई।

वादी को विक्रय की संविदा के भागिक पालन के अधीन संपत्ति के आधिपत्य में रखा गया, उसने वादग्रस्त मकान पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का प्रथम वाद प्रस्तुत किया – वादी ने पश्चातवर्ती वाद वादग्रस्त मकान के विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए प्रस्तुत किया – अभिनिर्धारित किया गया दोनों वाद के वाद कारण और उनमें दावा किये गये अनुतोष के घटक भिन्न है आदेश 2 नियम 2 सीपीसी की बाधा आकर्षित नहीं होती।

तृतीय व्यक्ति (पश्चातवर्ती क्रेता) को संपत्ति का विक्रय – विक्रय की संविदा के अधीन क्रेता के अधिकार और डिक्री का उचित प्रारूप – विधि समझाई गई।

प्रथम अपील न्यायालय की शक्तियों का विस्तार – विधि समझाई गई। **176 (i), (ii), (iii) & (iv)** **316**

Section 96, Order 9 Rule 13, Order 43 Rule 1(d), Order 43 Rule 1(u) and Order 41 Rule 23-A – First appeal and miscellaneous appeal, scope of.

धारा 96, आदेश 9 नियम 13, आदेश 43 नियम 1(डी), आदेश 43 नियम 1 (यू) और आदेश 41 नियम 23–ए – प्रथम अपील और विविध अपील का विस्तार समझाया गया।

7 **17**

Section 99 and Order 1 Rules 9 & 10 – Maintainability of suit – Improper and defective description of parties, non-effect of.

धारा 99 और आदेश 1 नियम 9 और 10 – वाद की प्रचलनशीलता – पक्षकारों के विवरण का अनुचित और त्रुटिपूर्ण होने का प्रभाव न होना। **120*** **219**

Section 149 and Order 41 Rule 3-A – (i) Effect of non-filing of application under Order 41 Rule 3-A CPC for condonation of delay along with memorandum of appeal.

(ii) Appeal filed without any payment of court fees.

(iii) Principles that should be kept in mind while condoning delay.

धारा 149 और आदेश 41 नियम 3.ए – (i) अपील के ज्ञापन के साथ आदेश 41 नियम 3.ए सी.पी.सी. का आवेदन विलंब क्षमा करने के लिये प्रस्तुत न करने का प्रभाव।

(ii) अपील बिना किसी न्यायालय शुल्क के भुगतान के प्रस्तुत की गई।

(iii) विलंब को क्षमा करते समय मस्तिष्क में रखे जाने वाले सिद्धांत । **68** **140**

Section 151 – During pendency of ejectment suit, defendants have been dispossessed from a portion of property – They filed application for restoration of possession after seven months – Same has been rejected by the trial court as well as by the High Court on the ground of delay – Apex Court held that delay in filing of application for restoration of possession cannot be the reason for declining relief.

धारा 151 – निष्कासन के वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति के कुछ भाग से प्रतिवादीगण को आधिपत्य विहीन कर दिया गया था उन्होंने 7 माह के पश्चात् आधिपत्य पुनः स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया – उस आवेदन के विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने विलंब के आधार पर खारिज कर दिया था – माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आधिपत्य के पुनः स्थापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब अनुतोष से इंकार करने का कारण नहीं हो सकता है। **280*** **496**

Section 151 and Order 22 Rule 4 – See section 5 of the Limitation Act, 1963.

धारा 151 और आदेश 22 नियम 4 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1955 की धारा 5।

281* **496**

Section 152 – (i) Scope of section 152 of CPC – Only accidental omissions or mistakes may be corrected – Not all omissions and mistakes.

(ii) In this case, High Court has allowed the application under section 152 CPC and directed that preliminary decree be amended – In the light of Order 20 Rule 18 (2) CPC in preliminary decree, not only the right of the plaintiff but also the rights and interests of others can also be declared – The Apex Court held High Court had not committed any mistake of law.

धारा 152 – (i) धारा 152 सी.पी.सी. का विस्तार – केवल आकस्मिक भूल या त्रुटि सुधारी जा सकती है – सभी भूल और त्रुटियाँ नहीं।

(ii) इस मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 152 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार किया और ये निर्देश दिये कि प्रारंभिक आज्ञप्ति में संशोधन किया जाये। आदेश 20 नियम 18 (2) सी.पी.सी. के प्रकाश में प्रारंभिक डिक्री में न केवल वादी के अधिकार बल्कि अन्य पक्षकारों के अधिकार और हित भी घोषित किये जा सकते है – सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया की उच्च न्यायालय ने ऐसा करके कोई विधि की त्रुटि नहीं की है।

69 **143**

Order 1 Rule 10 – Eviction suit – Necessary party – Law explained.

आदेश 1 नियम 10 – निष्काषन का वाद – आवश्यक पक्षकार – विधि समझाई गई।

282 **500**

Order 1 Rule 10 – Joinder of party – Addition of party resulting in triangular fight – Cannot be allowed.

आदेश 1 नियम 10 – पक्षकार का संयोजित किया जाना – यदि पक्षकार को जोड़े जाने का परिणाम विवाद को त्रिपक्षीय बना देता हो तब पक्षकार के जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

121 **219**

Order 1 Rule 10 – Suit relating to trust property – Applicant who is a beneficiary of the Trust filed application under Order 1 Rule 10 CPC for making him party – He is not a stranger to the dispute but a proper party – Application allowed.

आदेश 1 नियम 10 – न्यास की संपत्ति संबंधी वाद – न्यास के एक हितग्राही ने आदेश 1 नियम 10 सी.पीसी. का आवेदन स्वयं को पक्षकार बनाने का प्रस्तुत किया – वह विवाद के लिये एक अंजान व्यक्ति या स्ट्रेंजर नहीं है बल्कि एक उचित पक्षकार है – आवेदन स्वीकार किया गया।

122* **221**

Order 2 Rule 2 – Order 2 Rule 2 CPC, applicability of.

आदेश 2 नियम 2 – आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का लागू होना। **325 (ii)** **580**

Order 3 Rules 1 & 4 and Order 23 Rule 3 – (i) Compromise/settlement by counsel, permissibility and requirement of – Power of counsel depends on authority conferred by party by way of appointment in writing (Vakalatnama) and instruction given by him – Principles summarized.

(ii) Challenge as to validity of compromise, forum therefor.

आदेश 3 नियम 1 और 4 तथा आदेश 23 नियम 3 – (i) अभिभाषक द्वारा समझौता/ सेटलमेंट का अनुमत होना और (उसके लिए) अनिवार्यताएँ – अभिभाषक की शक्ति पक्षकार द्वारा लिखित नियुक्ति (वकालत नामा) में दिये गये प्राधिकार और उसके द्वारा दिये गये निर्देश पर निर्भर करती है – सिद्धांत संक्षिप्त में बतलाये गये।

(ii) समझौते की वैधता को चुनौती देने का फोरम (या मंच)। **283** **502**

Order 3 Rule 2 and Order 18 Rule 4 – Whether the power of attorney holder, who is also son of the landlord, can depose in place of landlord for factum of bona fide need?

Fact of non-payment of arrears of rent – May be within the personal knowledge of landlord or it may be within the knowledge of the power of attorney-holder.

आदेश 3 नियम 2 और आदेश 18 नियम 4 – क्या मुख्तयारनामा धारक, जो कि मकान मालिक का पुत्र भी है, मकान मालिक के स्थान पर, सद्भाविक आवश्यकता के तथ्य के लिये, कथन दे सकता है।

बकाया किराया भुगतान न करने का तथ्य मकान मालिक के व्यक्तिगत ज्ञान में हो सकता है या मुख्तयार नामा धारक के ज्ञान में हो सकता हैं। **224** **418**

Order 6 Rule 17 – Amendment after commencement of trial, permissibility of.

आदेश 6 नियम 17 – विचारण प्रारंभ होने के बाद के संशोधन की अनुमति।

8* **19**

Order 6 Rule 17 – Amendment in written statement – Defendant tried to withdraw an admission after closure of the trial without any sufficient reason – He was aware of the facts previously – Application rightly rejected by the trial Court.

आदेश 6 नियम 17 – लिखित कथन में संशोधन – प्रतिवादी ने बिना किसी पर्याप्त कारण के विचारण समाप्त होने के बाद एक स्वीकारोक्ति वापस लेने का प्रयास किया – वह तथ्यों को पहले से जानता था – विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन सही रूप से खारिज किया गया।

177 **326**

Order 6 Rule 17 – Amendment of plaint.

आदेश 6 नियम 17 – वाद पत्र में संशोधन । **284*** **508**

Order 6 Rule 17 – Application under Order 6 Rule 17 CPC, determination of.

आदेश 6 नियम 17 – आदेश 6 नियम 17 के आवेदन का निराकरण। **324 (ii) 576**

Order 6 Rule 17 – Prayer for amendment contrary to the basic pleading made after seeking several adjournments with an aim to procrastinate the trial – Is impermissible

आदेश 6 नियम 17 – संशोधन की प्रार्थना जो कि मूल अभिवचनों के विरूद्ध है कई स्थगन लेने के बाद विचारण को विलंबित करने के उद्देश्य से की गई – यह (संशोधन की प्रार्थना) अनुमति योग्य नहीं है। **123* 221**

Order 6 Rule 17 Proviso – Application for post-trial amendments, permissibility of – Law stated.

आदेश 6 नियम 17 का परन्तुक – विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाना – विधि बतलायी गयी। **9* 20**

Order 6 Rule 17 and Order 18 Rule 4 – (i) Pre-trial amendments, permissibility of.

(ii) Date of first hearing and commencement of proceedings, connotation of.

आदेश 6 नियम 17 और आदेश 18 नियम 4 – (i) विचारण प्रारंभ होने के पूर्व संशोधन की अनुमति दिया जाना।

(ii) सुनवायी की प्रथम तिथि और कार्यवाही के प्रारंभ होने का अर्थ। **10 21**

Order 7 Rule 3 – Suit for the relief of permanent prohibitory injunction – Effect of non-mentioning the length and width of the suit land.

आदेश 7 नियम 3 – स्थायी निषेधात्मक व्यादेश के अनुतोष का वाद – वाद संपत्ति की लंबाई व चौड़ाई (वाद पत्र में) दर्ज न करने का प्रभाव। **124 221**

Order 7 Rule 10 – Return of plaint, procedure for.

Court must return the plaint if it comes to the conclusion that it has no jurisdiction except deciding the suit on merit.

आदेश 7 नियम 10 – वाद लौटाने की प्रक्रिया।

यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसे क्षेत्राधिकार नहीं है तब उसे वाद गुण–दोष पर निराकरण करने के बजाय लौटा देना चाहिए। **285 509**

Order 7 Rule 11 – See section 7 (iv) and Entry (iii) of Schedule II of the Court Fees Act, 1870.

आदेश 7 नियम 11 – देखे न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (iv) और अनुच्छेद 2 की एन्ट्री (iii)। **13* 28**

Order 7 Rule 11 – Where the issue of limitation is a mixed question of fact and law, it can be decided only after framing of issues and recording of evidence – Plaint cannot be rejected under Order 7 Rule 11 CPC.

आदेश 7 नियम 11 – जहाँ परिसीमा का बिन्दू तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न हो जो वादप्रश्न विरचित करने और साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् ही निराकृत किया जा सकता है – वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। **225* 420**

Order 7 Rule 11 (d) – Stage of raising objection regarding non-maintainability of suit being barred by law.

आदेश 7 नियम 11 (डी) – वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रचलन योग्य न होने के संबंध में आपत्ति उठाने का प्रक्रम। **178*** **327**

Order 7 Rule 11 (d) – Bar against suit, applicability of – Law explained.

आदेश 7 नियम 11 (डी) – वाद के विरूद्ध वर्जन के लागू होने के बारे में विधि स्पष्ट की गयी।

11* **23**

Order 7 Rule 11 and Order 6 Rule 17 – See section 7 (vi-a) of the Court Fees Act, 1870.

आदेश 7 नियम 11 और आदेश 6 नियम 17 – देखें न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (vi-a)।

14 **29**

Order 9 Rule 7 and Section 151 – An application under Order 9 Rule 7 CPC for setting aside ***ex parte*** proceeding was rejected by the trial Court – Defendant produced another application under section 151 CPC with the prayer for permission to participate in further proceeding in the suit as also for taking W.S. and documents on record.

आदेश 9 नियम 7 और धारा 151 – एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिये आदेश 9 नियम 7 सी.पी. सी. का एक आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया – प्रतिवादी ने एक अन्य आवेदन धारा 151 सी.पी.सी. के अधीन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया कि उसे वाद की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाये और उसका लिखित कथन और दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाये।

226* **420**

Order 9 Rule 13 and Order 43 Rule 1 – A claim case was awarded ***ex parte*** by Additional Member, MACT – Application filed under Order 9 Rule 13 CPC was also rejected by him – High Court allowed Misc. Appeal and held that to do substantial justice between the parties expression "sufficient cause" should be construed liberally – Condition to deposit 50% award amount and Rs. 5,000/- as cost imposed upon the non-applicant.

आदेश 9 नियम 13 और आदेश 43 नियम 1 – अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक दावा प्रकरण एकपक्षीय अवार्ड किया – आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के अधीन प्रस्तुत आवेदन भी उन्होंने निरस्त कर दिया – उच्च न्यायालय ने विविध अपील स्वीकार की और अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच तात्विक न्याय करने के लिए अभिव्यक्ति ''पर्याप्त कारण'' का उदारतापूर्वक अर्थ लगाना चाहिए – अवार्ड राशि का 50 प्रतिशत व 5000/– खर्च जमा करवाने की शर्त अनावेदक पर लगाई गई। **227*** **421**

Order 11 Rule 14 – Power to direct a party to produce documents, conditions stated therefor.

आदेश 11 नियम 14 – एक पक्षकार को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देने की शक्ति के प्रयोग के लिये शर्तें बतलाई गई। **125** **223**

Order 12 Rule 6 – Nature of provision – It is discretionary.

आदेश 12 नियम 6 — प्रावधान की प्रकृति — यह वैवेकिय है। **286*** **511**

Order 13 Rule 4 – Objection regarding admissibility of a document and proper stage for deciding such objection.

आदेश 13 नियम 4 — दस्तावेज की ग्राह्यता संबंधी आपत्ति — ऐसी आपत्ती के निराकरण का उचित प्रक्रम। **228** **421**

Order 16 Rule 2 – Plaintiff claimed mesne profits – He wants to prove the prevalent market rate of the properties in the locality – Filed application under Order 16 Rule 2 CPC – Trial court rejected the same on the ground that under Section 10 of M.P. Accommodation Control Act, 1961 the plaintiff has remedy to approach RCA for fixation of standard rent – Held, the trial court has lost sight of the fact that section 10 of the Act has no application to the facts of the case as the plaintiff is not claiming standard rent – Order of trial court reversed.

आदेश 16 नियम 2 — वादी ने अंतर्वती लाभ का दावा किया — वह उस क्षेत्र में संपत्तियों की प्रचलित बाजार दर प्रमाणित करना चाहता है — उसने आदेश 16 नियम 2 सी.पी.सी. का आवेदन दिया — विचारण न्यायालय ने आवेदन इस आधार पर निरस्त किया की वादी को धारा 10 म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के तहत मानक किराया निर्धारित करवाने के लिये आर.सी.ए. के पास जाने का उपचार उपलब्ध है — अभिनिर्धारित किया गया, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि प्रकरण के तथ्यों में धारा 10 अधिनियम लागू नहीं होती है क्योंकि वादी ने मानक किराये का दावा नहीं किया है — विचारण न्यायालय का आदेश उलट दिया गया। **70** **145**

Order 18 Rule 3 – Evidence where there are several issues – Right to rebuttal on a particular issue – When can be reserved by a party?

आदेश 18 नियम 3 — जहां कई वाद प्रश्न हैं वहां साक्ष्य — एक वादप्रश्न विशेष पर खंडन का अधिकार — एक पक्षकार द्वारा कब सुरक्षित किया जा सकता है? **179** **327**

Order 21 Rule 97 – Application under Order 21 Rule 97 of the Code, procedure therefor.

आदेश 21 नियम 97 — आदेश 21 नियम 97 के आवेदन पर प्रक्रिया। **126*** **223**

Order 21 Rules 97, 99, 100, 101 103 and 107 – Resistance or obstruction for possession of immovable property by third party, maintainability of.

Appealable decree/deemed decree and non-appealable order – Law explained.

आदेश 21 नियम 97, 99, 100, 101, 103 और 107 — तृतीय पक्ष द्वारा अचल संपत्ति के आधिपत्य लेने में प्रतिरोध या बाधा की प्रचलनशीलता।

अपील योग्य आज्ञप्ति, डीम्ड डिक्री और अपील योग्य न होने वाले आदेश के बारे में विधि समझाई गई। **127** **224**

Order 22 Rules 2, 4 & 6, Order 47 Rule 1 and Section 100 – Death of plaintiff(s) or defendant(s) – Duty of the Court.

(ii) Death during pendency of appeal, effect of.

(iii) (a) Dispute as to legal representatives, determination of.

(b) Determination of dispute as to legal representative, scope of.

(c) Order 47 Rule 1 – Review, grounds for.

आदेश 22 नियम 2, 4 और 6, आदेश 47 नियम 1 और धारा 100 – वादीगण या प्रतिवादी गण की मृत्यु – न्यायालय का कर्त्तव्य।

(ii) अपील के लम्बित रहने के दौरान मृत्यु का प्रभाव।

(iii) (a) वैध प्रतिनिधियों संबंधी विवाद का निर्धारण।

(b) वैध प्रतिनिधि संबंधी विवाद के निर्धारण का विस्तार।

(c) आदेश 47 नियम 1 – पुनरावलोकन के आधार। **12** **24**

Order 22 Rule 4 – Death of defendant – Appeal, abatement of – Law explained.

आदेश 22 नियम 4 – प्रतिवादी की मृत्यु – अपील का उपशमित होना – विधि समझाई गई।

180* **328**

Order 22 Rules 4 and 5 – Defendant died during pendency of appeal – Appellate court allowed the application under Order 22 Rule 4 CPC without proper inquiry – Hon'ble the Apex Court held that after following proper procedure prescribed in Order 22 Rule 5 CPC, the appellate court should have decided, who are the LRs of deceased and under what capacity – Before deciding this material question the appellate court cannot proceed to decide the appeal on merits – It may take recourse to proviso of Order 22 Rule 5 CPC.

आदेश 22 नियम 4 और 5 – अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु हुई – अपील न्यायालय में आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन उचित जाँच के बिना स्वीकार कर लिया – सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की अपील न्यायालय को आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करके यह निर्धारित करना चाहिये की कौन मृतक का विधिक प्रतिनिधि है और किस हैसियत से है – इस तात्विक प्रश्न के निराकरण के पूर्व अपील न्यायालय अपील में आगे कार्यवाही नहीं कर सकती और अपील को गुणदोष पर निराकृत नहीं कर सकती – वह आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के परंतुक का सहारा भी ले सकती है।

71(i) **146**

Order 23 Rule 3 – See section 12 (2) of the Land Acquisition Act, 1894 and section 23 of the Contract Act, 1872.

आदेश 23 नियम 3 – देखें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12(2) और संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23। **321** **571**

Order 23 Rule 3 – The property which is not the subject-matter of the suit but related to the parties to the suit, compromise in this respect may be arrived at in the Court and compromise decree may be passed if it is arrived at by lawful agreement.

आदेश 23 नियम 3 – संपत्ति जो वाद की विषय वस्तु नहीं है लेकिन वाद के पक्षकारों से संबंधित है, उस संपत्ति के लिए भी न्यायालय में समझौता किया जा सकता है और समझौते के आधार पर आज्ञप्ति पारित की जा सकती है यदि वह (समझौता) वैध अनुबंध के आधार पर किया हो।

287* **511**

Order 23 Rule 3-A – Can the validity of a decree passed on a compromise be challenged in a separate suit?

आदेश 23 नियम 3–ए – क्या एक समझौते के आधार पर पारित आज्ञप्ति की वैधानिकता को एक पृथक वाद द्वारा चुनौती दी जा सकती है? **72** **149**

Order 26 Rule 9 – In a suit for declaration and injunction, there is no agreed map on record and question involved in the matter is that in what survey number the road is moving – In that situation, order to appoint Commissioner will not amount to exercise of collecting the evidence but it will facilitate the Court to separate the wheat from the chaff.

आदेश 26 नियम 9 – घोषणा और निषेधाज्ञा के एक वाद में स्वीकृत मानचित्र अभिलेख पर नहीं था – मामले में अंतरग्रस्त प्रश्न यह था कि सड़क किस सर्वे नंबर से गुजरती है – ऐसी स्थिति में कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश साक्ष्य संग्रहित करने के समान नहीं होगा बल्कि इससे न्यायालय को भूसे से दाना पृथक करने में सहायता होगी। **229*** **425**

Order 26 Rule 9 – Interim application for appointment of Commissioner in appeal, determination of.

आदेश 26 नियम 9 – अपील में कमीश्नर नियुक्ति के लिये अंतरिम आवेदन का निर्धारण किया जाना।

128 **229**

Order 30 Rule 10 – What is sole proprietorship concern?

आदेश 30 नियम 10 – एक सोल प्रोपराइटरशिप कनसर्न क्या है? **73*** **150**

Order 39 Rules 1 and 2 – Injunction in an appeal against decree passed in suit for specific performance of contract, grant of.

आदेश 39 नियम 1 और 2 – संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में पारित डिक्री के विरूद्ध अपील में निषेधाज्ञा दिया जाना। **55*** **120**

Order 39 Rules 1 and 2 – See section 41 (b) of the Specific Relief Act, 1963.

आदेश 39 नियम 1 और 2 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41 (बी)।

129 **231**

Order 39 Rules 1 and 2 – Temporary injunction against alienation – Held, to prevent complications resulting from creation of third party interest, injunction can be granted against creation of such interest.

आदेश 39 नियम 1 और 2 – अंतरण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा – अभिनिर्धारित किया गया, जटिलता को रोकने जो कि तृतीय पक्ष के हित सृजित होने के परिणाम से होगी, निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

130 **232**

Order 39 Rules 1 and 2 – (i) Temporary Injunction – Being an equitable and discretionary relief – Cannot be granted as a matter of course or on mere asking.

(ii) Possession of trespasser cannot be protected – Possession must be legal.

आदेश 39 नियम 1 और 2 – (i) अस्थाई व्यादेश – एक साम्यपूर्ण और विवेकीय अनुतोष – केवल मांगा है या सहज में नहीं दिया जा सकता।

(ii) अतिक्रमण कर्ता का आधिपत्य सुरक्षित नहीं रखा जा सकता आधिपत्य वैध होना चाहिए।

181 **329**

Order 39 Rule 2-A – Whether fine can be imposed under Order 39 Rule 2–A CPC? Held, No.

आदेश 39 नियम 2–ए – क्या आदेश 39 नियम 2–ए सी.पी.सी. के अधीन अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **230** **425**

Order 40 Rule 1 – Object of appointment of Receiver and his tenure.

आदेश 40 नियम 1 – प्रापक या रिसीवर नियुक्त करने का उददेश्य और उसकी अवधि।

182 **330**

Order 41 Rule 23-A and Order 43 Rule1 (u) – Passing order of remand by appellate court – Though discretionary but should not be passed routinely – Twin requirements must be there.

आदेश 41 नियम 23–ए और आदेश 43 नियम 1(यू) – अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण या रिमांड का आदेश पारित करना – यद्यपि विवेकीय है लेकिन रूटिन में पारित नहीं करना चाहिए – दो शर्तें होना आवश्यक है।

183 **332**

Order 41 Rules 31 and 33 – Duties of first appellate court, explained.

आदेश 41 नियम 31 व 33 – प्रथम अपील न्यायालय के कर्त्तव्य। **131(ii)** **233**

Order 47 Rule 1 – Review of an order.

आदेश 47 नियम 1 – एक आदेश का पुनरावलोकन। **231** **426**

CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

Articles 12, 14 and 300 – Equality before law – Undue or wrong benefit has been granted to someone inadvertently or by mistake – It may not be a ground to grant similar relief to others – Article 14 of the Constitution of India does not envisage for negative equality.

अनुच्छेद 12, 14 और 300 – कानून के समक्ष समानता – अनुचित या गलत लाभ असावधानी से (अनजाने में) या त्रुटिवश किसी को दे दिया गया है – यह किसी अन्य को समान सहायता देने का एक आधार नहीं हो सकता है – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता पर ध्यान देने या उस पर विचार करने के लिए नहीं है। **6(iii) 15**

Articles 14, 15 and 39 (d) – See Rules 9 and 11-A of the Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003.

अनुच्छेद 14, 15 और 39 (डी) – देखें न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम 2003 का नियम 9 और 11–ए। **98* 189**

Articles 14, 15 and 44 – See section 41 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

अनुच्छेद 14, 15 और 44 – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41। **38 85**

Articles 19 (1) (a) and 19 (2) – Freedom of speech and expression, reasonable restriction thereto – Public decency and morality – Obscenity, test of – Charge under section 292 IPC, maintainability of.

अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (2) – वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध – लोकशालीनता और नैतिकता – अशलीलता का परीक्षण – धारा 292 भ.दं.सं. के आरोप की प्रचलन शीलता – विधि समझाई गई। **288* 512**

Article 20(2) – See sections 4 (1-A), 21 and 22 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

अनुच्छेद 20 (2) – देखें माइन्स एवं मिनरल्स (डेवलपमेंट एडं रेग्युलेशन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1–ए), 21 और 22 **36 76**

Article 39-A – See section 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 and sections 138 and 147 of the Negotiable Instruments Act, 1881

अनुच्छेद 39–ए – देखें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और 147 **40 87**

Article 141 – Law of precedent – Judgments of Apex Court – ***Ratio decidendi,*** determination of.

अनुच्छेद 141 – पूर्व निर्णय की विधि – सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय – रेशियों डेसीडेन्डी का निर्धारण।

184* **333**

Articles 226 and 227 – (i) Whether judicial orders of the civil Court are amenable to writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution? Held, No.

(ii) Jurisdiction under Article 227 is distinct from jurisdiction under Article 226.

(iii) Writ of mandamus does not lie against a private person – Not discharging any public duty.

(iv) ***Surya Dev Rai v. Ram Chander Rai, (2003) 6 SCC 675*** overruled.

अनुच्छेद 226 और 227 – (i) क्या सिविल न्यायालय के न्यायिक आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट क्षेत्राधिकार में परीक्षण योग्य हैं? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) अनुच्छेद 227 का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार से भिन्न होता है।

(iii) एक निजी व्यक्ति, जो कोई लोक कृत्य का निर्वाहन नहीं करता है, उसके विरूद्ध समादेश याचिका चलने योग्य नहीं होती है।

(iv) सूर्यदेव राय वि. रामचंद्र राय, (2003) 6 एस.सी.सी. 675 को ओवररूल्ड किया गया।

185* **334**

Article 227 – See Order 6 Rule 17 and Order 18 Rule 4 of the Civil Procedure Code, 1908.

अनुच्छेद 227 – देखे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 17 और आदेश 18 नियम 4।

10 **21**

Article 227 – See section 7 (vi-a) of the Court Fees Act, 1870.

अनुच्छेद 227 – देखें न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (vi-a)। **14** **29**

Article 227 – See sections 63, 65 (c) and 66 of the Evidence Act, 1872.

अनुच्छेद 227 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 63, 65 (सी) एवं 66। **25** **49**

Article 246 – (i) Power of legislature, scope and competence of.

(ii) Doctrine of separation of powers, applicability of.

(iii) Transfer of Judicial Power – Permissibility and requirement of.

अनुच्छेद 246 – (i) विधायिका की शक्तियों का विस्तार और सक्षमता।

(ii) शक्तियों के पृथक करण के सिद्धांत का लागू होना।

(iii) न्यायिक शक्तियों के अंतरण की अनुमति और अनिवार्यताएँ। **186** **334**

Article 363 – Article 363 of the Constitution of India, applicability of – Suit for declaration of title by successor of Ex-Ruler of Holkar State, maintainability of.

अनुच्छेद 363 – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 का लागू होना – होल्कर राज्य के पूर्व शासक के उत्ताधिकारी द्वारा स्वत्व घोषणा के लिए वाद की प्रचलनशीलता।

289(i)* **512**

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1961 (M.P.)

मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1961

Section 64 (1) (c) – Respondents were agriculturists who had agreed to sell agricultural land to the appellant housing co-operative society – Whether it is a "business transaction" covered under section 64(1)(c) of the Act of 1961 and any dispute arising out of that contract for sale is amenable to adjudication under section 64 of the Act of 1961?

धारा 64 (1) (सी) – प्रत्यर्थीगण कृषक थे जो कृषि भूमि अपीलार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय करने को तैयार हुए – क्या यह एक ''व्यापारिक संव्यवहार'' है जो धारा 64 (1) (सी) अधिनियम, 1961 में आता है और क्या इस विक्रय संविदा से उत्पन्न कोई विवाद धारा 64 अधिनियम, 1961 के तहत निराकृत करने योग्य होता है? **290*** **513**

Sections 64 and 82 – See Order 7 Rule 11(d) of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 64 और 82 – देखे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11(डी)।

11* **23**

CONTRACT ACT, 1872

संविदा अधिनियम, 1872

Section 15 – Agreement to sale – Free consent – Coercion, connotation of – What may amount to?

धारा 15 – विक्रय करार – स्वतंत्र सहमति – प्रपीड़न का अर्थ – क्या प्रपीड़न के समान है?

56* **121**

Section 23 – A Society has entered into an agreement to sell with a person of the Scheduled Caste – A compromise decree has been passed by the court for specific performance of contract – A society is a juristic person – Person includes juristic person also – The transaction is ab initio void by virtue of specific provision of section 42 of the Rajasthan Tenancy Act,1955 – Society gets no advantage of such void transaction.

धारा 23 – एक समिति ने एक व्यक्ति के साथ विक्रय अनुबंध किया – जो अनुसुचित जाति का सदस्य है – न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति पारित की गई – एक समिति एक विधिक व्यक्ति होती है – व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी शामिल होता

है – संव्यवहार धारा 42 राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 के विशिष्ट प्रावधान के प्रकाश में आरंभ से अंत तक शून्य है समिति को ऐसे शून्य संव्यवहार से कोई लाभ नहीं मिलता है।

321(ii) 517

Section 55 – Whether time is essence of contract? Determination of.

धारा 55 – क्या समय संविदा का सार है? निर्धारण। **176 (iv) 316**

COURT FEES ACT, 1870

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

Section 7 (iv) and Entry (iii) of Schedule II – Suit for declaration that sale deed is a forged and fabricated document prepared in collusion with others and for permanent injunction – Court fees, payment of – Law stated.

धारा 7 (iv) और अनुच्छेद 2 की एन्ट्री (iii) – इस घोषणा के लिए वाद की विक्रय पत्र जाली और अन्य के साथ दुर्भीसंधि करके तैयार किया गया कूटरचित दस्तावेज है तथा स्थायी निषेधाज्ञा – न्यायालय शुल्क अदायगी की विधि समझायी गयी। **13* 28**

Section 7 (vi-a) – Suit for declaration, partition and possession of suit house – Court fees, payment of.

धारा 7 (vi-a) – घोषणा, विभाजन और आधिपत्य का वादग्रस्त मकान का वाद – न्यायालय शुल्क का भुगतान। **14 29**

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Sections 2 (d) and 154 – Police Officer on deputation, powers of – Inspector of Police deputed to Lokayukat can suo motu register FIR after being satisfied with the material facts published in the newspaper that there is a cognizable offence to be investigated by the police against the suspect/accused and may investigate the matter in accordance with law.

धाराएं 2 (डी) और 154 – प्रतिनियुक्ति पर होने पर पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ – पुलिस निरीक्षक को लोकायुक्त में प्रतिनियुक्ति किया गया वह स्वतः ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर सकता है यदि वह समाचार में प्रकाशित तात्विक तथ्यों से इस बारे में संतुष्ट होता है कि एक संज्ञेय अपराध है जिसका पुलिस द्वारा संदेही/आरोपी के विरूद्ध अनुसंधान होना है और वह विधि अनुसार मामले का अनुसंधान कर सकता है।

187 338

Section 31 – How to run sentences where there is one trial and the accused is convicted in two or more offences?

धारा 31 – जहां एक विचारण में अभियुक्त को दो या दो से अधिक अपराधों में दोषसिद्ध किया जाता है – दण्ड कैसे चलेंगे (भुगताए जाएंगे)। **74 150**

Section 31 – The Apex Court held that the expressions 'concurrently' and 'consecutively' mentioned in the Cr.P.C. are of immense significance while awarding punishment to the accused for offences punishable under IPC and any other Special Act arising out of one trial or more – Award of former enure to the benefit of the accused whereas award of latter is detrimental to the accused's interest – So, it is legally obligatory upon the trial court to specify in clear terms in the order of conviction as to whether sentences awarded to the accused would run concurrently or consecutively.

धारा 31 – माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित अभिव्यक्ति साथ साथ और एक के बाद एक का अत्यधिक महत्व उस समय होता है जब अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध और विशेष अधिनियम के अधीन उत्पन्न अपराध में एक या अधिक विचारण में दंड दिया जाता है – पूर्व वाला (अर्थात दण्ड साथ साथ चलेंगे) अभियुक्त के लाभ के लिये होता है जबकि बाद वाला (अर्थात दण्ड एक के बाद एक चलेंगे) अभियुक्त के हितों के लिये नुकसानदायक होता है – इस कारण विचारण न्यायालय पर यह विधिक दायित्व होता है कि वह दोषसिद्धि के आदेश में यह विशेष रूप से उल्लेख करें कि क्या दण्ड साथ–साथ चलेंगे या एक के बाद एक भुगताए जायेंगे। **188*** **339**

Section 53-A – Medical examination of accused during investigation – Prosecution filed application under section 53-A Cr.P.C. opposed by accused.

धारा 53–ए – अनुसंधान के दौरान अभियुक्त का चिकित्सा परीक्षण – अभियोजन ने धारा 53–ए द.प्र.सं. के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया – अभियुक्त ने उसका विरोध किया। **97*** **188**

Sections 91 and 92 – Accused filed an application under sections 91 and 92 Cr.P.C. for preserving record of call details of officers of raiding party.

धाराएं 91 और 92 – अभियुक्त ने एक आवेदन धारा 91 और 92 द.प्र.सं. के अधीन, छापादल के अधिकारियों के काल डिटेल्स के अभिलेख को संरक्षित रखने के लिए पेश किया। **241** **444**

Sections 93 and 165 – See sections 3 and 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धाराएं 93 एवं 165 – देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 3 और 4। **232** **427**

Section 125 – Filing of application for maintenance, limitation therefor.

Second marriage, proof of – Cogent evidence is required to be adduced.

Maintenance, eligibility therefor.

धारा 125 – भरण पोषण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा।

द्वितीय विवाह का प्रमाण – इसके लिये अकाट्य प्रमाण आवश्यक होता है।

भरण पोषण के लिये पात्रता। **132*** **234**

Section 125 – (i) Maintenance under section 125 CrPC, ingredients and entitlement of.

(ii) Proceedings under section 125 CrPC – Inquiry, scope of.

धारा 125 – (i) धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण–पोषण घटक और हकदारी।

(ii) धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में जाँच का क्षेत्र। **15*** **31**

Section 125 – See sections 7(1) Exp. (f) and 7(2) (a) of the Family Courts Act, 1984.

धारा 125 – देखें परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धाराएं 7(1) का स्पष्टीकरण (एफ) और 7(2)। **242** **444**

Sections 125 and 128 – Attachment of salary in execution of maintenance order, requirement of.

धारा 125 और 128 – भरण पोषण के आदेश के निष्पादन में वेतन कुर्की के लिये अनिवार्यतायें। **133*** **234**

Sections 125 and 354 – Grant of maintenance – Section 125 (2) Cr.P.C. impliedly requires the court to consider making the order for maintenance effective from either of the two dates i.e. from the date of order or from the date of application, having regard to the relevant facts – The court should record reasons in support of the order passed by it in both eventualities as provided under section 354 (6) of the Cr.P.C.

धारा 125 और 354 – भरण–पोषण मंजूर करना – धारा 125 (2) द.प्र.सं. परोक्ष रूप से न्यायालय से यह अपेक्षा करती है कि वह भरण पोषण का आदेश दो में से किसी तारीख से, सुसंगत तथ्यों के प्रकाश में, प्रभावी बनावे अर्थात आदेश की तारीख से या आवेदन की तारीख से। न्यायालय को उसके आदेश के समर्थन में दोनों ही दशाओं में कारण अभिलिखित करना चाहिये जैसा की धारा 354 (6) द.प्र.सं. में प्रावधान है। **75** **152**

Section 145 – Relevancy of finding given in proceedings under section 145 of CrPC.

The observations made in the above proceedings do not bind the competent court in a legal proceeding initiated before it – It cannot be made a ground for deciding relationship of landlord and tenant.

धारा 145 – धारा 145 दं.प्र.सं. की कार्यवाहियों में दिये गये निष्कर्ष की सुसंगतता।

उक्त कार्यवाही में दिये गये अभिमत किसी विधिक कार्यवाही जिस सक्षम न्यायालय के सामने शुरू की गई है उस पर बन्धनकारी नहीं होते है – ये (उक्त कार्यवाही में दिये गये अभिमत) मकान मालिक और किरायेदार के संबंध निर्धारित करने का आधार नहीं बनाये जा सकते है। **291** **514**

Section 154 – Appreciation of documentary evidence – FIR – It should contain the essential features of the prosecution case but cannot be expected to be an encyclopedia of whole prosecution case.

धारा 154 – दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन – प्रथम सूचना प्रतिवेदन – इसमें अभियोजन के प्रकरण के आवश्यक मुख्य तथ्य होना चाहिये किन्तु यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह अभियोजन के पूरे प्रकरण के विश्व ज्ञान कोष या इनसाइक्लोपीडिया के समान होगा। **152(i) 275**

Section 154 – Delay in lodging FIR.

धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाने में विलंब। **37(iv) 82**

Section 154 – Delay in lodging FIR – Incident took place at night.

धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाने में हुआ विलंब – घटना रात में घटी।

16(ii) 32

Section 154 – Delay in lodging FIR in sexual offence.

धारा 154 – लैंगिक अपराध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने में विलंब। **189 (i)* 340**

Section 154 – Effect of non-mentioning of names of all witnesses in the FIR.

धारा 154 – सभी गवाहों के नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज न करने का प्रभाव।

134(i) 235

Sections 154 (1), 154 (3), 156 (3), 200, 202 and 397 – (i) Power under section 156 (3) of the Code, exercise of – The duty cast on Magistrates cannot be marginalized – They must remain vigilant and diligent while exercising such power – Proper application of mind is ***sine qua non***.

(ii) Abuse of provisions under sections 156 (3) of the Code, prevention of.

(iii) Revisional power, exercise of – Opportunity of hearing, necessity of.

धाराएं 154 (1), 154 (3), 156 (3), 200, 202 और 397 – (i) धारा 156 (3) दं.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग – मजिस्ट्रेट पर अधिरोपित कर्तव्य को किनारे पर नहीं रखा जा सकता – ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय उन्हें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए – मस्तिष्क का प्रयोग एक आवश्यक शर्त है।

(ii) धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के प्रावधान के दुरूपयोग का निवारण।

(iii) पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाना – सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता।

190 341

Sections 156, 161 and 162 – (i) Contradiction as per provision under section 145 of the Evidence Act with the statement recorded under section 161 CrPC by the police – When cannot be looked into?

(ii) Effect of delay in recording statement under section 161 CrPC.

(iii) Omission on the part of I.O.

धाराएं 156, 161 और 162 – (i) धारा 145 साक्ष्य अधिनियम के अधीन, पुलिस द्वारा धारा 161 दं.प्रं.सं. के अधीन अभिलिखित कथन के साथ विरोधाभास – कब नहीं देखा जा सकता?

(ii) धारा 161 दंप्रसं के कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब का प्रभाव।

(iii) अन्वेषण अधिकारी के भाग पर चूक। **292 515**

Sections 156(3), 157, 173 and 202 – Power to direct investigation under section 156 (3) of the Code, exercise of.

Maxim ***"Expressio unius est exclusio alterious",*** non-applicability of.

Power u/s 202 of the Code, nature and scope of.

Section 157 of the Code, requirement of.

धाराएं 156(3), 157, 173 और 202 – धारा 156 (3) संहिता के अधीन अनुसंधान के निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग किया जाना।

सूत्र ''एक्सप्रेशन यूनियस इस्ट एक्सक्लूजन आल्टरियस'' का लागू न होना।

धारा 202 संहिता की शक्तियों की प्रकृति और क्षेत्र स्पष्ट किया गया।

धारा 157 संहिता की आवश्यकताएँ – विधि समझाई गयी। **233 429**

Sections 156 (3), 190 and 202 (1) – Power to direct investigation u/s 156 (3) of the Code – Re-exercise is impermissible.

धाराएं 156 (3), 190 और 202 (1) – धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अधीन अनुसंधान का निर्देश देने की शक्ति – इस शक्ति का पुनः प्रयोग (उसी मामले में दो बार प्रयोग) अनुमत नहीं है।

135 236

Section 157 – Delayed FIR and non-compliance of section 157 CrPC, effect of.

धारा 157 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन में विलंब और धारा 157 दं.प्र.सं. का अनुपालन न करने का प्रभाव।

26(ii) 51

Sections 164 and 439 – Statements of two prosecutrix recorded under section 164 Cr.P.C. for bail, use of –There are contradictions in the statements of both the prosecutrix regarding the place of occurrence – It can be used only for corroboration or contradiction purpose during trial – Application under section 439 Cr.P.C. rejected.

धाराएं 164 और 439 – दो अभियोक्त्रियों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का जमानत के लिये उपयोग – दोनों अभियोक्त्रियों के कथनों में घटना के स्थान के बारे में विरोधाभास है – इसे (धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन) पुष्टि या खण्डन के उद्देश्य से विचारण के समय उपयोग में लाया जा सकता है – धारा 439 दं.प्र.सं. का आवेदन खारिज किया। **95*** **185**

Section 167 (2) – What is the starting point of first fifteen days for the purpose of police custody?

Whether first fifteen days for the purpose of police custody specified in section 167 (2) Cr.P.C. should be reckoned from the date of surrender of accused before High Court on 18.06.2015 or when the accused was first produced by the police before the designated court on 30.06.2015 for police remand?

धारा 167(2) – पुलिस अभिरक्षा के उद्देश्य से प्रथम 15 दिन का प्रारंभिक बिन्दु क्या होता है?

धारा 167 (2) दं.प्रं.सं. में विनिर्दिष्ट पुलिस अभिरक्षा के उद्देश्य से प्रथम 15 दिन की गणना अभियुक्त के उच्च न्यायालय के समक्ष सर्मपण दिनांक 18 जून, 2015 से की जाना चाहिए या जब अभियुक्त को प्रथम बार पुलिस द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष 30 जून, 2015 को पुलिस रिमांड के लिए पेश किया उस दिन से की जाना चाहिए ? **234*** **436**

Section 167 (2) (a) (i) – Indefeasible right of accused to release him on bail – How to calculate the period of 90/60 days?

धारा 167 (2) (ए) (i) – अभियुक्त का उसे जमानत पर रिहा करने का आलोप्य अधिकार – 90/60 दिनों की अवधि की गणना कैसे की जाये? **191*** **345**

Section 167 (2), Proviso (a) (ii) – Accused persons were taken into custody on 18.02.2013 for the offences under sections 399 and 402 of IPC – Charge-sheet was filed on 22.04.2013 after expiry of sixteen days – Prior to the filing of charge-sheet, accused filed application u/s 167 (2) Cr.P.C. seeking benefit of statutory bail – Trial Court allowed the application – Revisional Court set aside that order – High Court restored the order of trial Court because before filing charge sheet, accused had filed application u/s 167 (2) Cr.P.C.

धारा 167 (2) परंतुक (ए) (ii) – अभियुक्तगण को धारा 399 और 402 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 18 फरवरी, 2013 को अभिरक्षा में लिया गया था – अभियोग पत्र 22.04.2013 को 60 दिन गुजर जाने के बाद प्रस्तुत किया गया था – अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पहले अभियुक्त ने धारा 167 (2) दं.प्र.सं. के अधीन वैधानिक जमानत का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था – विचारण न्यायालय ने आवेदन स्वीकार किया – पुनरीक्षण न्यायालय ने उस आदेश का अपास्त कर दिया – उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को पुनः कायम किया क्योंकि अभियोग पत्र प्रस्तुत होने से पहले अभियुक्त धारा 167(2) दं.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर चुका था। **192** **346**

Sections 173 and 190 – Cognizance is a process where the court takes judicial notice of an offence – The court is not bound by the report submitted by the police under section 173(2) Cr.P.C.

धाराएं 173 और 190 – प्रसंज्ञान एक प्रक्रिया है जब न्यायालय एक अपराध के बारे में एक न्यायिक अवेक्षा या ज्यूडिशियल नोटिस लेते है – न्यायालय पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन धारा 173 (2) द.प्र.सं. से बंधे हुये नहीं रहते है। **143(i) 250**

Sections 173 and 397 – (i) Caution in exercise of revisional jurisdiction.

(ii) Magistrate has power to direct further investigation but he cannot direct another investigating agency to investigate the matter – It would not be within the sphere of further investigation.

धाराएं 173 और 397 – (i) पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सावधानी।

(ii) मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त अनुसंधान का निर्देश देने की शक्ति होती है किन्तु वह मामले का अनुसंधान अन्य अनुसंधान ऐजेन्सी से करने का निर्देश नहीं दे सकता है – यह (ऐसा निर्देश) अतिरिक्त अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं आता है। **293* 518**

Sections 173 (5) (a) and 207 – Effect of non-supply of copies of the image of electronic documents as computer, keyboard, laptop or hard disc etc – How to consider?

धाराएं 173(5)(ए) और धारा 207 – इलेक्ट्रानिक अभिलेख जैसे, कम्प्यूटर, की–बोर्ड, लेपटाप या हार्ड डिस्क आदि की इमेज प्रतिलिपियाँ न देने का प्रभाव – कैसे विचार में लिया जाये?

235* 437

Section 190 – (i) Taking cognizance on protest petition.

(ii) After receiving final report under section 173 of Cr.P.C. the Magistrate has three options.

धारा 190 – (i) प्रतिवाद या विरोध याचिका पर प्रसंज्ञान लेना।

(ii) धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प होते है। **17 34**

Sections 190 and 204 – (i) Magistrate is empowered to issue process against a person who has not been charge-sheeted, provided sufficient material is available in the police report showing his involvement in the crime.

(ii) Principle of "alter ego" when applied.

धाराएं 190 और 204 – (i) मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसे पुलिस ने अपने अभियोग पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया है आदेशिका जारी करने के लिए सशक्त है।

(ii) ''आल्टर इगो'' का सिद्धांत कब लागू होता है। **88 171**

Section 195 (1) (a) (i) – See section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 195 (1) (a) (i) – देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188। **146** **256**

Section 197 – Allegation of police excess in connection with investigation of a criminal case – Requirement of previous sanction for prosecution.

धारा 197 – एक आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में पुलिस द्वारा जादती के अभियोग – अभियोजन के लिये पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता। **236*** **438**

Section 197 – Sanction for prosecution.

धारा 197 – अभियोजन के लिए स्वीकृति। **331*** **586**

Section 197 – Whether sanction under section 197 Cr.P.C. is necessary to initiate criminal proceedings in respect of offences under sections 420, 468, 477-A, 120-B r/w/s 109 IPC?

धारा 197 – क्या धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुमति, धाराएं 420, 468, 477–ए, 120–बी सहपठित धारा 109 भा.दं.सं. के बारे में दांडिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये, आवश्यक होती है? **246** **450**

Sections 197 and 482 – (i) Sanction for prosecution – Necessity – During discharging official duties, if a public servant enters into a criminal conspiracy or indulges in criminal misconduct, such misdemeanour on his part is not to be treated as an act in discharge of his official duties and therefore, provisions of section 197 of the Code will not be attracted.

(ii) After losing battle in civil proceeding – Filing of complaint – Attempt to convert a case of civil nature into a criminal prosecution by the respondent – Amounts to abuse of process of law.

धाराएं 197 और 482 – (i) अभियोजन चलाने की अनुमति – आवश्यकता – यदि एक लोक सेवक अपने कार्यालयीन कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान आपराधिक षड़यंत्र या आपराधिक दुराचरण में शामिल होता है तो उसके ऐसे आपराधिक कृत्यों को कार्यालयीन कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं माना जा सकता है और ऐसे में धारा 197 आकर्षित नहीं होती है।

(ii) सिविल कार्यवाही में पराजित हो जाने के बाद – परिवाद प्रस्तुत करना – एक सिविल प्रकृति के मामले को दांडिक मामले में परिवर्तित करने का प्रत्यार्थी द्वारा प्रयत्न किया गया – यह विधि की प्रक्रिया के दुरूपयोग के समान है। **76** **153**

Section 200 – Amendment in criminal complaint – When can be permitted?

धारा 200 – दांडिक परिवाद में संशोधन – कब अनुमत किया जा सकता है? **294** **518**

Section 200 – Vicarious liability of Managing Director or any other official of a company – When arises?

धारा 200 — एक कंपनी के प्रबंध संचालक या किसी अन्य पदाधिकारी की वायकेरीयस लायबेलिटी — कब उत्पन्न होती है। **159** **290**

Sections 200 and 202 – See sections 406, 409 and 420 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 200 और 202 — देखें भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराएं 406, 409 और 420। **318*** **569**

Sections 200 and 204 – See sections 138, 142 and 145 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

धाराएं 200 और 204 — देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 142 और 145। **109** **203**

Sections 216, 227 and 228 – Framing of charge.

धाराएं 216, 227 और 228 — आरोप विरचित करना। **252*** **464**

Sections 227 and 228 – At the time of framing of charge, only charge-sheet along with accompanying material is to be considered.

धाराएं 227 एवं 228 — आरोप विरचित करते समय अभियोग पत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री को विचार में लिया जाता है। **237** **439**

Sections 227 and 319 – Can a person, who has been added as an accused under section 319 of CrPC by the court avail the remedy of discharge under section 227 of CrPC?

धाराएं 227 और 319 — एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया हो क्या वह धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचन के उपचार का लाभ ले सकता है? **295*** **520**

Section 233 (3) – Revision against order to refuse to recall the witness, maintainability of.

धारा 233 (3) — गवाह को पुनः बुलाने से इंकार करने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की प्रचलनशीलता। **136*** **237**

Sections 227 and 228 – Opportunity of being heard – Necessity of.

धाराएं 227 और 228 — सुनवायी का अवसर — आवश्यकता। **18** **36**

Sections 235 and 248 (2) – Hearing on a sentence to accused by the appellate court – Where there is minimum sentence prescribed and same has been awarded by the appellate court and no prejudice is caused to the accused, it is not necessary to follow the procedure under section 235 Cr.P.C.

धाराएं 235 और 248 (2) – अपील न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना – जहां न्यूनतम दण्ड विहित है और वही अपील न्यायालय द्वारा दिया जा रहा है और उससे अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं गिरता है – यह आवश्यक नहीं है कि धारा 235 दं.प्र.सं. में बतलाई प्रक्रिया का पालन किया जाये। **77(ii) 155**

Section 309 – Unnecessary adjournments – Duty of Court is to see that not only the interest of the accused as per law is protected but also the societal and collective interest is safeguarded – Cross-examination of a witness should not be deferred unless there are special reasons for grant of time and that too has to be recorded.

धारा 309 – अनावश्यक स्थगन – न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि न केवल विधि अनुसार अभियुक्त के हितों की सुरक्षा की जाये बल्कि समाज और सामूहिक हित की सुरक्षा भी की जाये – एक गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं रोकना चाहिये जब तब की समय देने के लिये विशेष कारण न हो और ऐसे कारण लेखबद्ध करना चाहिये। **78 157**

Section 311 – Once a witness has been examined and cross-examined by prosecution, he cannot be recalled because of filing of affidavit against his previous version.

धारा 311 – एक बार एक गवाह का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण अभियोजन द्वारा करवाया जा चुका हो, उसे उसके पूर्व कथन के विरूद्ध शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के कारण पुनः नहीं बुलाया जा सकता।

19 37

Section 313 – (i) Effect of non-compliance of mandatory provision of Section 313 Cr.P.C. – Accused would not be entitled for acquittal on the ground of such non-compliance.

(ii) If such non-compliance caused material prejudice to the accused, the appellate Court is empowered to remand the case to examine the accused again under section 313 Cr. P.C. and may direct for re-trial of the case from the stage of recording of statement under section 313 Cr.P.C. – It cannot be said to be amounting to filling up of lacuna in the prosecution case.

धारा 313 – (i) धारा 313 दं.प्र.सं. के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन न करने का प्रभाव – अभियुक्त ऐसा अनुपालन न करने के आधार पर दोषमुक्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि ऐसा अनुपालन न करना अभियुक्त पर तात्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब अपील न्यायालय प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के लिए सशक्त होती है और यह निर्देश दे सकती है कि धारा 313 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित करने के प्रक्रम से मामले का पुनः विचारण किया जाये। इसे अभियोजन के प्रकरण की कमी पूरा करने के समान नहीं कहा जा सकता। **79 159**

Section 313 – Examination of accused, object and necessity of.

धारा 313 – अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य और आवश्यकता। **193* 347**

Section 313 – Examination of accused under section 313 Cr.P.C.

धारा 313 — अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन परीक्षण। **194** **347**

Section 313 – Omission to bring the attention of the accused to an inculpatory material in his examination under section 313 of Cr.P.C, effect of.

धारा 313 — धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त का ध्यान उसे अपराध में लिप्त करने वाली सामग्री पर न लाने का प्रभाव। **155 (iv)** **281**

Section 319 – Power under section 319 Cr.P.C. to summon additional accused – When cannot be exercised?

धारा 319 — धारा 319 दं.प्र.सं. के अधीन अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन करने की शक्ति — कब प्रयोग नहीं की जा सकती? **238** **440**

Sections 320 and 482 – See section 307 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 320 और 482 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307। **35** **73**

Sections 326 (1) & (3) and 386 – Distinction between 'speedy trial' and 'fair trial'. Directions issued for procedure to be followed for speedy trial and expeditious disposal.

De novo trial, when can be resorted to?

धाराएं 326 (1) एवं (3) और 386 — 'त्वरित विचारण और' ऋजु विचारण का अंतर स्पष्ट किया गया शीघ्र विचारण और शीघ्र निराकरण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्देश जारी किये गये।

पुनः विचारण का आदेश कब किया जा सकता है? **217(i)** **397**

& (iii)

Section 354 – See sections 300 and 376 (2) (g) of the Indian Pendal Code, 1860.

धारा 354 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 और 376 (2)(जी)।

296 **521**

Sections 357 and 357-A – (i) Awarding compensation to the victim of offence – It is the duty of the court to duly consider the aspect of rehabilitating the victim – Court has to award compensation to the victim of offence – When the accused is not in a position to pay fair compensation, the same be paid by the State as per section 357-A CrPC [***Suresh v. State of Haryana, (2015) 2 SCC 227*** relied on].

(ii) Sentencing policy.

धाराएं 357 और 357—ए — (i) अपराध के पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना — यह न्यायालय का कर्तव्य है कि पीड़ित के पुनर्वास के पक्ष को सम्यक रूप से विचार में लेवे — न्यायालय को अपराध के पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना ही चाहिए — यदि अभियुक्त ऋजु (या उचित) प्रतिकर अदा करने की स्थिति में न हो तो धारा 357—ए दं.प्र.स. के अधीन यह राज्य द्वारा अदा करना चाहिए (सुरेश विरूद्ध स्टेट आफ हरियाणा, (2015) 2 एससीसी 227 पर विश्वास किया गया)।

(ii) दण्ड नीति। **297*** **529**

Section 357-A – Duty of the court to grant compensation to the victim – Explained.

धारा 357–ए – आहत् को प्रतिकर देने का न्यायालय का कर्तव्य – स्पष्ट किया। **80(iii) 161**

Section 366 – See sections 3 and 27 of Evidence Act, 1872 and sections 302 and 376 (2) (f) of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 366 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 और 376 (2) (एफ)। **92* 181**

Sections 378 and 386 – (i) Hon'ble the Apex Court has recapitulated the general principles related to powers of the appellate court while deciding the appeal against acquittal.

(ii) How to take the discrepancies in the evidence?

धाराएं 378 और 386 – (i) दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील को निराकृत करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संक्षेप में दोहराया।

(ii) साक्ष्य में आये विरोधाभासों को किस तरह लिया जाये ? **158 288**

Section 394 – Appeal against acquittal – Effect of death of appellant during pendency of appeal – Maxim ***"actio personalis moritur cum persona"*** is not applicable to criminal prosecution – The death of complainant cannot ***ipso facto*** bring termination of the proceeding.

धारा 394 – दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील – अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु का प्रभाव – सुक्ति ''एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटयूर कम परसोना'' दांडिक अभियोजन पर लागू नहीं होती है – परिवादी की मृत्यु से कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। **263 478**

Section 397 – Revisional jurisdiction, exercise of.

धारा 397 – पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना। **309 (ii) 548**

Sections 397 and 401 – See Criminal Trial.

धाराएं 397 और 401 – देखें दांडिक विचारण। **298* 530**

Section 401 (2) – Before passing an order against any person in revision, whether it is necessary to give him right of hearing?

धारा 401 (2) – क्या पुनरीक्षण में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने के पूर्व उसे सुनवायी का अधिकार दिया जाना आवश्यक होता है? **20 38**

Sections 406, 407 and 408 – Transfer of case, ground and need therefor.

धाराएं 406, 407 और 408 — प्रकरण के अंतरण के आधार और आवश्यकता।

299 **531**

Section 427 – When benefit of provision of section 427 Cr.P.C. can be extended to the accused?

धारा 427 — कब धारा 427 द.प्र.सं. के प्रावधानों का लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है?

137 **238**

Sections 438 and 439 (2) – When an order for cancellation of bail can be passed?

धाराएं 438 और 439 (2) — कब जमानत निरस्ती का आदेश पारित किया जा सकता है?

81* **163**

Sections 438 and 439 (2) – (i) Whether an application under section 439 of CrPC for cancellation of anticipatory bail before High Court or the Court of Sessions is maintainable? Held, Yes.

(ii) Anticipatory bail, grant of.

(iii) Subsequent/repeat anticipatory bail applications – Material change of circumstances – Law stated.

(iv) Subsequent bail application – Forum and grounds thereof.

धाराएं 438 और 439 (2) — (i) क्या अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए धारा 439 दं.प्र.सं. का आवेदन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष प्रचलन योग्य है ? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ।

(ii) अग्रिम जमानत का दिया जाना।

(iii) पश्चातवर्ती/पुनः अग्रिम जमानत के आवेदन — परिस्थितियों में तात्विक परिवर्तन — विधि बतलायी गयी।

(iv) पश्चातवर्ती जमानत आवेदन — फोरम और आधार। **21*** **40**

Section 439 (2) – Application for cancellation of bail, ***locus standi*** therefor.

Any member of the public can move the High Court to remind it of the need to exercise its power suo motu in this regard.

Bail, cancellation of – Bail can be cancelled if there is a likelihood of its misuse.

धारा 439 (2) — जमानत निरस्त करने के आवेदन को पेश करने के लिए लोकस स्टेन्डी।

जनता का कोई भी सदस्य उच्च न्यायालय को इस संबंध में उसकी स्वप्रेरणा की शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता को याद दिलाने के लिए आवेदन कर सकता है।

जमानत निरस्तीकरण – यदि जमानत का दुरूपयोग किया गया हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है।

300 **533**

Section 439 (2) – Cancellation of bail – If it is not found that accused had misused the liberty after being released on bail, the same cannot be cancelled – Legal position relating to cancellation of bail reiterated.

धारा 439 (2) – जमानत निरस्त करना – अभियुक्त ने जमानत पर रिहा किये जाने के बाद स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया हो यह नहीं पाया गया – जमानत निरस्त नहीं की जा सकती – जमानत निरस्तीकरण के बारे में विधिक स्थिति पुनः बतलाई गई। **239** **442**

Section 451 – See sections 52 (4)(a), 52 (c) and 54 of the Forest Act, 1927.

धारा 451 – देखें वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 (4)(a), 52 (सी) और 54।

138 **239**

Sections 457 and 482 – Transportation of coal – Seizure of vehicle, release of – Law explained.

धाराएं 457 और 482 – खनिज (अवैध खनन, परिवहन और संग्रहण का संरक्षण) नियम, 2006 – नियम 18 (4) कोयले का परिवहन – जब्त वाहन का छोड़ा जाना – विधि समझाई गई।

82* **164**

Sections 468 and 472 – (i) Gram crop was kept in the go-down of the accused lastly on 27.05.2002 by the complainant – After four months, said crop was demanded first time – Complaint had to be lodged on or before 27.09.2005 but it was made on 10.09.2006 i.e. near about 9½ month belatedly – On perusal of written complaint it appears that in above period of 9½ months many time crop or its value was demanded by the complainant and every time accused persons used to promise the complainant to fulfill the said demand, so it is a case of continuing offence committed under section 406 of IPC and whenever demand was made, from that date a fresh period of limitation began to run – It would be a continuing offence under section 472 of Cr.P.C.

(ii) Period of limitation in relation to offences which may be tried together, shall be determined with reference to the offence which is punishable with more severe punishment.

धाराएं 468 और 472 – (i) चने की फसल अभियुक्त के गोदाम में अंतिम बार 27.05.2002 को परिवादी द्वारा रखी गई चार माह बाद पहली बार उक्त फसल की मांग की गई परिवादी को 27.09.2005 को या उसके पूर्व शिकायत दर्ज कर देना थी किन्तु उसने 10.09.2006 को अर्थात लगभग 9½ बाद विलंब से शिकायत दर्ज की। लिखित शिकायत से यह प्रतित होता है कि उक्त 9½ माह में कई बार फसल या उसकी कीमत की मांग परिवादी द्वारा की गई थी और हर बार अभियुक्तगण ने परिवादी की उक्त मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, अतः यह एक सत्त जारी रहने वाला धारा 406 भा.दं.सं. के अधीन कारित अपराध है और जब–जब मांग की गई उस

तारीख से एक नया परिसीमाकाल लागू होता है। धारा 472 दं.प्र.सं. के अधीन यह एक सत्त अपराध होगा।

(ii) एक साथ विचारण किये जाने वाले अपराधों के बारे में परिसीमाकाल, उस अपराध के आधार पर निर्धारित होगा जो अपेक्षाकृत अधिक कठोर दंड से दंडनीय है। **195** **350**

Section 482 – Quashing of criminal proceedings – Name of accused was not stated in the FIR – He has been implicated as an accused only on the basis of statement made under section 27 of the Evidence Act of co-accused.

धारा 482 – दाण्डिक कार्यवाही अभिखंडित करना – अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज नहीं था – उसे सह–अभियुक्त के धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दिये गये कथन के आधार पर अभियुक्त के रूप में लिप्त किया गया था। **240*** **444**

CRIMINAL TRIAL:

दाण्डिक विचारण :

– (i) Charge-sheet in respect of offences punishable under POCSO Act, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and IPC – Trial and jurisdiction of – Law explained.

(ii) Offences under POCSO Act, trial of – In exercise of powers conferred under section 28 of the POCSO Act, a Court of Sessions has been notified as a Special Court, therefore, Sessions Judges and Additional Sessions Judges posted in a Sessions Division may discharge the function of Special Court as "Children's Court".

(iii) Non-observance of section 193 Cr.P.C. in respect of an offence under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, effect of – Law explained.

(iv) Conflict between two special enactments, which shall prevail? Law explained.

(i) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में आरोप पत्र – विचारण और क्षेत्राधिकार के बारे में – विधि समझाई गई।

(ii) पास्कों अधिनियम के अपराधों का विचारण – विधि समझाई गई।

(iii) धारा 193 दं.प्र.सं. के अपालन के बारे में विधि स्पष्ट की गई।

(iv) दो विशेष अधिनियमों में विरोधाभास होने पर कौन सा अधिनियम अधिभावी होगा? इस बारे में विधि समझाई गई। **196** **351**

– Court, duty of – The Court cannot be a mute spectator, particularly in criminal cases and shun its primary duty of finding out the truth from the material on record – It has to punish the guilty and protect the innocent.

False plea taken by accused, effect of – A false plea is to be taken as an additional circumstance against the accused.

Appeal against acquittal – Power of Appellate Court, scope and exercise of.

न्यायालय का कर्तव्य – न्यायालय एक मूक दर्शक नहीं हो सकता है, विशेषकर दांडिक मामलों में यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से सत्य का पता लगाये – उसे दोषी को दंडित करना चाहिये और निर्दोष को संरक्षित करना चाहिये।

अभियुक्त द्वारा एक असत्य बचाव लेने का प्रभाव – अभियुक्त द्वारा एक असत्य बचाव लेना उसके विरूद्ध परिस्थिति की एक अतिरिक्त श्रृंखला होती है।

दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील – अपील न्यायालय की शक्ति का विस्तार और प्रयोग।

155 (i), (iii)&(v) **281**

– (i) Fair investigation, objective and need of.

(ii) Whistleblower, protection of – If actions of whistleblower serve public interest, his prosecution is not warranted.

(i) ऋजु विचारण के उद्देश्य व आवश्यकता।

(ii) विसलब्लोअर का संरक्षण – यदि विसलब्लोअर का कृत्य लोकहित की पूर्ति के लिए हो तो उसका अभियोजन उचित नहीं होगा। **301*** **535**

– Fair trial – Reversal of order of acquittal and direction of re-trial in revisional jurisdiction – Duty of court and prosecutor in conducting trial.

ऋजु विचारण – पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार में दोषमुक्ति के आदेश को पलटना और पुनः विचारण के निर्देश देना – विचारण का संचालन करने में न्यायालय और अभियोजक के कर्तव्य।

298* **530**

– Offence of rape – Test Identification Parade – Non-significance of – T.I. parade ***vis-a-vis*** dock identification – Law explained.

Traumatic and tragic experience in the course of commission of such heinous offence and close proximity with the offender affords sufficient time to imprint upon the mind of the prosecutrix the identity of the offender – Identification of the offender in court by her is the substantive evidence – Test identification parade is not a rule of law but only a rule of prudence – Identification of the accused in court can be relied upon even in the absence of test identification parade.

बलात्संग का मामला – पहचान परेड – तात्विक या महत्वपूर्ण न होना – पहचान परेड की तुलना में न्यायालय कक्ष में पहचान – विधि समझाई गई।

अपराध के कारित होने के दौरान के मानसिक आघात पहुंचाने वाले और दुखद अनुभव तथा अपराधी से (अपराध कारित होने के दौरान) सामिप्य या निकटता, अभियोक्त्री के मस्तिष्क में अपराधी की पहचान अंकित करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है – अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त की न्यायालय में पहचान तात्विक साक्ष्य होती है – पहचान परेड (संचालित करवाना) विधि का नियम नहीं है बल्कि प्रज्ञा का नियम है – पहचान परेड के बिना भी न्यायालय में की गई अभियुक्त की पहचान पर भरोसा किया जा सकता है। **197** **358**

– Offences under Prevention of Corruption Act, 1988 – Sentencing policy – Theories of punishment, applicability of.

Misplaced sympathy or unwarranted leniency will send a wrong message to public at large giving room to suspect institutional integrity affecting the credibility of its verdict – Judgments must project and promote the policy aims of punishment – The court owes a duty to protect and promote public interest and build-up public confidence in efficacy of the rule of law.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध – दण्ड नीति – दण्ड के सिद्धांतों का लागू होना – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के बारे में दण्ड का सुधारात्मक सिद्धांत लागू नहीं होता है – जिस क्षण लोक सेवक को दोषसिद्ध किया जाता है वह उसकी नौकरी खो देता है इस कारण लोक सेवा में उसके आचरण में सुधार के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रहता है – ऐसे मामलों में दण्ड का उद्देश्य भर्त्सना और निवारक होता है। **302** **536**

– Sentencing policy – Death sentence – Principle of the rarest of rare case – Aggravating and mitigating factors – Law explained.

दण्ड नीति – मृत्यु दण्ड – विरले से विरलतम का सिद्धांत – गंभीर और शमनकारी कारक विधि समझाई गई। **303*** **540**

– (i) Sentencing policy:

(a) Sentence, object of – It serves a three-fold purpose; punitive, deterrent, and protective.

(b) Death sentence, imposition of – Aggravating and mitigating circumstance, consideration of.

(ii) Victimology – It is the paramount duty of the Court to provide justice to the incidental victims of the crime (i.e. the family members of the deceased persons) – Appropriate and proportional sentence requires to be imposed.

(i) दंड नीतिः

(a) दंड का उद्देश्य – इसके तीन उद्देश्य है दंडात्मक, निवारक और सुरक्षात्मक – कठोर दंड अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, विधि का सम्मान अग्रसर करना अपराध के लिये युक्तियुक्त दंड देने के लिये होता है साथ ही उसी प्रकार के अपराध से समुदाय को सुरक्षित करना और दांडिक आचरण में सुधार लाना भी इसका लक्ष्य होता है।

(b) मृत्यु दण्ड दिया जाना – परिस्थितियाँ स्पष्ट की गई।

(ii) विक्टिमोलॉजी – अपराध से पीड़ित के प्रति न्यायालय के कर्तव्य स्पष्ट किये गये।

139 **240**

Sentencing policy and duty of court – Reiterated.

दण्ड नीति और न्यायालय का कर्त्तव्य – पुनः बतलाये गये। **22** **42**

DIVISION OF PROPERTY OF CHRISTIANS:

ईसाईयों में संपत्ति का विभाजनः

(i) Christian Family – Concept of joint family property or coparceners under Hindu Law, non-applicability of.

(ii) Absolute owner – A Christian who inherited property from his parents is the absolute owner of such property – He can divide and distribute property as per his wish.

(i) ईसाई परिवार – संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति या सहदायिक की हिन्दू विधि के अधीन धारणा का लागू न होना

(ii) निरपेक्ष या पूर्ण स्वामी – एक ईसाई जो उसके माता–पिता से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करता है वह ऐसी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है – वह उस संपत्ति को उसकी इच्छा अनुसार विभाजित और वितरित कर सकता है। **140** **245**

DOWRY PROHIBITION ACT, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

Section 2 – Definition of "dowry".

धारा 2 – ''दहेज'' की परिभाषा। **251** **461**

ELECTRICITY ACT, 2003

विद्युत अधिनियम, 2003

Section 154 – Filing of private complaint in respect of an offence relating to unauthorized consumption of electricity, necessity therefor – Submission of complaint to police prior to filing of complaint before Special Court is not ***sine qua non*** – Electricity Company may directly file private complaint before the Court.

धारा 154 – विद्युत के अनाधिकृत उपभोग के संबंध में निजी परिवाद का प्रस्तुत किया जाना – विशेष न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व पुलिस को शिकायत करना आवश्यक शर्त नहीं है – विद्युत कंपनी न्यायालय के समक्ष सीधे परिवाद प्रस्तुत कर सकती है।

141 **247**

EVIDENCE ACT, 1872

साक्ष्य अधिनियम, 1872

Section 3 – Appreciation of evidence.

धारा 3 — साक्ष्य का मूल्यांकन। **304** **541**

Section 3 – Appreciation of evidence – Conduct and behavior of witnesss.

धारा 3 — साक्ष्य का मूल्याकंन — गवाह का आचरण और व्यवहार। **16(i)** **32**

Section 3 – Appreciation of evidence – Previous animosity – It is a double edged weapon – Can be a basis for false implication and can also be a motive for the crime, decided by the court on facts and circumstances of each case.

धारा 3 — साक्ष्य का मूल्यांकन — पूर्व वेमनस्य — यह एक दो धार वाला हथियार है — यह एक असत्य फंसाने का आधार हो सकता है, अपराध करने का हेतू भी हो सकता है, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णीत करती है (की पूर्व वेमनस्य का प्रभाव क्या है)।

134 (ii) **235**

Section 3 – See sections 7, 13(1)(d) r/w13(2) and 20 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धारा 3 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 7, 13 (1) (d) सहपठित धारा 13 (2) और 20

272* **488**

Section 3 – See sections 378 and 386 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 3 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 और 386। **158** **288**

Section 3 – See sections 399 and 402 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 399 और 402। **254*** **465**

Sections 3 and 8 – Motive – Where case is based on circumstantial evidence, motive becomes an important factor but that does not mean, in all cases of circumstantial evidence, if prosecution is unable to prove the motive, prosecution must fail.

Theory of last seen – If a person, who is last seen in the company of another is dead or missing, the person with whom he was last seen alive has to explain the circumstances in which he parted with the company.

Case based on circumstantial evidence – The circumstances from which the conclusion of guilt is sought to be drawn must be fully proved beyond any reasonable doubt and such circumstances must be consistent and must form a complete chain unerringly point to the guilt of the accused.

धाराएं 3 और 8 — हेतुक — जहाँ मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो, हेतुक एक महत्वपूर्ण कारक होता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामलों में जहाँ अभियोजन हेतुक प्रमाणित करने में समर्थ नहीं होता है अभियोजन असफल ही होता है।

अन्तिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – यदि एक व्यक्ति अन्तिम बार दूसरे व्यक्ति के साथ पाया जाता है और उसकी मुत्यु हो जाती है या वह गायब हो जाता है तब जिस व्यक्ति के साथ वह अन्तिम बार जीवित साथ पाया गया था उसे यह स्पष्टीकरण देना ही होता है कि कैसे वह व्यक्ति उससे अलग हुआ।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला – परिस्थितियाँ जिनके आधार पर अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है वे सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना चाहिए परिस्थितियाँ निश्चित और एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हो और अभियुक्त के दोषी होने को अचूक रूप से इंगित करती हो। **249** **456**

Sections 3 and 9 – Appreciation of evidence – Identification of accused after 7½ years not previously known to the injured – Human behaviour.

धाराएं 3 और 9 – साक्ष्य का मूल्याकंन – अभियुक्त जिसे आहत पहले से नहीं जानता था उसकी पहचान उसने 7½ वर्ष बाद की – मानव स्वभाव। **23** **46**

Sections 3, 9 and 118 – (i) Dock identification, evidentiary value of.

(ii) Child witness, credibility of.

(iii) Last seen theory, absence of explanation on the part of accused, effect of .

(iv) Discovery of fact, effect of .

धाराएं 3, 9 और 118 – (i) न्यायालय में की गई पहचान का साक्षियक मूल्य।

(ii) बाल साक्षी की विश्वसनीयता।

(iii) अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने का सिद्धांत, अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न देने का प्रभाव ।

(iv) तथ्य का पता लगने का प्रभाव – समझाया गया। **305 (i)* to (iv)** **543**

Sections 3, 11 and 32 – (i) Plea of alibi – Burden of proof – The burden on the accused is rather heavy.

(ii) Dying declaration – 100% burn injury cases.

धाराएं 3, 11 और 32 – (i) घटनास्थल से अनुपस्थिति – प्रमाण भार – अभियुक्त पर अपेक्षाकृत भारी प्रमाणभार होता है।

(ii) मृत्यु पूर्व कथन – 100 प्रतिशत जलने से आई चोटों का प्रकरण। **198** **360**

Sections 3 and 27 – (i) Circumstantial evidence, tests thereof.

(ii) Circumstantial evidence – Cautious approach, necessity of.

धाराएं 3 और 27 – (i) परिस्थिति जन्य साक्ष्य का परीक्षण कैसे किया जाये स्पष्ट किया गया।

(ii) परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में सावधानी पूर्ण रूख की आवश्यकता बतलाई गई।

92(i) & (ii)* **181**

Sections 3 and 32 – Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 3 और 32 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302। **90** **179**

Sections 3 and 45 – (i) Appreciation of evidence – Prosecutrix a married lady – According to doctor no definite opinion regarding rape could be given – Want of conclusive opinion of doctor regarding rape in case of married woman – Not to be a ground for acquittal.

(ii) Appreciation of evidence –The sole testimony of prosecutrix is sufficient to prove the commission of rape – Corroborative evidence is not required.

धाराएं 3 और 45 — (i) साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियोक्त्रि एक विवाहित महिला – डॉक्टर के अनुसार बलात्संग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती – विवाहित महिला के मामले में बलात्संग के बारे में डॉक्टर की निश्चायक राय का अभाव – दोषमुक्ति का एक आधार नहीं हो सकता।

(ii) साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियोक्त्रि की एक मात्र साक्ष्य बलात्संग को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त होती है पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। **24** **47**

Sections 3 and 45 – (i) Determination of age of prosecutrix – Oral evidence v/s ossification test – Appreciation of evidence.

(ii) Facet of consent of prosecutrix – Once it is proved that the prosecutrix is below 16 years of age at the time of incident consent is absolutely irrelevant.

धाराएं 3 और 45 — (i) अभियोक्त्री के उम्र का निर्धारण – मौखिक साक्ष्य विरूद्ध ओशिफिकेशन परीक्षण – साक्ष्य का मूल्यांकन।

(ii) अभियोक्त्री की सहमती का पक्ष – एक बार यह प्रमाणित हो जाता है कि अभियोक्त्री घटना के समय 16 वर्ष से कम की थी तब सहमती (का पहलू) बिल्कुल असंगत होता है।

316 **565**

Sections 3 and 114-A – Appreciation of evidence of prosecutrix in rape case – Whether corroboration is necessary?

धाराएं 3 और 114—ए — बलात्कार के प्रकरण में अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन – क्या पुष्टि आवश्यक है?

189 (iii)* **340**

Sections 3 and 134 – Appreciation of evidence:

(i) Interested/related witnesses.

(ii) Minor discrepancies on trivial matters, Effect of.

(iii) Examination of all the eye witnesses, whether necessary.

धाराएं 3 और 134 – साक्ष्य का मूल्यांकन

(i) हितबद्ध /रिश्तेदार गवाह।

(ii) तुच्छ बातों के बारे में छोटे विरोधाभाषों का प्रभाव।

(iii) सभी प्रत्यक्ष साक्षीगण का परीक्षण करवाने की आवश्यकता न होना। **93 (A)*** **182**

Sections 3 and 145 – See Sections 156, 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973

धाराएं 3 और 145 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156, 161 और 162

292 **515**

Section 8 – See Sections 190 and 204 of the Criminal Procedure Code, 973.

धारा 8 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 और 204। **88** **171**

Sections 8 and 27 – Discovery of fact and recovery of articles under section 27 of the Evidence Act – Law explained.

Distinction between the conduct of an accused, admissible under section 8 and the statement made to police in the course of investigation – Law explained.

What is excluded by section 162 of Cr.P.C. is the statement made to Police Officer in the course of investigation and not the evidence relating to the conduct of an accused person (not amounting to a statement) when confronted or questioned by a Police Officer during the course of an investigation.

धाराएं 8 और 27 – धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्यों का पता लगना और वस्तुओं की बरामदगी संबंधी विधि समझाई गई।

अभियुक्त के आचरण जो की धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य है और उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान पुलिस को दिये गये कथन में अंतर – विधि समझाई गई।

151 (ii) & (iii) **267**

Section 27 – Accused was in police custody in a particular offence – In interrogation, he led to the discovery in connection with other offence.

धारा 27 – अभियुक्त एक विशिष्ट अपराध में पुलिस अभिरक्षा में था – पूछताछ में उसने अन्य अपराध से संबंधित (नये तथ्यों का पता लगने) संबंधी जानकारी दी। **261 (i)** **476**

Section 27 – Disclosure Statement, admissibility and significance of.

धारा 27 – प्रगटन कथन की ग्राह्यता और महत्व। **199*** **362**

Sections 27 and 106 – When section 106 of the Evidence Act, 1872 is attracted?

धाराएं 27 और 106 – धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कब आकर्षित होती है?

80(i) **161**

Section 32 – Appreciation of evidence – If a dying declaration is found to be reliable, then there is no need for corroboration by any evidence and conviction can be sustained on that basis alone.

धारा 32 – साक्ष्य का मूल्याकंन – यदि एक मृत्यु कालीन कथन विश्वसनीय पाया जाता है तब उसकी किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उस अकेले के आधार पर दोषसिद्धि स्थिर की जा सकती है। **34(ii) 70**

Section 32 – Appreciation of evidence – Two consistent dying declarations of victim – One oral D.D. made to her brother and P.W. 8 – Another D.D. made to Doctor – No possibility of tutoring – Mere absence of smell of kerosene from the body of the victim does not render the dying declaration doubtful and unreliable.

धारा 32 – साक्ष्य का मूल्याकंन – आहत के दो समनुरूप मृत्युकालीन कथन – एक मौखिक मृत्युकालीन कथन जो उसके भाई और अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 को किया गया था – दूसरा मृत्यु कालीन कथन डॉक्टर को किया गया – सिखाये जाने की कोई संभावना नहीं थी – केवल आहत के शरीर से कैरोसीन की गंध अनुपस्थित होना उसके मृत्यु कालीन कथन को संदेहास्पद या अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

33 70

Section 32 (1) – Appreciation of evidence – Minor discrepancies and infirmities in investigation, non-effect of – Available overwhelming evidence proving the offence alleged, cannot be discredited or rejected on account of minor discrepancies in evidence and infirmities in investigation.

धारा 32 (1) – साक्ष्य का मूल्यांकन छोटे विरोधाभास और अनुसंधान की कमी का प्रभाव न होना – अभिलेख पर अभिकथित अपराध को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है उस पर केवल छोटे विरोधाभासों और अनुसंधान की कमियों के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

155(ii) 281

Section 32 (1) – Dying declaration of 'A' relating to cause of death of herself and 'B' – Whether it is admissible for the cause of death of 'B'?

धारा 32 (1) – 'ए' का मृत्यु पूर्व कथन जो उसकी स्वयं की व 'बी' की मृत्यु के कारण के बारे में था – क्या यह (मृत्यु कालिन कथन) 'बी' की मृत्यु के कारण के बारे में ग्राह्य है?

142 249

Section 32 (1) – Dying declaration – Reliability, test and requirement of.

धारा 32 (1) – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता, जाँच और आवश्यकताएँ।

200* 363

Section 32 (1) – Recording of dying declaration, procedure therefor.

Dying declaration, evidentiary value of.

धारा 32 (1) – मृत्यु पूर्व कथन अभिलखित करने की प्रक्रिया बतलाई गई।

मृत्यु पूर्व कथन का साक्ष्यिक मूल्य समझाया गया। **314 (ii) &(iii)** **557**

Sections 45 and 114 – (i) Divorce on the ground of adulterous life style of the wife – Husband moved an application for DNA test of himself and the male child born to the wife.

(ii) If wife declines for DNA test, the allegation would be determined by the court, by drawing a presumption provided under Section 114 (h) of the Evidence Act.

धाराएं 45 और 114 – (i) पत्नी की जारतापूर्ण जीवनशैली के आधार पर विवाह विच्छेद – पति ने एक आवेदन उसके और उसकी पत्नी से उत्पन्न बच्चे के डी.एन.ए. परीक्षण के लिये लगाया।

(ii) यदि पत्नी डी.एन.ए. परीक्षण से इंकार करती है तब न्यायालय द्वारा अभियोगों को धारा 114 (एच) साक्ष्य अधिनियम में उपलब्ध उपधारणा लेते हुये निर्धारित किया जा सकता है। **84** **167**

Section 62 – See Sections 498–A and 304–B of the Indian Penal Code, 1860 and Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973

धारा 62 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498–A और 304–B और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154। **37** **82**

Sections 63, 65, 65-A and 65-B – ***Generalia specialibus non derogant*** means special law will always prevail over the general law – Proof of electronic record is a special provision introduced by the IT Act amending various provisions under the Evidence Act – Sections 59, 65-A and 65-B of the Evidence Act are complete Code in itself – So, in the case of CD, VCD, chip etc. same shall be accompanied by the certificate in terms of section 65-B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence regarding that electronic record is inadmissible.

[***State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu @ Afsan Guru AIR 2005 SC 3820*** overruled]

धाराएं 63, 65, 65–ए और 65–बी – जनरलिया स्पेशिलिबस नान डेरोगेट अर्थात विशेष विधि हमेशा सामान्य विधि पर अभिभावी होगी। इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को प्रमाणित करना एक विशेष प्रावधान है जो सूचना और प्रौद्योगिक अधिनियम द्वारा साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन द्वारा लाया गया है। धारा 59, 65–ए, 65–बी साक्ष्य अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। अतः सी.डी., व्ही.सी.डी. चिप आदि के मामले में उनके साथ धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए जो दस्तावेज लेते समय प्राप्त किया जाता है – उसके बिना इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के बारे में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होती है।

(स्टेट (एन.सी.टी. देहली) विरूद्ध नवजोत संधु उर्फ अफसान गुरू, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 3820 को ओवर रूल्ड किया गया, **83** **166**

Sections 63, 65 (c) and 66 – Leading secondary evidence, entitlement for.

धाराएं 63, 65 (सी) एवं 66 – द्वितीयक साक्ष्य देने का अधिकार। **25** **49**

Sections 63, 65 and 66 – Xerox copy of power-of-attorney produced by the plaintiff in evidence – Signature and contents of the said document were admitted by the defendant – Certified copy of that document is also on record – There is no question of proving the said document as required under the Evidence Act.

Discretionary relief for specific performance – Depends upon the conduct of the parties.

धाराएं 63, 65 और 66 – वादी द्वारा साक्ष्य में मुखतियार नामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई – इस दस्तावेज की अंतरवस्तु और उस पर हस्ताक्षर होना प्रतिवादी ने स्वीकार किया था – दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी अभिलेख पर है – इस दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विनिर्दिष्ट पालन का विवेकीय अनुतोष – पक्षकारों के आचरण पर निर्भर रहता है।

115(i) **211**

&(ii)

Sections 65-A and 65-B – Admissibility of an electronic evidence – Source and authenticity are the two key factors for an electronic evidence so, at the time of admitting such evidence, the court should bear in mind the above two factors.

धाराएं 65–ए और 65–बी – एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता – स्त्रोत व अधिकृतता एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के दो मुख्य कारक होते हैं अतः न्यायालय को ऐसी साक्ष्य ग्राह्य करते समय उक्त दो कारक मस्तिष्क में रखना चाहिये। **143(ii)** **250**

Section 65 (b) – See Sections 91 and 92 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 65 (बी) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 91 और 92। **241** **444**

Section 65 (f) – Secondary evidence – Certified copy of documents obtained under Right to Information Act, admissibility of.

धारा 65 (एफ) – द्वितीयक साक्ष्य – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त की गई दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की ग्राह्यता। **201** **366**

Sections 67, 68 and 71 – See Section 63 of Succession Act, 1925.

धाराएं 67, 68 और 71 – देखें उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 65।

336 **592**

Section 90 – Nature of presumption under section 90 of the Evidence Act for 30 years old document – It is discretionary – Whether it can be taken for 29½ years old document?

धारा 90 – 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में धारा 90 साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की प्रकृति – यह विवेकीय है – क्या साढ़े उनतीस वर्ष (29) वर्ष) पुराने दस्तावेज के बारे में यह उपधारणा ली जा सकती है?

144 **253**

Section 106 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 106 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302। **148** **259**

Section 113-B – Dowry death within one year of marriage – Appreciation of evidence – Mentioning in suicide note that 'nobody be held responsible' but also stating that all the doors were closed for her – She had no other way available (expect to leave the world).

धारा 113–बी – विवाह के एक वर्ष के भीतर दहेज मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – आत्महत्या के लेख में ''किसी को उत्तरदायी नहीं माना जाये'' दर्ज था – किन्तु उसने यह भी लिखा था कि उसके लिये सभी दरवाजे बंद हो चुके थे – उसके पास अन्य कोई रास्ता (केवल संसार को छोड़ने के अलावा) उपलब्ध नहीं था। **94(i)** **184**

Section 132 – (i) Interpretation of proviso.

(ii) The rule against self-incrimination can be seen in (a) Section 161 Cr.P.C, 1973 (b) Sections 25 and 26 of the Evidence Act and (c) The proviso to section 132 of the Evidence Act.

धारा 132 – (i) परंतुक का अर्थान्वयन।

(ii) स्वदोशिता के विरूद्ध नियम को (ए) धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (बी) धारा 25 एवं 26, साक्ष्य अधिनियम; और (सी) धारा 132, साक्ष्य अधिनियम के परंतुक में देखा जा सकता है। **202** **365**

Sections 137 and 138 – See Section 309 of Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 137 और 138 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309। **78** **157**

Section 154 – Evidence – Hostile witness, appreciation of.

Testimony of injured eye witness, appreciation of.

Testimony of interested witness, appreciation of.

धारा 154 – साक्ष्य – पक्ष विरोधी साक्षी की साक्ष्य का मूल्याकंन।

आहत चक्षु साक्षी की साक्ष्य का मूल्याकंन।

हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का मूल्याकंन। **26(i), (iii) &(iv)** **51**

EXCISE ACT, 1915 (M.P.)

आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)

Section 34 (1) and (2) – See Section 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 34 (1) और (2) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482। **240*** **444**

FAMILY COURTS ACT, 1984

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984

Section 7 – See Section 41 (6) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

धारा 7 – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41 (6)(बी)।

27 **58**

Sections 7(1) Exp. (f) and 7 (2) (a) – Husband took voluntary retirement after the judgment dated 17.02.2012 – Whether it is a ground for reducing the amount of maintenance?

Whether an application under section 125 Cr.P.C. filed by a divorced Muslim woman, is maintainable before the Family Court?

धाराएं 7(1) का स्पष्टीकरण (एफ) और 7 (2) (ए) – (i) पति ने निर्णय दिनांक 17.02.2012 के बाद स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली – क्या यह भरण पोषण की राशि घटाने या कम करने के लिए एक आधार हो सकता है?

क्या एक तलाक शुदा मुस्लिम महिला द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 125 दं.प्र.सं., परिवार न्यायालय के समक्ष, प्रचलन योग्य है? **242** **445**

FOREST ACT, 1927

वन अधिनियम, 1927

Section 2 (2) – Whether a forest guard is a forest officer? Held, Yes – Further held, he is also empowered to seize any animal, articles.

धारा 2 (2) – क्या एक वनरक्षक वन अधिकारी होता है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वह किसी पशु, वस्तु को जप्त करने के लिए सशक्त भी होता है। **61 (i)*** **130**

Sections 33 (1) (c) and 52 – Allegation against the accused is confined to the fact that he was cultivating the reserved forest land – His tractor was seized by the Forest Department – Confiscation proceeding has been initiated by specific authority – There was no forest produce seized from the tractor so it cannot be confiscated – High Court ordered for release of the tractor [***State of Kerala v. P. V. Mathew, AIR 2012 SC 1502*** relied on].

धाराएं 33 (1) (सी) और 52 – अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग इस तथ्य तक सीमित थे कि उसने संरक्षित वन भूमि पर खेती की थी – उसका ट्रैक्टर वन विभाग द्वारा जप्त किया गया था – संपहरण कार्यवाही विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी – ट्रैक्टर से कोई वन उपज बरामद नहीं हुई थी इस कारण ट्रैक्टर का संपहरण नहीं किया जा सकता – उच्च न्यायालय द्वारा ट्रैक्टर छोड़े जाने का आदेश दिया गया – स्टेट ऑफ केरला विरूद्ध पी.वी. मैथ्यू, ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 1502 पर भरोसा किया गया।

306* **545**

Sections 52 (4)(a), 52(c) and 54 – Who can start proceeding of confiscation of the property which was seized in offence relating to Forest Act, 1927?

धाराएं 52 (4)(ए), 52(सी) और 54 – वन अधिनियम, 1927 से संबंधित अपराध में जब्त संपत्ति के संबंध में सम्पहरण या कॉन्फेसिकेशन की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है?

138 **239**

FOREST MANUAL

वन नियमावली

Rule 75 (1) – See Sections 2(12-A) and 50(1)(c) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and Section 2(2) of the Forest Act, 1972.

नियम 75 (1) – देखें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराएं 2(12–ए) और 50(1)(सी) वन अधिनियम, 1927 की धारा 2(2)। **61*** **130**

GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

Section 7 – Infant, custody of – Must ordinarily be given to the mother.

धारा 7 – बालक की अभिरक्षा – साधारणतः माता को देना चाहिए। **307** **545**

HINDU ADOPTION AND MAINTENANCE ACT, 1956

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956

Sections 7 and 9 (4) – See Section 41 (6) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

धाराएं 7 और 9 (4) – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41(6)(बी)। **27** **58**

HINDU LAW:

हिन्दू विधिः

– Partition – Key issues relating to partition suit – Explained in para 24.

विभाजन विभाजन के वाद से संबंधित मुख्य बिन्दु – निर्णय चरण 24 में समझाये गये। **131(i)** **233**

– Presumption of jointness of a family.

एक परिवार के संयुक्त होने की उपधारणा। **308** **547**

HINDU MARRIAGE ACT, 1955

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

Section 5 – Presumption of marriage – When can be drawn? When a man and woman have cohabited continuously for a number of years like spouse – The court can draw such presumption.

धारा 5 – विवाह की उपधारणा – कब की जा सकती है – जब एक पुरूष और एक महिला लगातार कई वर्षो से स्पाउस के रूप में रहते है – तब न्यायालय ऐसी उपधारणा कर सकता हैं।

71(ii) 146

Section 7 – Marriage, proof of.

धारा 7 – विवाह का प्रमाण। **28(i) 60**

Section 13 – Dissolution of marriage as per custom, validity of.

धारा 13 – प्रथा के अनुसार विवाह के विघटन की वैद्यता। **145 254**

Section 13 – Divorce on the ground of mental cruelty – Whether refusal to have sexual intercourse for a long time without sufficient reason itself amounts to mental cruelty? Held, Yes [***Samar Gosh v. Jaya Gosh, (2007) 4 SCC 511*** (ThreeJudge Bench) followed].

धारा 13 – मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति – क्या लंबे समय तक लैंगिक सहवास से, बिना पर्याप्त कारण के, इंकार करना अपने आप में मानसिक क्रूरता के समान है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ, समीर घोष विरूद्ध जया घोष (2007) 4 एस.सी.सी. 511 तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ का अनुसरण किया गया। **85 169**

Section 13 – Divorce petition on ground of epilepsy, proof of.

धारा 13 – मिरगी के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका में प्रमाण। **243 447**

Section 13 (1) (1a) – Divorce on the ground of mental cruelty.

धारा 13 (1) (1a) – मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका।

244* 449

Section 13 – See Sections 45 and 114 of the Evidence Act, 1872.

धारा 13 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 और 114। **84 167**

HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

Section 6 – Custody, determination of – The paramount consideration is the welfare of the child and not the rights of his/her parents.

धारा 6 – अभिरक्षा का निर्धारण – बालक का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण विचार योग्य प्रश्न है न कि उसके माता–पिता के अधिकार। **29 63**

Section 6 – See Section 7 of the Guardians and Wards Act, 1890.

धारा 6 – देखें संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7। **307** **545**

HINDU SUCCESSION ACT, 1956

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956

Sections 4, 6 and 8 – Suit for partition by grandson – After coming into force of the Hindu Succession Act, 1956 grandson has no birth right in the properties of grandfather and he cannot claim partition during the life time of his father.

धाराएं 4, 6, और 8 – पोते द्वारा विभाजन का वाद – हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने के बाद पोते को उसके दादा की संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है और वह उसके पिता के जीवन काल में विभाजन का दावा नहीं कर सकता।

86* **170**

Section 8 – See Sections 9, 13(b), 16(b) and 17 of the Specific Relief Act, 1956

धारा 8 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएँ 9, 13 (बी), 16 (बी) और 17

220 **413**

Section 8 – (i) Succession – Self-acquired property of deceased, devolution of.

(ii) Principle of ***res judicata***, applicability of.

धारा 8 – (i) उत्तराधिकार – मृतक की स्वअर्जित संपत्ति का न्यागमन।

(ii) पूर्व न्याय या रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत का लागू होना। **203** **366**

INDIAN PENAL CODE, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860

Sections 34, 120-B and 302 – (i) There is always no direct evidence available for common intention and conspiracy – Both are matters to draw inference.

(ii) Accused was seen by sole eye witness, standing outside the house during incidence – Not named in FIR – No weapon or property seized from him – There were no evidence against him either direct or circumstantial – His conviction set aside by the Apex Court.

धाराएं 34, 120–बी और 302 – (i) सामान्य आशय और षड़यंत्र के लिए प्रायः कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है – यह दोनों अनुमान निकालने के विषय है।

(ii) अभियुक्त का घटना के दौरान घर के बाहर खड़े होना, एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी ने देखा – अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं था – उससे कोई हथियार या सम्पत्ति बरामद नहीं हुई – उसके विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं थी – उसकी दोषसिद्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त की गयी।

30 **64**

Sections 34, 201, 302 and 364-A – Defective investigation, non effect of.

Non-recovery of corpus delicti, effect of.

Proof of offence beyond reasonable doubt, necessity of .

धाराएं 34, 201, 302 और 364–ए – त्रुटि पूर्ण अनुसंधान का प्रभाव न होना – बतलाया गया।

मृत शरीर के जप्त न होने का प्रभाव – बतलाया गया।

अपराध के युक्तियुक्त संदेह का परे प्रमाणित होने की आवश्यकता – बतलाई गयी।

305(v) to(vii) **543**

Sections 34, 302 and 149 – Offence of murder under sections 148, 302 r/w/s 34 or 149.

(a) Testimony of the eye witness regarding the main accused 'A' is acceptable, duly proved by FIR and postmortem report as well as by medical evidence and circumstantial evidence – Conviction held, proper.

(b) Common intention and common object, consideration of.

धाराएं 34, 302 और 149 – धारा 148, 302 सहपठित धारा 34 या 149 के अधीन हत्या का अपराध।

(a) चक्षु साक्षी की साक्ष्य मुख्य अभियुक्त ''ए'' के संबंध में स्वीकार योग्य है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन से और शव परीक्षण प्रतिवेदन, मेडीकल साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सम्यक रूप से समर्थित – दोषसिद्धि, उचित पायी गयी।

(b) सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य पर विचार। **26(v)** **51**

Sections 53, 279, 337 and 304-A – (i) By driving the jeep on the public road in a rash and negligent manner, the accused had endangered the life of one victim who died and another who got injured – Trial court found him guilty for offences punishable under Section 279, 337, 304-A IPC and sentenced him to undergo six months and two years R.I. with fine of Rs. 2,500 – ASJ, in appeal, upheld the order of trial court – High Court, in revision, reduced the sentences to period already undergone – The Apex Court set aside the order of the High Court and restored the sentence imposed by the Trial Court.

(ii) Duty of court to award adequate sentence – Reiterated.

धाराएं 53, 279, 337 और 304–ए – (i) अभियुक्त ने लोकमार्ग पर जीप को उतावलेपन और उपेक्षा से चलाकर एक आहत् का जीवन खतरे में डाला जिसकी मृत्यु हो गई और दूसरा आहत् घायल हुआ – विचारण न्यायालय ने उसे अपराध धारा 279, 337, 304ए भा.द.सं. में दोषी पाया और उसे 6 माह और 2 वर्ष का दण्ड और रूपये 2500/– अर्थदण्ड किया – अपर सत्र न्यायाधीश ने अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को कायम रखा – उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में दण्ड को अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि तक कम किया – सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया और विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्ड को पुनः कायम किया।

(ii) न्यायालय के युक्तियुक्त दण्ड को देने के कर्त्तव्य को पुनः बतलाया गया।

87 **170**

Sections 96 to 100, 149 and 302 – Right of private defence – When not available?

धाराएं 96 से 100, 149 और 302 — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार – कब उपलब्ध नहीं होता है?

204 **373**

Section 97 – Right of private defence, availability and exercise of.

धारा 97 — निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपलब्ध होना व प्रयुक्त किया जाना।

309(i) **548**

Sections 97, 100, 302 and 325 – Right of private defence and whether or not a right of private defence of person or property was available to an accused is a question of fact or at least a mixed question of law and fact.

धाराएं 97, 100, 302 और 325 — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार – एक अभियुक्त को शरीर या संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था या नहीं यह एक तथ्य का प्रश्न या कम से कम विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होता है। **245*** **450**

Sections 109, 120-B, 420, 468 and 477 – See Section 197 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 109, 120—बी, 420, 468 और 477 — देखें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197।

246 **450**

Section 120-B – See Sections 190 and 204 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 120—बी — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 और 204। **88** **171**

Section 120-B – See Section 197 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 120—बी— देखें दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 197। **331*** **586**

Sections 120-B, 420 and 468 – See Sections 197 and 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 120—बी, 420 और 468 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 और 482। **76** **153**

Sections 120-B and 500 – See Section 200 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 120—ब और 500 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200।

294 **518**

Sections 149, 299, 300, 302 and 304 – Culpable homicide and murder – When a case falls under section 302 or 304 Part I or Part II IPC – Factors to be seen.

धाराएं 149, 299, 300, 302 और 304 — सदोष मानव वध और हत्या — कब एक मामला धारा 302 या 304 भाग—प या भाग—पप, भा.दं.सं. में आता है — तथ्य जो देखनें होंगे।

248* 455

Sections 149 and 302 – Unlawful assembly – Some accused persons were acquitted, number of the rest of accused is reduced to less than five – Whether they can be convicted with the aid of section 149 of IPC?

धाराएं 149 और 302 — अवैध सभा — कुछ अभियुक्तगण दोषमुक्त किए गए, शेष अभियुक्त की संख्या घट कर 5 से कम रह गई — क्या उन्हें (शेष अभियुक्तगण को) धारा 149 भा.दं.सं. की सहायता लेकर दोषसिद्ध किया जा सकता है? **310 550**

Sections 149, 302 and 304 – Effect of non-framing of specific charge under section 149 IPC.

धाराएं 149, 302 और 304 — धारा 149 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट आरोप विरचित न करने का प्रभाव। **247 452**

Section 188 – What is the condition precedent for taking cognizance of offence under section 188 of IPC?

धारा 188 — धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लेने के लिये पूर्ववर्ती शर्त क्या है।

146 256

Section 300 Exception 1 and Section 302 – (i) When exception 1 of Section 300 IPC is attracted? Held, where the ingredients of exception 1 are satisfied then the same is attracted.

(ii) Grave provocation within the meaning of Exception 1 of Section 300 IPC is a provocation where judgment and reason take leave of the offender and violent passion takes over – "Provocation" has been defined by Oxford Dictionary.

धारा 300 अपवाद एक और धारा 302 — (i) धारा 300 का अपवाद एक कब आकर्षित होता है ? अभिनिर्धारित किया गया, जब अपवाद एक के घटक संतुष्ट होते है तब वह आकर्षित होता है।

(ii) ''प्रकोपन'' को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक क्रिया, अपमान आदि के रूप में परिभाषित किया गया है।

89 177

Sections 300 Exception 4, 302 and 304 – When exception 4 of section 300 I.P.C. is attracted?

धाराएं 300 का अपवाद 4, 302 और 304 — धारा 300 भा.दं.सं. का अपवाद 4 कब आकर्षित होता है?

31 65

Sections 300 Exception 4, 302 and 304 – When Exception 4 to section 300 IPC is attracted? Held, to attract Exception 4 of section 300 IPC, four requisites must be satisfied.

When above Exception is attracted, conviction can be altered to section 304 Part I IPC instead of section 302 IPC.

धाराएं 300 का अपवाद 4, धारा 302 और 304 – कब धारा 300 भा.द.सं. का अपवाद 4 आकर्षित होता है? अभिनिर्धारित किया गया जहां 4 अनिवार्यतायें संतुष्ट हो जाती है वहां धारा 300 का अपवाद 4 आकर्षित होता है।

जहां उक्त अपवाद आकर्षित होता है वहां धारा 302 भा.द.सं. के स्थान पर दोष सिद्धि 304 भाग 1 भा.द.सं. में परिवर्तित करना चाहिये। **147** **257**

Section 300 Exception 5 – (i) When Exception 5 of Section 300 I.P.C. is attracted?

(ii) Nature of Exception 5 of Section 300 I.P.C.

धारा 300 का अपवाद 5 – (i) धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता का अपवाद 5 कब आकर्षित होता है?

(ii) धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 5 की प्रकृति। **32** **68**

Sections 300 and 376 (2) (g) – Crime against women – Sentencing Policy.

धाराएं 300 और 376 (2)(जी) – महिला के विरूद्ध अपराध – दण्ड नीति।

296 **521**

Section 302 – As many as 20 injuries, all incised wounds, were found all over the body of deceased/wife – Immediately before the death of the deceased/wife, when the accused/husband and deceased/wife were living together, the entire burden was upon the accused to show as to who else was responsible for killing the deceased.

Submission of accused for lesser sentence, denied.

धारा 302 – बीस चोटें, जो सभी छेदित घाव या इंसाइज्ड वूंड थी, मृतक/पत्नी के पूरे शरीर पर पाई गई थी – जब अभियुक्त/पति और मृतक/पत्नी, मृतक/पत्नी की मृत्यु के ठीक पूर्व साथ–साथ रह रहे थे अभियुक्त पर यह पूरा भार (प्रमाण भार) था कि वह यह दर्शावे की मृतक की हत्या के लिये कौन उत्तरदायी है।

अभियुक्त का कम दण्ड देने का तर्क – नकारा गया। **148** **259**

Section 302 – (i) Death – Suicide or homicide – Burn injury case.

(ii) Setting afire another person after pouring kerosene – It is an act which is likely to cause death of such person – Offence of murder is complete – Conviction held, proper.

धारा 302 – (i) मृत्यु – आत्महत्या या मानव वध – जलने से आयी चोट का प्रकरण।

(ii) अन्य व्यक्ति पर केरोसिन उड़ेलने के बाद आग लगाना – यह ऐसा कृत्य है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी – हत्या का अपराध पूर्ण हो जाता है – दोषसिद्धि उचित पाई गई।

90 **179**

Section 302 – Murder trial – Burn injury case – Two probable hypothesis arise in the judicial mind in this type of cases.

धारा 302 – हत्या का विचारण – जलने से आयी चोटों का मामला – इस प्रकार मामलों के में एक न्यायिक मस्तिष्क में दो संभाव्य परिकल्पनाएं उत्पन्न होती है। **34 (i)** **70**

Section 302 – Murder trial – Circumstantial evidence – Theory of last seen together – Deceased was last seen with the accused – His dead body was found soon thereafter – Certain articles belonging to the deceased were recovered from the custody of accused and his uncle at their instance – Conviction held proper.

धारा 302 – हत्या का विचारण – परिस्थिति जन्य साक्ष्य – अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – मृतक अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया – उसके ठीक पश्चात् उसका मृत शरीर पाया गया – मृतक से संबंधित कुछ वस्तुएँ अभियुक्त और उसके चाचा से उनकी निशादेही से बरामद हुई – दोषसिद्धि उचित पायी गई। **91*** **180**

Section 302 – Murder Trial – Circumstantial evidence – Whether theory of last seen together itself is a conclusive proof for convicting the accused?

धारा 302 – हत्या का विचारण – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – क्या अंतिम बार जीवित साथ देखे जाने का सिद्धांत अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिये अपने आप में एक निश्चायक प्रमाण होता है? **205** **375**

Section 302 – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32। **33** **70**

Section 302 – See Sections 3 and 8 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 और 9। **249** **456**

Sections 302 r/w/s 34 and 302 r/w/s 149 – Absence of charge with the help of section 34 of IPC, effect of – Accused persons were tried jointly for the offence of murder and charges were framed under section 302/149 IPC – Held, instead of convicting with the help of section 149 of the Code, no prejudice would be caused to the accused if he is convicted with the help of section 34 of the Code.

धाराएं 302 सहपठित 34 और 302 सहपठित 149 – धारा 34 की सहायत से आरोप के न होने का प्रभाव – अभियुक्तगण का विचारण संयुक्त रूप से हत्या के अपराध के लिए किया गया व और धारा 302/149 के आरोप विरचित किए गये – अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्तगण को धारा 149 की सहायता लेकर दोषसिद्ध करने के स्थान पर धारा 34 की सहायता लेकर दोषसिद्ध किया गया तो अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल असर नहीं गिरता। **311** **554**

Section 302 r/w/s 147, 148 and 149 – Unlawful assembly – Necessity for constitution of.

धारा 302 सहपठित धारा 147, 148 और 149 — अवैध सभा — प्रत्येक सदस्य का कुछ कृत्य होने की आवश्यकता का अपवाद — समझाया गया। **93(B)*** **182**

Sections 302 and 304 Part 1 – Conviction can be altered to section 304 Part I IPC in place of section 302 IPC.

धारा 302 और 304 भाग 1 — दोषसिद्धि धारा 302 भा.द.सं. के स्थान पर 304 भाग 1 भा.द.सं. में परिवर्तित की जा सकती है। **149** **261**

Sections 302 and 304 Part II – Nature of offence – Bride burning cases – Whether the act of accused of pouring water on the burning deceased would be a mitigating circumstance?

धाराएं 302 और 304 भाग 2 — अपराध की प्रकृति नवविवाहिता को जलाने के मामले — क्या अभियुक्त द्वारा जल रही मृतक पर पानी उड़लने का कृत्य एक शमनकारी परिस्थिति होगी?

312 **555**

Sections 302, 304-B and 498-A – When charge under section 302 IPC shall be framed along with section 304-B IPC?

धाराएं 302, 304—बी और 498—ए — कब धारा 304—बी भा.द.सं. के आरोप के साथ धारा 302 भा.द.सं. का आरोप विरचित किया जायेगा? **77(i)** **155**

Sections 302, 326 and 460 – Offence under sections 302, 326 and 460 of IPC – Acid attack – Death of a married woman by acid burns caused by accused, who had an evil eye and wanted to keep her and also caused injuries to other persons who went to her rescue – Offences charged were proved beyond reasonable doubt by duly proved dying declaration and statements of eye witnesses – FIR was also lodged promptly – Imposition of death penalty – Reference under section 366 Cr.P.C., confirmation of – Held, Trial Court rightly awarded death penalty to accused – Further held, persons who suffered disfiguration and burn injuries are entitled to adequate compensation.

धाराएं 302, 326 और 460 — धारा 302, 326 और 460 के अधीन अपराध — अम्ल या एसिड द्वारा हमला अभियुक्त द्वारा कारित अम्ल द्वारा हमले से एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई जिस पर अभियुक्त बुरी नजर रखता था और उसे उसके साथ रखना चाहता था तथा बचाने आये एक व्यक्ति को उपहति कारित हुई — प्रत्यक्ष साक्षीगणों के कथन और सम्यक रूप से प्रमाणित मृत्यु पूर्व कथन से अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुआ — प्रथम सूचना तत्काल दर्ज करवाई गई थी — मृत्यु दंड अधिरोपित किया गया — धारा 366 दं. प्र.सं. के अधीन उसकी पुष्टि के लिये निर्देश — अभिनिर्धारित किया गया विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु दंड सही दिया है — व्यक्ति जिन्हें जलने के कारण चोटे आयी और विद्रूपीकरण हुआ, पर्याप्त प्रतिकर पाने के हकदार है। **150** **264**

Sections 302 and 364-A – (i) Applicability of section 364-A of IPC (kidnapping for ransom).

(ii) Whether the provision of section 364-A of the IPC is unconstitutional?

(iii) Meaning of expression 'any other person' used in section 364-A of the IPC.

धाराएं 302 और 364–ए – (i) धारा 364–ए का लागू होना (मुक्ति धन के लिए व्यपहरण)

(ii) क्या धारा 364–ए भा.द.सं. का प्रावधान असंवैधानिक है?

(iii) धारा 364–ए भा.द.सं. में प्रयुक्त शब्द ''कोई अन्य व्यक्ति'' का अर्थ। **313*** **556**

Sections 302 and 364-A – Recovery of dead body from covered gutters and personal belongings of the deceased from other places disclosed by the accused stood fully proved – It casts a duty on the accused to give proper explanation – If accused failed to give an explanation, it provides an additional circumstance against the accused.

धाराएं 302 और 364–ए – एक ढकी हुई नाली से मृत शरीर और मृतक के व्यक्तिगत सामान अन्य स्थान से अभियुक्त की सूचना पर बरामद होना पूर्णतः प्रमाणित हुआ – यह अभियुक्त पर कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह उसका उचित स्पष्टीकरण दे – यदि अभियुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो यह अभियुक्त के विरूद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति होती है। **80(ii)** **161**

Sections 302 and 376 – Offence of rape alongwith murder – Death sentence, confirmation of – Law explained.

धाराएं 302 और 376 – हत्या सहित बलात्कार का अपराध – मृत्यु दण्ड की पुष्टि – विधि समझाई गई।

151(i) **267**

Sections 302 and 376(2)(f) – Gang rape and murder – Circumstantial evidence, appreciation of.

धाराएं 302 और 376(2)(एफ) – सामूहिक बलात्संग और हत्या – परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मूल्यांकन मृत्यु दण्ड संबंधित परिस्थितियाँ बतलाई गई। **92 (iii)*** **181**

Section 304-A – See Sections 357 and 357-A of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 304–ए – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 357 और 357–ए।

297* **529**

Section 304-A – (i) Offence of causing death by rash or negligent driving, severity of – Law explained.

(ii) Sentencing Policy – Quantum of sentence, adequacy of – Law explained.

धारा 304–ए – (i) तेजी या लापरवाही पूर्वक वाहन चालन द्वारा मृत्यु कारित करने संबंधी अपराध की गंभीरता – विधि समझाई गई।

(ii) दंड नीति – दंड की मात्रा की पर्याप्तता – विधि समझाई गई। **206*** **377**

Section 304-B – Accused/husband was acquitted by High Court – Claim of parity by mother–in–law.

धारा 304–बी – अभियुक्त/पति उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था – सास द्वारा समानता का दावा। **152 (ii) 275**

Section 304-B – Dowry death – The prosecution should produce evidence to prove that soon before her death, the deceased was subjected to cruelty or harassment.

धारा 304–बी – दहेज मृत्यु – अभियोजन को यह प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि मृतक के साथ उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता या उसे परेशान किया गया था।

250 459

Section 304-B – (i) Offence under section 304-B IPC – Bride burning, proof of – Initial burden lies on the prosecution to prove ingredients of the offence by preponderance of probabilities.

धारा 304–बी – (i) धारा 304–बी भ.दं.सं के अधीन अपराध – वधु को जलाने का प्रमाण – प्रारंभिक प्रमाण भार अभियोजन पर होता है कि वह अपराध के घटक अधिसंभावनाओं की प्रबलता के स्तर पर प्रमाणित करे।

314(i) 557

Section 304-B – (i) Offence under section 304-B IPC, ingredients of and word 'shown', connotation of.

(ii) Offence under section 304-B IPC – The word 'soon', interpretation of.

(iii) Initial presumption of innocence of the accused, replacement of by an assumption of guilt – Burden of proof.

(iv) Dowry death – Cruelty – Soon before death – Wife committed suicide within one year of her marriage – It cannot be said that cruelty was not soon before death.

(v) Presumption of innocence, importance of.

(vi) Dowry death – Family members of husband, implication of – If accused husband not living with parents and/or other family members, stronger proof is required to implicate family members of the accused husband.

(vii) Guilt of accused husband – Acquittal of father, brother or other family members, non-effect of – Law explained.

(viii) FIR – Delay, non-effect of – Wife died allegedly by consuming poison – FIR lodged on the next day i.e. after 10 hours of incident – Held, in fact delay has no effect as it cannot be said to be inordinate delay.

धारा 304–बी – (i) धारा 304 बी भा.द.सं. के अपराध के घटक में शब्द ''दर्शाया'' का अर्थ – वास्तव में इसका अर्थ ''प्रमाणित करना'' है।

(ii) धारा 304 बी भा.द.सं. का अपराध – शब्द ''कुछ पूर्व'' या ''soon'' का अर्थान्वयन।

(iii) अभियुक्त के निर्दोष होने की प्रारंभिक उपधारणा का स्थान दोषसिद्धि की धारणा द्वारा लिया जाना – प्रमाण भार।

(iv) दहेज मृत्यु – मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता पत्नी ने विवाह के 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या की – यह नहीं कहा जा सकता की मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता नहीं थी।

(v) निर्दोष होने की उपधारणा का महत्व – स्पष्ट किया गया।

(vi) दहेज मृत्यु – पति के परिवार के सदस्यों को लिप्त किया जाना।

(vii) अभियुक्त पति का दोषी होना – पिता, भाई या परिवार के अन्य सदस्यों की दोषमुक्ति का प्रभाव न होना – विधि समझाई गई।

(viii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन – विलंब का प्रभाव न होना – अभिकथित रूप से जहर का सेवन करने से पत्नी की मृत्यु – घटना के 10 घंटे बाद अगले दिन प्रथम सूचना दर्ज करवायी गई – अभिनिर्धारित किया गया, विलंब का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह असामान्य विलंब नहीं है। **153*** **276**

Section 304-B – See Section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961.

धारा 304–बी – देखें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2। **251** **461**

Sections 304-B, 306 and 498-A – Mother and brother were acquitted by the High Court – Claim for parity by husband.

धाराएं 304–बी, 306 और 498–ए – उच्च न्यायालय द्वारा माता और भाई को दोषमुक्त किया गया है – पति द्वारा समानता का दावा। **94(ii)** **184**

Sections 304-B and 498-A – Dowry death – Bride burning.

(i) Acquittal of co-accused (i.e. sister-in-law of deceased) – Criminal liability of the other accused person (i.e. mother-in-law of deceased), non-effect of.

(ii) Dowry death, proof of.

(iii) Dowry death – Bride burning – Sentencing – Undue sympathy is not warranted with respect to crime against women and children.

धाराएं 304–बी और 498–ए – दहेज मृत्यु – बहु को जलाना।

(i) ननंद सह–अभियुक्त की दोषमुक्ति – अन्य अभियुक्त सास के दांडिक दायित्व पर इसका प्रभाव न होना।

(ii) दहेज मृत्यु का प्रमाण।

(iii) दहेज मृत्यु – बहु का जलाना – दंड – महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध के संबंध में अनावश्यक दयालुता आवश्यक नहीं होती है। **154** **279**

Sections 304-B and 498-A – Dowry death, proof of – Death of the deceased was within seven years of marriage – Was subjected to harassment for dowry soon before her death by her husband and mother-in-law who were living together – Death was in circumstances other than natural and not accidental – Accused persons; husband and mother-in-law of the deceased, living in the same house, took false plea that they had no idea that the deceased received burn injuries – Although subsequent dying declaration recorded by Magistrate was inconsistent but the same recorded earlier by the Police Officer was consistent with the circumstances on record – Held, offences duly proved – Allowing the appeal against acquittal, conviction recorded by the Trial Court restored.

धाराएं 304–बी और 498–ए – दहेज मृत्यु का प्रमाण – मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई – सास और पति द्वारा मृत्यु के ठीक पूर्व पत्नी को दहेज की मांग को लेकर तंग किया जाना प्रमाणित हुआ है – म ृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी और दुर्घटनावश नहीं हुई थी – अभियुक्तगण पति और सास उसी घर में मृतक के साथ रहते थे और उन्होंने यह असत्य बचाव लिया की मृतक को जलने से कैसे चोटें आई उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं – मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये गये मृत्यु पूर्व कथन में विसंगतता थी किन्तु पुलिस द्वारा उसके पूर्व अभिलिखित मृत्यु पूर्व कथन में स्थिरता थी – अभिनिर्धारित किया गया अपराध सम्यक रूप से प्रमाणित हुआ – दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील को स्वीकार किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दोषसिद्धि के आदेश को पुनः कायम किया गया। **155(vi) 281**

Sections 304-B and 498-A – Offences under sections 304-B and 498-A IPC are not mutually inclusive – If an accused is acquitted under one offence, it does not mean that the accused cannot be convicted for another offence.

धाराएं 304–बी और 498–ए – धारा 304–बी और 498–ए भा.द.सं. के अधीन अपराध परस्पर एक दूसरे में शामिल नहीं है – यदि अभियुक्त को इनमें से एक अपराध में दोषमुक्त कर दिया गया हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे दूसरे अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। **156 286**

Sections 306/34 – See sections 438 and 439 (2) of the Criminal Procedure Code, 1860.

धाराएं 306/34 – देखें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 और 439 (2)।

21* 40

Sections 306 and 498-A – See Sections 216, 227 and 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 306 और 498–ए – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 216, 227 और 228।

252* 464

Sections 306 and 498-A – Whether mere extra-marital relationship of husband comes under mental cruelty as provided in explanation (a) of section 498-A of the IPC?

धाराएं 306 और 498–ए – क्या केवल पति के विवाहेत्तर संबंध धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता के स्पष्टीकरण (ए) में उल्लेखित मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते है? **315** **563**

Section 307 – (i) Offence of attempt to murder punishable under section 307 IPC is not a private dispute between the parties inter se but is held to be a crime against the society so, not allowed to be compounded.

(ii) Quashing of proceeding on the ground of settlement arrived at between parties – Principles stated in para 12.

धारा 307 – (i) धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन हत्या के प्रयत्न का अपराध पक्षकारों के मध्य का एक निजी विवाद नहीं होता है बल्कि यह समाज के विरूद्ध अपराध होता है अतः इसमें समझौते की अनुमति नहीं देना चाहिए।

(ii) पक्षकारों के मध्य समझौता होने के आधार पर कार्यवाही समाप्त करना – सिद्धांत – निर्णय चरण 12 में बतलाये गये। **35** **73**

Sections 324 and 326 – Where complainant and accused are close relatives, taking into account the compromise reached between them, reduction in sentence can be ordered.

धाराएं 324 और 326 – जहाँ परिवादी और अभियुक्त निकट संबंधी हो वहाँ उनके बीच हुए समझौते के प्रकाश में दण्ड को कम करने का आदेश किया जा सकता है। **253** **465**

Sections 353 and 503 – A page created by traffic police on the Face book – Posting comment on it by accused – Whether constitute offences under sections 353 and 503 of IPC?

धारा 353 और 503 – यातायात पुलिस द्वारा फेसबुक पर एक पेज या पृष्ठ सृजित किया गया – अभियुक्त द्वारा उस पेज पर कमेंट या टिप्पणी दर्ज की गई – क्या धारा 353 व 503 भा.द.सं. के अपराध का गठन होता है? **157** **287**

Sections 363 and 364-B – See sections 378 and 386 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 363 और 364–बी – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 और 386। **158** **288**

Sections 363 and 376 – See Sections 164 and 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 363 और 376 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 और 439। **95*** **185**

Sections 363 and 376(2) (g) – See Sections 3 and 45 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 363 और 376 (2) (g) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 और 45।

316 **565**

Section 376 – (i) Directions issued in ***Delhi Domestic Working Women's Forum v. Union of India and others, (1995) 1 SCC 14*** reiterated.

(ii) Sexual assault cases, how to be dealt with? Hon'ble the Apex Court made some important observations.

धारा 376 – (i) न्याय दृष्टांत देहली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (1995) 1 एस.सी.सी. 14 में दिये गये निर्देश पुनः बतलाये गये।

(ii) लैंगिक हमले के मामलों को किस तरह लिया जाये – माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की। **96** **186**

Section 376 – See Rule 12(3) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007

धारा 376 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 (3) **317** **567**

Section 376 – Whether lapses on the part of I.O. in any manner affect the credibility of the statement of prosecutrix?

धारा 376 – क्या अनुसंधान अधिकारी के भाग पर की गई कमियाँ अभियोक्त्री के कथनों को किसी भी तरह से प्रभावित करती है? **189 (ii)*** **340**

Section 376 (2) (f) – When compromise is produced in sexual assault cases, what should be the approach of the court?

धारा 376(2)(एफ) – जब लैगिंक हमले के प्रकरणों में समझौता प्रस्तुत किया जाता है तब न्यायालय का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? **318*** **569**

Sections 376, 377, 417 and 420 – See Section 53-A of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 376, 377, 417 और 420 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53–ए।

97* **188**

Section 379 – See Section 4 (1-A), 21 and 22 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

धारा 379 – देखें माइन्स एवं मिनरल्स (डेपलपमेंट एडं रेग्युलेशन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1ए), 21 और 22। **36** **76**

Section 381 – See Section 31 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 381 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31। **188*** **339**

Sections 399 and 402 – Offence of making preparation and assembling to commit dacoity – Appreciation of evidence.

धाराएं 399 और 402 – डकैती करने की तैयारी करने और डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होने के अपराध – साक्ष्य का मूल्यांकन। **254*** **465**

Sections 406 and 407 – See Sections 468 and 472 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 406 और 407 – देखें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 और 472। **195** **350**

Sections 406, 409 and 420 – A society purchased a land in the year 1978 – Its officials sold the same to their relatives in the year1996 – Relatives sold the same to the Directors of the society in the same year – Complaint filed under sections 406, 409 and 420 IPC.

धाराएं 406, 409 और 420 – एक सोसायटी ने जमीन वर्ष 1978 में क्रय की – वर्ष 1996 में उसके अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों को वही जमीन विक्रय कर दी – रिश्तेदारों ने उसी वर्ष में जमीन वापस सोसायटी के संचालकों को विक्रय कर दी – एक परिवाद धारा 406, 409 और 420 भा.दं.सं. का प्रस्तुत किया गया। **319*** **570**

Section 420 – See section 200 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 420 – देखें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200। **159** **290**

Sections 420, 467 and 468 – Offence of cheating and forgery, constitution of – Forged caste certificate.

धाराएं 420, 467 और 468 – छल और कूटरचना के अपराध का गठन – कूटरचित जाति प्रमाण पत्र। **320** **571**

Sections 498–A and 304–B – If a document produced by prosecution but not exhibited – It is always open for the defence to seek reliance on such document to falsify the prosecution version.

Demand and payment of dowry – Effect of absence of documentary evidence – Demand and payment of dowry – Effect of absence of independent witness.

धाराएं 498–ए और 304–ए – एक दस्तावेज जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रदर्शित नहीं करवाया गया – प्रतिरक्षा पक्ष के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह ऐसे दस्तावेज की सहायता अभियोजन के कथानन को असत्य बतलाने के लिए ले सकती है।

दहेज की मांग और भुगतान – दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति का प्रभाव – दहेज की मांग और भुगतान – स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति का प्रभाव। **37 (i),(ii) &(iii)** **82**

Sections 498-A and 306 – See Section 31 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 498–ए और 306 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31। **74** **150**

INDORE LAND REVENUE AND TENANCY ACT, 1931

इन्दौर लैण्ड रेवेन्यू और टेनेन्सी अधिनियम, 1931

Section 31 – Tenancy rights, claim of – Basis of suit for declaration of title by successor of Ex-Ruler of Holkar State is covenant and title not claimed on the basis of tenancy rights – Tenancy rights cannot be claimed over suit scheduled properties.

Suit, burden of proof – Plaintiff has to prove and succeed on the strength of his own case – He cannot take advantage of weakness of defendant's case.

धारा 31 – टेनेन्सी राईट का दावा – स्वत्व घोषणा के वाद का आधार होल्कर राज्य के पूर्व शासक के उत्ताधिकारी द्वारा प्रसंविदा है और टेनेन्सी राईट के आधार पर स्वत्व का दावा नहीं किया है – वाद की अनुसूचित संपत्ति पर टेनेन्सी राईट का दावा नहीं किया जा सकता।

वाद का प्रमाण भार – वादी को अपना मामला अपने बल पर प्रमाणित करना होता है – वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। **289 (ii) & (iii) *** **512**

INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

Sections 66-A, 69-A and 79 – (i) Section 66-A I.T. Act, constitutional validity of – Being violative of Article 19 (1) (a) of the Constitution, is wholly unconstitutional and void.

(ii) Sections 69-A and 79 of I.T. Act and Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, constitutional validity of – Are constitutionally valid.

धाराएं 66–ए, 69–ए और 79 – (i) धारा 66–ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संवैधानिक वैधता – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के उल्लंघन में होने से यह प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक और शून्य हैं।

(ii) धारा 69–ए और 79 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्यागिकी (आम जन द्वारा सूचना तक पहुंच की रोक के लिए प्रक्रिया और रक्षा उपाय) नियम, 2009 की संवैधानिक वैधता – ये संवैधानिक रूप से वैध है। **207** **378**

JUDICIAL SERVICE PAY REVISION, PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS RULES, 2003

न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम 2003

Rules 9 and 11-A – (i) Labour judiciary – Salary and dearness allowance, payment of.

(ii) Petrol allowance and other benefits, payment of.

नियम 9 और 11–ए – (i) श्रम न्याय पालिका – वेतन और मंहगाई भत्ता का भुगतान।

(ii) पेट्रोल एलाउंस और अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाना। **98*** **189**

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

Section 7 – Claim of juvenility – Such relief can be claimed even if the matter is finally decided.

धारा 7 – किशोरावस्था का दावा – ऐसे अनुतोष का दावा मामले के अंतिम रूप से निराकृत हो जाने के बावजूद किया जा सकता है। **208*** **386**

Section 7-A – See Rule 12 (3) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007.

धारा 7–ए – देखें किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 (3) (बी)। **160** **291**

Sections 12, 52 and 53 – Legal position regarding bail of juvenile in conflict with law:

(i) Heinousness, seriousness, severity, gravity of crime are no grounds for rejection of bail.

(ii) The bail can only be rejected on the grounds (or exceptions) stated in section 12 of J.J. Act, 2000.

(iii) The provisions of section 12 of J.J. Act, 2000 are independent of general provisions of bail enshrined in sections 437 and 439 of the Cr.P.C., 1973.

धाराएं 12, 52 और 53 – विधि संबंधित विरोध में किशोर की जमानत संबंधित विधिक स्थितिः–

(i) अपराध की जघन्यता, गंभीरता, प्रचंडता, विकटता जमानत निरस्त करने के आधार नहीं है।

(ii) जमानत केवल धारा 12 अधिनियम, 2000 में बतलाये आधारों (या अपवादों) पर निरस्त की जा सकती है।

(iii) धारा 12 अधिनियम, 2000 के प्रावधान धारा 437 और 439 दं.प्र.सं. के सामान्य प्रावधानों से स्वतंत्र प्रावधान है। **161** **293**

Section 15 – If it is proved that on the date of offence the accused was juvenile, the maximum period for which he could be kept in a special home is for three years – Where such period has already lapsed, he should be released immediately – ***Ajay Kumar v. State of M.P., 2010 (15) SCC 83*** relied on.

धारा 15 – यदि यह प्रमाणित होता है कि अपराध करने की तारीख पर अभियुक्त किशोर था – उसे अधिकतम अवधि जिसके लिये विशेष गृह में रखा जा सकता है वह 3 वर्ष होती है – जहां ऐसी अवधि पहले से निकल चुकी हो उसे तत्काल रिहा कर देना चाहिये। अजय कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी., 2010 (15) एस.सीसी. 83 पर विश्वास किया गया। **162 295**

Section 41 – Adoption under section 41 of the Act of 2000 – Procedure of – Law explained.

धारा 41 – धारा 41 अधिनियम, 2000 के अधीन दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, विधि समझायी गयी।

38 85

Section 41 (6)(b) – Adoption under section 41 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 – Family court, jurisdiction of.

धारा 41 (6)(बी) – धारा 41 जे.जे. एक्ट 2000 के तहत दत्तक ग्रहण – परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकार।

27 58

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2003 (M.P.)

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2003 (म.प्र.)

Rule 2 (v) – See section 41 (6) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

नियम 2 (अ) – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41 (6) (बी)। **27 58**

JUVENILE JUSTICE (CARE & PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007

Rule 12 – See Section 7 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000.

नियम 12 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7। **208* 386**

Rule 12 (3) – There is difference of just two days between two birth certificates of prosecutrix – Both the documents, which covered under rule 12(3) (a) of the Rules of 2007, supported the case of prosecution – The difference held, immaterial – Ossification test is not the sole criteria for determination of age of the prosecutrix .

नियम 12 (3) – अभियोक्त्री की जन्म तिथि में दो जन्म प्रमाण पत्रों में मात्र दो दिन का अंतर है, दोनों दस्तावेज नियम 12(3)(ए) नियम, 2007 में शामिल है जो अभियोजन के मामले का समर्थन करते है – ये अंतर अतात्विक होना अभिनिर्धारित किया गया – ओशिफिकेशन परीक्षण अभियोक्त्री की उम्र निर्धारित करने का एक मात्र तरीका नहीं है। **317** **567**

Rule 12 (3) (b) – Applicant is deaf and dumb – Never admitted in any school – Only possible method to decide his claim of juvenility is to obtain medical opinion from the duly constituted Medical Board in terms of Rule 12(3) of the Rules, 2007.

नियम 12 (3) (बी) – आवेदक गूंगा और बहरा है – उसे कभी किसी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया – उसके किशोरावस्था का दावा निराकृत करने का एक मात्र संभव उपाय, सम्यक रूप से गठित मेडिकल बोर्ड से नियम 12 (3) के अनुसार राय लेना है। **160** **291**

Rules 12 and 98 – See section 15 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

नियम 12 और 98 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15। **162** **295**

Rule 33 (5) – See Section 41 (6) (b) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

नियम 33 (5) – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41 (6)(बी)। **27** **58**

LAND ACQUISITION ACT, 1894

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

Sections 4, 6 and 11 – Land acquisition proceeding initiated under the Act of 1894, lapse of after coming into force of section 24 (2) of the Act of 2013 – Law explained.

धाराएं 4, 6 और 11 – भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 1894 के तहत प्रारंभ की गई, धारा 24 (2) अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद लेप्स होना – विधि समझाई गई। **163** **296**

Section 12 (2) – What is constructive notice of an award passed under section 11 of the Act of 1894?

धारा 12 (2) – धारा 11 अधिनियम, 1894 के अधीन पारित अवार्ड की प्रलक्षित सूचना या आन्वयिक सूचना का अर्थ। **321 (i)** **571**

Section 23 – (i) Assessment of compensation – Deductions for development of land.

(ii) Determination of market value of land – Comparative sale method.

(iii) In this case sixty percent deduction on market value of acquired land for development expenses allowed.

धारा 23 – (i) प्रतिकर निर्धारण – भूमि के विकास के लिये कटौतियाँ।

(ii) भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करना – तुलनात्मक विक्रय विधि।

(iii) इस मामले में अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य में 60 प्रतिशत कटौती विकास खर्च के लिये मानी गई। **99** **190**

Sections 23 (1A) and 28 – (i) Determination of compensation – Belting area.

(ii) Nature of proviso to sections 23 (1A) and 28.

धाराएं 23 (1ए) और 28 – (i) प्रतिकर का निर्धारण – बिलेटिंग एरिया।

(ii) धारा 23 (1ए) और 28 के परन्तुक की प्रकृति। **39** **86**

Section 28-A – Whether second application under section 28-A of the Land Acquisition Act is maintainable after getting advantage of same provision?

धारा 28–ए – क्या धारा 28–ए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन, इस प्रावधान का लाभ ले लेने के बाद, द्वितीय आवेदन प्रचलन योग्य होता है ? **322*** **573**

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)

भू राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)

Sections 117, 176, 177 (3), 185 and 190 – Suit for declaration of title on the basis of sub-tenancy – Unauthorized entries as occupancy tenant in khasra, effect of .

धाराएं 117, 176, 177 (3), 185 और 190 – सब टेनेन्सी के आधार पर स्वत्व घोषणा का वाद – खसरे में मौरूसी कृषक के अनाधिकृत इंद्राज का प्रभाव न होना। **323** **574**

Sections 162 and 248 – (i) Section 162 of the Code, applicability of.

(ii) Section 248 of the Code, eviction thereunder – Law explained.

धाराएं 162 और 248 – (i) धारा 162 का लागू होना।

(ii) धारा 248 के अधीन निष्कासन – विधि समझाई गई। **164** **298**

Section 165 (1) – Devolution of interest – Unamended section 165 (1) of the Code of 1959, applicability of .

धारा 165 (1) – हित का न्यागमन – असंशोधित धारा 165 (1) अधिनियम, 1959 का लागू होना।

324 (i) **576**

Sections 165 (6), 170–B (1) and (2) – Permission under section 165(6) of M.P. Land Revenue Code – Obtained by playing fraud – Burden of proof – It is upon seller to prove that the permission was obtained by playing fraud.

When the provisions of sub-section (1) and (2) of the section 170-B are not applicable? Held, where the land has been transferred by way of registered instrument and after due permission of Collector, the said provisions are not applicable.

धाराएं 165(6), 170–बी(1) और (2) – धारा 165 (6) म.प्र. भूराजस्व संहिता के अधीन अनुमति – कपट द्वारा प्राप्त की गई – प्रमाण भार – यह (प्रमाण भार) विक्रेता पर है कि वह प्रमाणित करें कि अनुमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है।

धारा 170–बी (1) और (2) के प्रावधान कब लागू नहीं होते हैं ? अभिनिर्धारित किया गया, जब भूमि पंजीकृत विलेख द्वारा, कलेक्टर की सम्यक अनुमति उक्त प्रावधान के तहत लेने के बाद, अंतरित की जा चुकी है वहां ये प्रावधान लागू नहीं होते है। **209*** **386**

Sections 185 (1) (ii) (a), 190 (1) and 158 (2) – See Article 363 of the Constitution of India and section 31 of the Indore Land Revenue and Tenancy Act, 1931.

धाराएं 185(1)(ii)(ए), 190(1) और 158(2) – देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 363 एवं इन्दौर लैण्ड रेवेन्यू और टेनेन्सी अधिनियम, 1931 की धारा 31। **289*** **512**

Section 248 – Unauthorizedly taking possession of land – Whether the provision of section 248 are attracted in encroachment relating to land situated within the municipal area? Held, Yes. [Refer : ***State of M.P. & anr. v. Sind Mahajan Exchange Ltd. 1999 RN 329 (SC)***].

धारा 248 – अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेना – क्या धारा 248 के प्रावधान म्युनिसिपल क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में अतिक्रमण के बारे में आकर्षित होते है? अभिनिर्धारित किया गया हाँ – स्टेट ऑफ एम. पी. एण्ड अनादर विरूद्ध सिन्ध महाजन एक्सचेन्ज लिमिटेड, 1999 राजस्व निर्णय 329 (एससी), रेफर किया। **210** **387**

LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

Section 19 – Lok Adalat, constitution and status of.

(ii) Lok Adalat – Advantages and objects of

(iii) Reference of settled cases to Lok Adalat, necessity of.

धारा 19 – लोक अदालत, गठन और प्रास्थिति।

(ii) लोक अदालत – लाभ और उद्देश्य।

(iii) निराकृत प्रकरणों को लोक अदालत को रेफर करने की आवश्यकता। **40** **87**

LIMITATION ACT, 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 5 – Appeal, abatement of.

धारा 5 – अपील का उपशमन। **281** **496**

Section 5 – Condonation of delay in filing of appeal – Sufficient cause – How to examine?

धारा 5 — अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करना — पर्याप्त कारण — कैसे परीक्षित किया जाये?

211 **388**

Section 5 – When one of the legal representatives is already on record, the appeal does not abate – In such eventuality, appellant is neither required to apply for setting aside the abatement nor to file an application for condonation of delay under section 5 of the Limitation Act.

धारा 5 — जहाँ एक वैध प्रतिनिधि पहले से अभिलेख पर हो वहाँ अपील उपशमित नहीं होती है — ऐसे अवसर पर अपीलार्थी के लिए न तो उपशमन को अपास्त करवाना आवश्यक होता है न ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत विलंब क्षमा करवाने का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। **180*** **328**

Section 14 – See section 34 (2) of the Arbitration and Concilliation Act, 1996.

धारा 14 — देखें माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2)। **223** **417**

Section 27 and Articles 64 to 66 – Adverse possession – Declaration of title – Its non-permissibility of – Adverse possession can be used as a shield/defence – Further held, no relief for declaration of title can be granted to the plaintiff even if the plaintiff is found to be in adverse possession – Also held, such a person may be entitled to the relief of injunction to the effect that his possession cannot be disturbed except by due process of law.

धारा 27 और अनुच्छेद 64 से 66 — विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का अनुमत योग्य न होना — विरोधी आधिपत्य को ढाल/बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है — यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादी को उसका विरोधी आधिपत्य पाये जाने पर भी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता — यह भी अभिनिर्धारित किया गया, ऐसा व्यक्ति इस आशय की निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का हकदार हो सकता है कि उसके आधिपत्य को विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना डिस्टर्ब न किया जाये या छेड़ा न जाये। **57** **122**

Article 54 – Suit for specific performance of agreement for sale of immovable property – Period of limitation, commencement of.

अनुच्छेद 54 — अचल संपत्ति के विक्रय के करार के विनिर्दिष्ट पालन के वाद की परिसीमा का प्रारंभ।

176 (v) **316**

Article 54 – Suit for specific performance of contract, limitation therefor.

अनुच्छेद 54 — संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद की परिसीमा। **325(i)** **580**

Article 54 – See section 53-A of the Specific Relief Act, 1963.

अनुच्छेद 54 — देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 53–अ। **335*** **592**

Article 55 – Whether limitation for filing suit for recovery of balance amount would start from the date of sending recall notice for outstanding amount or when the assets of the company were sold and the balance amount payable was ascertained?

अनुच्छेद 55 – क्या अवशेष राशि की वसूली के वाद दायर करने के लिये परिसीमा बकाया राशि के लिये रिकाल नोटिस भेजने की तारीख से प्रारम्भ होगी या जब कंपनी की संपत्ति बेची गई और अवशेष राशि जो देय थी वह अभिनिश्चित की गई उस तारीख से प्रारम्भ होगी? **212** **389**

Articles 64 and 65 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908

अनुच्छेद 64 और 65 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11

225 **420**

M.B. LAND REVENUE AND TENANCY ACT, 1950

मध्य भारत लैण्ड रेवेन्यू और टेनेन्सी अधिनियम, 1950

Sections 54 (vii) and 54 (xviii) – See Article 363 of the Constitution of India and section 31 of the Indore Land Revenue and Tenancy Act, 1931.

धाराएं 54 (vii) और 54 (xviii) – देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 363 एवं इन्दौर लैण्ड रेवेन्यू और टेनेन्सी अधिनियम, 1931 की धारा 31। **289*** **512**

MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2006

खनिज (अवैध खनन, परिवहन और संग्रहण का संरक्षण) नियम, 2006

Rule 18 (4), Proviso – See sections 457 and 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.

नियम 18 (4), परंतुक – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 और 482। **82** **164**

MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957

माइन्स एवं मिनरल्स (डेपलपमेंट एडं रेग्युलेशन) अधिनियम, 1957

Section 4 (1-A), 21 and 22 – (i) Bar of section 22 of MMDR Act, 1957 against taking cognizance, when attracted?

(ii) When can police register and investigate a case relating to mines and minerals etc.?

(iii) Double jeopardy – Based on a maxim ***nemo debet bis vexari pro una et eadem cause***.

(iv) Theft and offence under the MMDR Act.

धारा 4 (1–ए), 21 और 22 – (i) धारा 22 एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की बाधा प्रसंज्ञान लेने के विरूद्ध कब आकर्षित होती है?

(ii) कब पुलिस खान और खनिज आदि के बारे में एक मामला पंजीबद्ध और अनुसंधान कर सकती है? जहाँ रेत और कंकड़ शासकीय भूमि से चोरी होती है, पुलिस एक प्रकरण पंजीबद्ध कर सकती है।

(iii) दोहरा जोखिम – एक विधि सूत्र नेमो डेविड वायस वेक्सारी प्रो यूनो इट ऐडम काज पर आधारित है – किसी भी व्यक्ति को एक ओर समान अपराध के लिए दो बार जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।

(iv) चोरी और एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अधीन अपराध। **36** **76**

MOTOR VEHICLES ACT, 1988

मोटरयान अधिनियम, 1988

Section 2(30) – Whether it is the duty of financier bank to renew the insurance policy of the vehicle from time to time, which was the subject matter of an agreement of hypothecation and also in possession of the owner?

धारा 2(30) – क्या यह वित्तदाता या फाइनेंसर बैंक का कर्त्तव्य है कि वाहन की बीमा पालिसी का समय – समय पर नवीनीकरण करावे, जो वाहन हायपोथिकेशन अनुबंध का विषय है और स्वामी के आधिपत्य में था?

255 **467**

Sections 2 (30), 50 (1) (a) (i) and 168 – Who is owner for the purpose of section 168 of M.V. Act, 1988?

धाराएं 2 (30), 50 (1) (ए) (प) और 168 – धारा 168 मोटरयान अधिनियम, 1988 के उद्देश्य से वाहन स्वामी कौन है? **100** **193**

Sections 2 (30) and 168 – (i) Who is the owner of a motor vehicle especially in case of hire-purchase agreement?

(ii) Who is liable to pay compensation where vehicle is subject to hire-purchase agreement?

धारा 2 (30) और 168 – (i) एक वाहन स्वामी कौन है विशेषतः हायर परचेस अनुबंध के मामले में?

(ii) जहां वाहन हायर परचेस अनुबंध के अधीन हो प्रतिकर के लिए कौन उत्तरदायी होता है?

101 **194**

Sections 41 (7) and 147 (1) – Insurance – What is the limitation of lifetime premium?

धाराएं 41 (7) और 147 (1) – बीमा – आजीवन प्रीमियम की परिसीमा क्या होती है?

42 **95**

Sections 140 and 166 – Interim award was passed under section 140 of the M.V. Act but not paid – Meanwhile, the claim application under section 166 of M.V. Act was withdrawn by the claimant – Whether interim award can be executed even after withdrawal or dismissal of application under section 166?

धाराएं 140 और 166 – धारा 140 मोटर यान अधिनयम के अधीन अंतरिम अवार्ड पारित किया गया किन्तु उसका भुगतान नहीं हुआ, इसी बीच दावा आवेदन धारा 166 मोटर यान अधिनियम आवेदक द्वारा वापस ले किया गया – क्या अंतरिम अवार्ड, धारा 166 के अधीन आवेदन वापस ले लेने या खारिज हो जाने के बाद भी निष्पादित करवाया जा सकता है ? **326*** **582**

Sections 147 and 149 – (i) Claimant was travelling in a transport vehicle along with his cattle after paying fare for cattle – Insurance company held, liable.

(ii) Want of valid D.L. – Burden of proof – It is upon the insurance company to prove.

धाराएं 147 और 149 – (i) दावेदार परिवहन यान में अपने मवेशी के साथ मवेशी का भाड़ा देने के बाद यात्रा कर रहा था – बीमा कंपनी का उत्तरदायी (प्रतिकर के लिए) होना अभिनिर्धारित किया गया।

(ii) चालन अनुज्ञप्ति का अभाव – प्रमाण भार – यह (प्रमाण भार) बीमा कंपनी पर है कि वह प्रमाणित करे कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। **213** **391**

Sections 147, 149 (2) and 170 – (i) Whether insurance company is entitled to challenge the award on the ground of non-involvement of the alleged vehicle in motor accident or it is entitled to challenge the award only on the ground of breach of policy as provided under sections 147 and 149(2) of M.V. Act,1988?

(ii) Appreciation of evidence in motor accident cases – No vehicle number mentioned in F.I.R – It was about an unknown vehicle – Alleged vehicle sized after six month of the accident by I.O. – I.O. was not examined by claimant – Presence of eye witnesses also doubtful – Natural witnesses were not examined by claimant – involvement of the alleged vehicle in motor accident held, not proved.

धाराएं 147, 149 (2) और 170 – (i) क्या बीमा कंपनी अवार्ड को वाहन के दुर्घटना में लिप्त न होने के आधार पर चुनौती दे सकती है या वह इसे केवल बीमा पालिसी के भंग के आधार पर ही धारा 147 और 149 (2) मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ही चुनौती दे सकती है ?

(ii) मोटर दुर्घटना मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन – प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वाहन का कोई नम्बर दर्ज नहीं था – वह एक अज्ञात वाहन के बारे में थी – अभिकथित वाहन अन्वेषण अधिकारी द्वारा दुर्घटना के 6 माह के बाद जप्त किया गया – अन्वेषण अधिकारी का आवेदक ने कथन नहीं करवाया – प्रत्यक्ष साक्षीगण की उपस्थिति भी संदेहास्पद थी – प्राकृतिक गवाहों को आवेदक द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया – अभिकथित वाहन का दुर्घटना में शामिल होना प्रमाणित नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया। **43** **96**

Section 147 (1) – Cheque of premium against insurance policy dishonoured – Legal position of liability of insurance company – Explained.

धारा 147 (1) – बीमा पॉलिसी की प्रीमियम का चैक अनादरित हुए – बीमा कंपनी के दायित्व के बारे में विधिक स्थिति। **44** **99**

Section 147 (1) – Whether insurance company is liable to satisfy the award in case of pillion rider or gratuitous passenger travelling in four-wheeler or goods vehicle? He would be a third party within the meaning of section 147 of the Act? Legal position explained.

धारा 147 (1) – क्या बीमा कंपनी पीलियन राइडर (दोपहिया वाहन में पीछे बैठा व्यक्ति) या चार पहिया वाहन के अनुग्रह यात्री या मालवाहक वाहन के अनुग्रह यात्री के प्रतिकर के लिए उत्तरदायी होती है? क्या ऐसा व्यक्ति धारा 147 अधिनियम के अर्थों में एक तृतीय पक्ष होता है? विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी।

45 **101**

Sections 147 (1) and 149 (2) – (i) Direction of pay and recover, when can be given?

(ii) Order of pay and recover, when cannot be given?

(iii) Liability to pay compensation to persons, travelling in trolley attached to tractor.

धाराएं 147 (1) और 149 (2) – (i) भुगतान करे और वसूले के निर्देश कब दिये जा सकते है?

(ii) भुगतान करे और वसूले करके के निर्देश कब नहीं दिये जा सकते है?

(iii) व्यक्ति जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ी गयी ट्राली में यात्रा कर रहे हो उनके प्रतिकर का दायित्व।

46 **102**

Section 149 – Insurer, liability of.

Accident took place at 11.00 o'clock while premium for insurance deposited at 3.10 o'clock.

धारा 149 – बीमाकर्त्ता का दायित्व।

दुर्घटना 11 बजे हुई जबकि बीमा की किश्त 3.10 बजे जमा की गई । **327*** **582**

Section 149 – Insurer, liability of.

Tractor being insured for agricultural purposes, was being used for transporting sand.

धारा 149 – बीमाकर्त्ता का दायित्व।

ट्रैक्टर कृषि उद्देश्य के लिए बीमित था – रेत के परिवहन के लिए उपयोग किया गया।

328* **583**

Section 149 (2)(a)(ii) – Liability of insurance company – Driving licence – When a person possess driving licence to drive light motor vehicle, can he be entitled to drive light goods vehicle? Held, Yes – It may not amount to breach of insurance policy.

धारा 149 (2)(a)(ii) – बीमा कंपनी का दायित्व – चालन अनुज्ञप्ति – जब एक व्यक्ति के पास हल्के मोटर यान चलाने की चालन अनुज्ञप्ति हो, क्या वह हल्के माल वाहक चलाने के लिये अधिकृत हो सकता है ? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ – यह बीमा पालिसी का उल्लंघन भी नहीं है।

47 **104**

Section 149 (2) (a) (ii) – Liability of insurance company where vehicle has been driven at the time of accident by minor, having no driving licence.

धारा 149 (2)(a)(ii) – जहाँ वाहन दुर्घटना के समय अवयस्क द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी वहाँ बीमा कंपनी का दायित्व। **48** **106**

Section 163-A – If claimant himself was found negligent, he is not entitled to claim compensation on the principle of no fault liability under section 163-A of M.V. Act.

धारा 163–ए – यदि दावेदार स्वयं उपेक्षावान पाया गया था तब वह धारा 163–ए मोटर यान अधिनियम के अधीन त्रुटि के बिना दायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होता है।

214 **392**

Section 166 – Assessment of compensation in death case.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण। **329*** **583**

Section 166 – Assessment of compensation in death case – Deceased aged 32, was working in an Indian restaurant in Germany.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण – मृतक 32 वर्ष उम्र का जर्मनी में भारतीय रेस्टोरेंट में कार्य करता था। **256** **469**

Section 166 – Assessment of compensation in death cases – Income of house wife, assessment of.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरणों में प्रतिकर का निर्धारण – गृह स्वामिनी या हाउस वाईफ की आय।

102 **195**

Section 166 – Assessment of compensation in injury case.

धारा 166 – चोट के प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण। **257** **470**

Section 166 – Assessment of compensation in injury cases – Claimant suffered head injury.

धारा 166 – चोटों के मामलों में प्रतिकर का निर्धारण – दावेदार को सिर में चोटें आयी।

49 **106**

Section 166 – Contributory negligence – Collusion between truck and two-wheeler.

धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – दोपहिया वाहन और ट्रक के बीच टककर। **50** **107**

Section 166 – (i) Contributory negligence – Tractor and motor cycle collided in the middle of the road.

(ii) Assessment of compensation in injury cases – Income of agriculturist, who has 30 bighas irrigated land, must be at least Rs. 5000 p.m.

धारा 166 – (i) योगदायी उपेक्षा – सड़क के मध्य ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल टकराये।

(ii) चोटों के प्रकरणों में प्रतिकर का निर्धारण – कृषक की आय जिसके पास 30 बीघा सिंचित जमीन है कम से कम 5000 प्रतिमाह होना चाहिए। **51** **108**

Section 166 – Whether deduction of ex gratia payment from compensation is permissible? Held, No.

धारा 166 – क्या प्रतिकर में से एक्सग्रेसिया का भुगतान कम किया जाना (अर्थात काटा जाना) अनुमत है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **103** **196**

Sections 166 and 168 – Assessment of compensation in death case – Choice of multiplier – Deceased was a bachelor – Claimants are the parents.

धाराएं 166 और 168 – मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – गुणक का चयन – मृतक अविवाहित था – दावेदार माता पिता हैं। **258** **470**

Sections 166 and 168 – (i) Assessment of compensation in death case – Choice of multiplier – Deceased was bachelor – Claimants are parents.

(ii) Assessment of compensation in death case – Personal expenses of a bachelor deceased – Claimants are parents.

धाराएं 166 और 168 – (i) मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – गुणक का चयन – मृतक अविवाहित था – दावेदार माता पिता हैं।

(ii) मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – अविवाहित मृतक का व्यक्तिगत निर्वाह खर्च – दावेदार माता पिता हैं। **215** **394**

Sections 166 and 168 – Assessment of compensation in injury case.

धाराएं 166 और 168 – चोट के प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण। **216** **396**

Sections 166 and 168 – Composite negligence – Liability of joint tortfeasors – Whether a claimant can recover entire compensation from one of the joint tortfeasors particularly, when the composite negligence of drivers of both trailer-truck and bus is in the ratio of 2/3rd and 1/3rd respectively?

धाराएं 166 और 168 – सम्मिश्र उपेक्षा – संयुक्त दोषकर्त्ताओं का दायित्व – क्या एक दावेदार पूरा प्रतिकर संयुक्त दोषकर्त्ताओं में से किसी एक दोषकर्त्ता से वसूल कर सकता है विशेषकर जहाँ दुर्घटना में ट्रेलर ट्रक व बस के चालकों की सम्मिश्र उपेक्षा 2/3 और 1/3 की सीमा तक पाई गई है? **259** **472**

Section 168 – (i) Assessment of compensation in death case – Future prospects for bank manager aged 27 years – 50 % of annual income to be added under the head of future prospects.

(ii) Assessment of compensation in death case – Claimants are parents – What is the appropriate multiplier?

(iii) Rs. 25,000 was awarded as funeral expenses according to the principles laid down by the Apex Court in ***Rajesh v. Rajbir Singh, 2013 ACJ 1403***.

धारा 168 – (i) मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण – 27 वर्षीय बैंक मैनेजर के लिए भविष्य की संभावनाएँ – वार्षिक आय का 50 प्रतिशत भविष्य की संभावना के शीर्ष में जोड़ा जाये।

(ii) मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – आवेदकगण माता–पिता – उचित गुणांक क्या है।

(iii) दाह संस्कार खर्च 25000/– रूपये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत राजेश विरूद्ध राजबीर सिंह, 2013 ए.सी.जे. 1403 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अवार्ड किये गये।

104 **197**

MOTOR VEHICLES RULES, 1989 (CENTRAL)

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989

Rule 55 – See sections 2(30), 50(1)(a)(i) and 168 of the Motor Vehicle Act, 1988.

नियम 55 – देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं 2(30), 50(1)(ए)(प) और 168।

100 **193**

MUSLIM LAW

मुस्लिम विधि

(i) Divorce (Khula), meaning of.

(ii) Khula, when can be effected?

(iii) Application u/s 12 of Protection of Women from Domestic Violence Act by divorced Muslim wife, maintainability of.

(i) तलाक (खुला) का अर्थ।

(ii) खुला, कब प्रभावशील किया जा सकता है?

(iii) तलाक शुदा पत्नी द्वारा धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के आवेदन की प्रचलनशीलता। **165** **300**

– Gift – Distinction in Muslim Law between the corpus and the usufruct i.e. the thing itself and the use of thing.

– दान – मुस्लिम विधि में कारपस या वस्तु और भोगाधिकार अर्थात् वस्तु स्वयं और वस्तु के उपयोग के अधिकार में अन्तर। **41** **94**

Prompt Dower – Suit for declaration and permanent injunction filed by plaintiff/wife against defendant/husband alleging that the suit plot was given to the plaintiff on account of Prompt Dower by the defendant.

मेहर–ए–मुसज्जल – वादी /पत्नी द्वारा प्रतिवादी/पति के विरूद्ध घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पेश किया गया – यह अभिवचन किया गया कि वादग्रस्त प्लाट वादी को प्रतिवादी द्वारा मेहर–ए–मुसज्जल के कारण दिया गया। **105** **199**

– Status of Shariat courts and legal sanctity of Fatwas issued by such bodies and subjects on which Fatwas can be issued.

(i) Dar-ul-Qazas and Nizam-e-Qaza are neither created nor sanctioned by any law made by competent legislature – Not part of the ***corpus juris*** of State – They are not illegal by itself but are informal justice delivery system with an objective of bringing about amicable settlement between the parties.

(ii) Fatwas issued by such bodies have no legal sanctity and cannot be enforced by any legal process – Practice of issuing Fatwas – Not by itself illegal – But as fatwas have religious strength issuance of Fatwa on rights, status and obligation of individual Muslim at behest of rank outsider would not be permissible.

– शरियत न्यायालयों की स्थिति और उनके द्वारा जारी फतवों की विधिक पवित्रता और विषय जिन पर फतवें जारी किये जा सकते हैं।

(i) दार–उल–कज़ास और निजाम–ए–काजा सक्षम विधायिका द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा न तो सृजित और न ही अनुमत है – ये राज्य के विधि शास्त्र का भाग नहीं है – ये अपने आप में अवैध नहीं है बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौते के उद्देश्य से एक अनौपचारिक न्याय दान प्रणाली है।

(ii) ऐसी निकायों द्वारा जारी फतवें की कोई विधिक पवित्रता नहीं है और इन्हें विधिक प्रक्रिया से लागू नहीं करवाया जा सकता – फतवें जारी करने की प्रथा – अपने आप में अवैध नहीं है – किन्तु फतवों में धार्मिक बल होता है किसी मुस्लिम के अधिकारों, स्थिति और दायित्वों के बारें में जारी फतवा उसके लिए एक आदेश होता है किन्तु बाहरी लोगों के लिए (अर्थात् मुस्लिम के अलावा अन्य लोगों के लिए) यह अनुमत नहीं होगा। **5** **13**

N.D.P.S. ACT, 1985

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Sections 8 and 20 – See sections 12, 52 and 53 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

धाराएं 8 और 20 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराएं 12, 52 और 53। **161** **293**

Section 8/18 – See sections 91and 92 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 8/18 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 91 और 92। **241** **444**

Sections 15, 35, 50 and 54 – Conscious possession – How to be judged? Search and seizure from truck – Section 50 of the Act is not applicable.

Witnesses have identified the accused in the torch light – They had also seen them running away – Nothing has been elicited in their cross-examination to discern the testimony of witnesses – Non-holding of T.I. parade held, insignificant.

धाराएं 15, 35, 50 और 54 – जागृत अधिपत्य – कैसे निर्णित किया जावे ?

ट्रक से तलाशी और जप्ती – आधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है।

गवाहों ने अभियुक्त को टार्च की रोशनी में पहचाना था – उन्होंने उन्हें (अभियुक्तगण को) भागते हुए भी देखा था – गवाहों के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं लाया गया था, जिससे उनके कथन पर अविश्वास किया जाए – पहचान परेड का संचालन न करवाना महत्वहीन माना गया। **260** **473**

Sections 18, 42, 43 and 52-A – Search made in a public place i.e. beneath a bridge of a public road, so the question of compliance of section 42 (1) & (2) does not arise.

Delay in sending seized articles for chemical examination.

धाराएं 18, 42, 43 और 52–ए – तलाशी लोक स्थान अर्थात पुलिया के नीचे एक आम सड़क पर की गई, धारा 42(1) और (2) के अनुपालन का प्रश्न उत्पन्न नही होता है।

बरामद सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण के लिये भेजने में देरी। **261 (ii) & (iii)** **476**

Sections 20 and 52 – See section 3 of the N.D.P.S. Act, 1985

धाराएं 20 और 52 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 **304** **541**

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Section 20 – Issuance of blank/partly filled cheque, effect of.

धारा 20 – कोरा/आंशिक रूप से भरा हुआ चैक जारी करने का प्रभाव। **166** **304**

Section 138 – Non-signatory of the cheque was made an accused in a complaint under section 138 of the N.I. Act.

धारा 138 – धारा 138 एन.आई. एक्ट के परिवाद में चैक पर हस्ताक्षर न करने वाले को एक अभियुक्त बनाया गया। **262*** **478**

Section 138 – (i) Offence by Company, liability of – Directors of the Company as well as every person who was in charge of and was responsible to company for conduct of its business at the time of commission of its offence shall be liable.

(ii) Averment in complaint, necessity of – Mere assertion that accused persons were the Directors of the company will not suffice to make them liable – Court must see whether

they (Directors) were incharge and responsible for conduct of business of Company or not.

धारा 138 — (i) कम्पनी द्वारा अपराध, दायित्व — कम्पनी के संचालक और प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के कार्य का प्रभारी और कम्पनी के व्यापार संबंधी कृत्यों के लिए अपराध किये जाते समय उत्तरदायी हो वे दायी होगें।

(ii) परिवाद में अभिवचन की आवश्यकता — केवल इतना अभिकथन कि अभियुक्तगण संचालक थे उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है — न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या वे (संचालक) कम्पनी के व्यापार संबंधी कृत्यों के लिए उत्तरदायी थे या नहीं। **52*** **111**

Section 138 – Offence under section 138, liability of – Law explained.

धारा 138 — धारा 138 के अधीन अपराध का दायित्व — विधि समझाई गई।

167* **305**

Section 138 – See section 394 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 138 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 394। **263** **478**

Section 138 – See section 427 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 138 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427। **137** **238**

Section 138 – Territorial jurisdiction for complaint under section 138 N.I. Act.

धारा 138 — धारा 138 एन.आई. एक्ट के परिवाद के लिये प्रादेशिक क्षेत्राधिकार।

106 **200**

Section 138 – Though "stop payment" instructions have been given by drawer to the bank, offence punishable under section 138 N.I. Act is made out – Complainant had failed to discharge his obligations as per agreement by not repairing/replacing the damaged USP system or contents of the reply sent by the accused were not disclosed in the complaint – These facts are matter of evidence.

धारा 138 — यद्यपि ''भुगतान रोके'' या स्टाप पेमेन्ट के निर्देश बैंक को चैक जारी करने वाले ने दिये थे, धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध बनता है — परिवादी अनुबंध के अधीन क्षतिग्रस्त यूएसपी सिस्टम को सुधारने/रिप्लेस करने में असफल रहा या उसने अभियुक्त के जवाब के तथ्यों को परिवाद में प्रगट नहीं किया — ये तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं।

107 **201**

Section 138 (b) – Constructive service of demand notice – What it may amount to?

धारा 138 (बी) — मांग सूचनापत्र की आन्वयिक तामील — किसके समान है?

264 **479**

Sections 138 and 139 – Neither cheque nor signature of accused has been disputed by the defence – Presumption u/s 139 of N.I. Act would operate.

धाराएं 138 और 139 — न तो चेक न उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर को बचाव द्वारा विवादित किया गया है – धारा 139 एन.आई.एक्ट की उपधारणा लागू होगी। **265** **480**

Sections 138 and 141 – Company was not made an accused and even demand notice was also not sent to it – But accused, in his personal capacity, had drawn the cheque, on a bank account maintained by him for paying the payee – Appeal against acquittal allowed.

धाराएं 138 और 141 — कंपनी को एक अभियुक्त नहीं बनाया गया, यहां तक की उसे मांग सूचना पत्र भी नहीं भेजा गया – किन्तु अभियुक्त ने उसके द्वारा पोषित बैंक खाते से, व्यक्तिगत हैसियत में, चैक जारी किया जो कि पाने वाले को भुगतान के लिये था। दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील स्वीकार की। **266** **481**

Sections 138 and 141 – Taking cognizance against Director of a Company by Magistrate.

धाराएं 138 और 141 — मजिस्ट्रेट द्वारा एक कंपनी के संचालक के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेना।

267 **482**

Sections 138 and 141 – Vicarious liability of Director of Company – Dishonoured cheques were issued by virtue of Letter of Guarantee as per complainant – Letter of Guarantee gives way to civil liability – Complainant can always pursue the remedy before appropriate Court – Such dishonour of cheques would not make alleged Director of Company liable under section 138 of the N.I. Act.

धाराएं 138 और 141 — कंपनी के साथ उसके संचालक का संयुक्त दायित्व। (ii) परिवादी के अनुसार अनादरित चैक लेटर ऑफ ग्यारन्टी की वजह से जारी किये गये थे – लेटर ऑफ ग्यारन्टी सिविल दायित्व प्रदान करती है – परिवादी उचित न्यायालय के समक्ष उपचार ले सकता है – ऐसे अनादरित चैक कंपनी के संचालक को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधीन दायी नहीं बनाते है। **108(i)** **202**

Sections 138 and 141 – Whether notice under section 138(b) of the N.I. Act is mandatorily required to be sent to the Directors of a Company before a complaint could be filed against such Directors along with the Company?

धाराएं 138 और 141 — क्या धारा 138 (बी) एन.आई. एक्ट का सूचनापत्र कंपनी के संचालकों को, कंपनी के साथ उनके विरूद्ध परिवाद पेश करने के पूर्व भेजना, आज्ञापक रूप से आवश्यक होता है।

268 **483**

Sections 138 and 142 – Cheque was issued by the accused on bank situated at Karnataka – Same was presented for collection by complainant in bank situated at Kerala – Dishonoured due to insufficiency of funds – Complaint under section 138 N.I. Act filed in the court situated at Kerala – Returned by the Magistrate for presentation

before proper court at Karnataka – Held, presentation of cheque by complainant at a place of his choice or issuance of demand notice from a particular place, not confer jurisdiction upon the courts situated at that places – ***Dashrath Rupsingh Rathod's case, AIR 2014 SC 3519*** followed.

धाराएं 138 और 142 – अभियुक्त ने कर्नाटक स्थित एक बैंक का चैक जारी किया – परिवादी ने वह चैक संग्रहण या कलेक्शन के लिये केरल स्थित बैंक में पेश किया – चैक अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित किया गया – धारा 138 एन.आई. एक्ट का परिवाद केरल स्थित न्यायालय में पेश किया गया – मजिस्ट्रेट ने परिवाद कर्नाटक के उचित न्यायालय में पेश करने के लिये लौटा दिया – अभिनिर्धारित किया गया, परिवादी द्वारा उसके पसंद के स्थान पर चैक पेश कर देने या मांग सूचना पत्र किसी स्थान विशेष से दिलवा देना उन स्थानों पर स्थित न्यायालयों को कोई क्षेत्राधिकार (प्रादेशिक) प्रदान नहीं करता है न्यायदृष्टांत दशरथ रूप सिंह राठौर, ए.आई.आर. 2014 एस.सी. 3519 के मामले का अनुसरण किया गया। **168* 306**

Sections 138 and 142 – Whether provisions of section 5 of the Limitation Act are applicable to the complaint made under section 138 of the N.I. Act?

What is the proper stage for filing an application for condonation of delay as per proviso to section 142 (b) of the N.I. Act ?

धाराएं 138 और 142 – क्या धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधीन परिवाद में लागू होते है ?

धारा 142 (बी) एन. आई. एक्ट के परंतुक के अनुसार विलंब क्षमा करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने का उचित प्रक्रम क्या है ? **269 484**

Sections 138, 142 and 145 – (i) Can complaint be filed by a power-of-attorney holder? Held, Yes.

(ii) If power-of-attorney holder possess personal knowledge of the transactions, he can depose and verify the contents of the complaint.

(iii) Where the complainant herself has come in the witness box, no need to examine power-of-attorney holder as a witness.

धाराएं 138, 142 और 145 – (i) क्या परिवाद मुखतियार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ? अभिनिर्धारित, हाँ।

(ii) यदि मुखतियार नामा धारक को संव्यवहार का व्यक्तिगत ज्ञान हो तो वह कथन दे सकता है और परिवाद की अंतरवस्तु को सत्यापित कर सकता है।

(iii) जहां परिवादी स्वयं साक्ष्य कक्ष में आ गई हो – वहां मुखतियार नामा धारक को साक्षी के रूप में परिक्षित करवाना आवश्यक नहीं था। **109 203**

Sections 138 and 143 to 147 – Offence under section 138 of the Act of 1881, procedure for trial of – Law explained.

धाराएं 138 और 143 से 147 – धारा 138, अधिनियम, 1881 के अपराध के विचारण के लिए प्रक्रिया के बारे में विधि समझाई गई। **217(ii) 397**

Sections 138 and 147 – (a) Compounding of offences under section 147 of the Negotiable Instruments Act, how to proceed with? Guidelines given in ***Damodar S. Prabhu v. Sayyad Baba Lal, (2010) 5 SCC 663,*** objectives of.

(b) Guidelines contained in ***Damodar S. Prabhu*** (supra) – Whether can be dispensed with when a case is decided in Lok Adalat? Held, No.

धाराएं 138 और 147 – (a) धारा 147 एन.आई.एक्ट. के तहत अपराध में समझौता, कैसे कार्यवाही की जाये – न्यायदृष्टांत दामोदर एस. प्रभु विरूद्ध सैयद बाबालाल, (2010)5 एस.सी.सी. 663 में दिये गये दिशा निर्देश के उद्देश्य।

(b) दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में दिये गये दिशा निर्देश – क्या जहां मामला लोक अदालत में निराकृत होता है वहां उनसे (खर्च या कास्ट के बारे में दिये गये दिशा निर्देश से) मुक्ति दी जा सकती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **40 87**

Sections 138 (c) and 142 (b) – (i) Premature complaint – Offence punishable under section 138 of the Negotiable Instruments Act, cognizance of.

Can cognizance of offence punishable under section 138 of the Negotiable Instruments Act be taken on the basis of a complaint filed before the expiry of 15 days referred to in clause (c) of the proviso to section 138 of the N.I. Act? Held, No.

(ii) Can the complainant be permitted to present the complaint again notwithstanding the fact that the period of one month stipulated under section 142 (b) for filing of such complaint has expired? Held, No.

धाराएं 138 (सी) और 142 (बी) – (i) अपरिपक्व परिवाद – धारा 138 एन.आई. एक्ट. के अपराध का संज्ञान लिया जाना क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट. के अपराध का संज्ञान उस परिवाद के आधार पर लिया जा सकता है जो धारा 138 (सी) एन.आई. एक्ट. के परन्तुक में उल्लेखित 15 दिन की अवधि व्यतीत होने के पहले प्रस्तुत किया गया हो ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) क्या परिवादी को धारा 142 (बी) एन.आई.एक्ट. में उल्लेखित एक माह की अवधि निकल जाने के बाद पुनः वही परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमत किया जा सकता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

53 112

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

Sections 3 and 4 – Issuance of search warrant by the Special Judge appointed under P.C. Act,1988 – Whether by invoking jurisdiction under section 93 (1) Cr.P.C. search warrant can be issued by the Court competent on the request of Investigating Agency?

धाराएं 3 और 4 – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा तलाशी वारण्ट जारी किया जाना – क्या धारा 93(1) दं.प्र.सं. के अधीन क्षेत्राधिकार प्रयोग करके सक्षम न्यायालय द्वारा, अनुसंधान एजेन्सी के निवेदन पर, तलाशी वारण्ट जारी किया जा सकता है?

232 **427**

Sections 5 and 13 (1) (d) – Offences under Prevention of Corruption Act, 1988 – Power of Special Judge for taking cognizance, scope of.

धाराएं 5 और 13 (1) (डी) – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध – विशेष न्यायाधीश की प्रसंज्ञान लेने की शक्तियों का विस्तार। **169** **307**

Sections 7 and 13 – Twin requirements are ***sine qua non*** for proving the offence under section 7 of the Act of 1988 – Firstly, the demand and secondly, the voluntary acceptance of illegal gratification – If these are proved by evidence, then conviction must follow under section 7 of the Act of 1988.

धाराएं 7 और 13 – धारा 7 अधिनियम, 1988 के अपराध को प्रमाणित करने के लिये 2 अनिवार्यतायें आवश्यक होती है – पहली अवैध परितोषण की मांग, दूसरी उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना – यदि साक्ष्य से ये दो तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं तो धारा 7 अधिनियम, 1988 के तहत् दोषसिद्धि होना चाहिये।

170 **309**

Sections 7, 13 (1)(d) r/w 13(2) – Almost all the facts alleged by the prosecution are admitted by the accused in his examination under section 313 of Cr.P.C. – He has taken the defence that the amount was received by him on account of repayment of loan which was given to the complainant by him prior to the date of incident – Defence version was not found acceptable by the trial court as well as by Hon'ble the High Court.

धाराएं 7, 13(1)(क) और सहपठित धारा 13(2) – अभियुक्त ने अभियोजन द्वारा अभिकथित लगभग सभी तथ्यों को उसके परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. में स्वीकार कर लिया – उसने यह बचाव लिया कि उसने जो राशि प्राप्त की है वह ऋण के भुगतान के लिए है जो ऋण परिवादी को घटना दिनांक के पूर्व उसने दिया था – बचाव अभिकथन को विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया।

270* **486**

Sections 7 and 13(1)(d) r/w/s 13(2) – (i) Mutation work – Illegal gratification – Incompetency of the accused, non-effect of.

(ii) Demand and acceptance of illegal gratification – Is ***sine qua non*** – Law reiterated.

(iii) Evidence of Police Officer, appreciation of – Police Officer cannot be disbelieved merely on the basis that he is a Police Officer.

धाराएं 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) – (i) नामांतरण का कार्य – अवैध परितोषण – अभियुक्त के अक्षम (उक्त कार्य करने में) होने का प्रभाव न होना।

(ii) अवैध परितोषण की मांग और उसे स्वीकार किया जाना – एक अनिवार्य शर्त है – विधि पुनः बतलाई गई।

(iii) पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का मूल्यांकन – पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर उसके पुलिस अधिकारी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। **110** **206**

Sections 7, 13(1)(d) and 13(2) – When alleged previous enmity becomes immaterial in corruption cases?

When demand, acceptance and recovery of tainted money from possession of accused have been proved – No preliminary inquiry could be done due to paucity of time – Plea of defence is not found reliable – Presumption under Section 20 of the Act stands unrebutted.

धाराएं 7, 13(1)(डी) और 13(2) – कब अभिकथित पूर्व रंजिश भ्रष्टाचार के मामले में अतात्विक हो जाती है ?

जब माँग, स्वीकारोक्ती और दूषित धन का अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद होना प्रमाणित हो जाता है। समय की कमी के कारण कोई प्रारंभिक जाँच नहीं की जा सकी हो। बचाव का अभिवाक स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। धारा 20 अधिनियम की उपधारणा अखंडित रहती है। **271** **487**

Sections 7, 13 (1)(d) r/w/s 13(2) and 20 – Appreciation of evidence – Statement of key witness PW 9 was recorded almost after three years of incident – Cross-examination was not done on the same day – In his cross-examination, he admitted that the amount was not demanded by him.

धाराएं 7, 13 (1)(क) सहपठित धारा 13(2) और 20 – साक्ष्य का मूल्यांकन – मुख्य गवाह, अभियोजन साक्षी क्रमांक 9 का बयान घटना के लगभग तीन वर्ष बाद अभिलिखित किया गया था – उसी दिन उसका प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया था – उसने प्रतिपरीक्षण में कहा कि अभियुक्त द्वारा धनराशि की मांग नहीं की गई थी। **272*** **488**

Sections 7, 13(1)(d) r/w/s 13(2) and 20 – The tainted money was recovered from the possession of the accused – Immediate written explanation offered by him was that the alleged money was thrust into his pocket – During trial he did not stand by his earlier version and remained silent – Where the accused has not given any explanation that under what circumstances tainted money was found in his possession, presumption under section 20 of the Act,1988 is not rebutted – Held, High Court rightly reversed the acquittal.

धाराएं 7, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) और 20 – दूषित धन अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद हुआ – अभियुक्त द्वारा तत्काल दिया गया लिखित स्पष्टीकरण यह था कि धन उसकी जेब में डाला गया था – विचारण के दौरान वह उसके पूर्व कथन पर कायम नहीं रहा और मौन रहा – जहां अभियुक्त यह स्पष्टीकरण नहीं देता है कि किन परिस्थितियों में दूषित धन उसके आधिपत्य में पाया गया धारा 20 अधिनियम 1988 के अधीन उपधारणा खण्डित नहीं होती है – अभिनिर्धारित किया गया, उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को सही रूप से उल्टा है। **273** **489**

Sections 7, 13 (2) and 20 – Demand and acceptance of illegal gratification, proof of.

धाराएं 7, 13 (2) और 20 — अवैध परितोषण की मांग और स्वीकारोक्ति का प्रमाण।

330 **584**

Sections 13(1)(d) and 19 – See section 197 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 13 (1) (डी) और 19 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197।

331* **586**

Sections 13 (1)(c), (d) and 15 – For framing of charge under section 15 of PC Act against an accused, whether it is necessary that he must also be charged either under section 13 (1)(c) or 13 (1)(d) of the PC Act ? Held, No.

धाराएं 13(1)(सी), (डी) और 15 — क्या एक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोप विरचित करने के लिये यह आवश्यक है की उस पर या तो धारा 13 (1)(सी) या धारा 13 (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप होना चाहिये? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **111** **208**

Section 13 (1)(e) r/w/s 13 (2) – What is the meaning of "known sources of income"?

धारा 13 (1) (ई) सहपठित धारा 13 (2) — ''आय के ज्ञात स्त्रोत'' का अर्थ क्या है ?

274 **489**

Section 19 – Sanction for prosecution under section 19 of the Act.

धारा 19 — धारा 19 अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए स्वीकृति। **332** **586**

Sections 19 and 20 – (i) Where it is proved that the amount was recovered from the possession of the accused, the burden of proof lies on him to prove that he received the same bona fidely or for some other purpose.

(ii) Mere error, omission or irregularity in sanction for prosecution is not considered fatal for the prosecution unless it has resulted in failure of justice.

धाराएं 19 और 20 — (i) जहाँ यह प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त के आधिपत्य से राशि बरामद हुई, अभियुक्त पर यह प्रमाण भार होता है कि वह यह प्रमाणित करे कि उसने राशि सद्भावना पूर्वक ली है या किसी अन्य उद्देश्य से ली है।

(ii) अभियोजन चलाने की अनुमति में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता अभियेाजन के लिए घातक नहीं होती है जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की हानि न हुई हो। **218*** **404**

PROPERTY LAW :

संपत्ति विधि :

– See Division of Property of Christians.

देखें ईसाईयों में संपत्ति का विभाजन। **140** **245**

– See Sections 7, 8, 58, 60, 62, 72, 76 (a), and 111(c) of the Transfer of Property Act, 1882

देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 7, 8, 58, 60, 62, 72, 76 (ए) और 111 (सी)

219 **405**

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

Sections 6 and 17 – See sections 164 and 439 of the Criminal Procedure Code, 1973

धाराएं 6 और 17 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 और 439

95* **185**

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1994

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1994

Section 12 – Jurisdiction of Human Rights Commission – It does not have any jurisdiction to deal with disputed questions of title and possession of the property.

धारा 12 – मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार – आयोग को संपत्ति के स्वत्व और आधिपत्य के विवादित प्रश्नों को निपटाने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। **112*** **208**

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

Sections 3 and 12 – Application under section 12 of the Act of 2005 has been filed by the wife in the year 2007 – Couple has started living separately since 1992 – Whether such application is maintainable?

धाराएं 3 और 12 – पत्नी द्वारा वर्ष 2007 में धारा 12 अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था – पति–पत्नि ने वर्ष 1992 में पृथक रहना शुरू किया था – क्या ऐसा आवेदन चलने योग्य है? **333*** **589**

REGISTRATION ACT, 1908

पंजीकरण अधिनियम, 1908

Sections 17(1) (a) and 17(2)(vi) – Consent decree passed by the court for disputed property – In subsequent suit it was found that some property was joint Hindu family property and some was self-acquired – Property related to joint Hindu family did not require compulsory registration in view of section 17 (2) (vi) of the Registration Act –

Property which was self-acquired and gifted did require compulsory registration in view of section 17 (1) (a) of Registration Act.

धाराएं 17(1)(a) और धारा 17 (2)(vi) – विवादग्रस्त संपत्ति के लिये न्यायालय द्वारा सहमति अज्ञाप्ति या कंसेन्ट डिक्री पारित की गई – पश्चातवर्ती वाद में यह पाया गया कुछ संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है और कुछ स्वअर्जित संपत्ति है – संपत्ति जो संयुक्त हिन्दू परिवार से संबंधित है उसके लिये अनिवार्य पंजीकरण धारा 17(2)(vi) पंजीकरण अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं है – संपत्ति जो स्व–अर्जित हो और दान की गई हो उसके बारे में धारा 17(1)(a) पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।

113 **209**

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

Section 24(2) – (i) Nature of second proviso of section 24 (2) (as inserted vide Amendment Ordinance of 2014 w.e.f. 01.01.2015 – It is prospective in operation.

(ii) Interpretation of Statutes – Fresh legislation, whether prospective or retrospective?

(iii) Award was passed on 06.08.2007 under the old Act of 1894 – Neither physical possession taken nor compensation paid – More than five years have already passed – Land acquisition proceedings are deemed to have lapsed in terms of section 24 (2) of the Act of 2013.

धारा 24 (2) – (i) धारा 24 (2) के द्वितीय परंतुक की प्रकृति (जिसे संशोधन अध्यादेश 2014 दिनांक 01.01. 2015 से प्रभावशील द्वारा जोड़ा गया है) – यह भविष्यलक्षी लागू होता है।

(ii) विधि का अर्थान्वयन – एक नवीन विधान – भूतलक्षी या भविष्यलक्षी कैसा होगा।

(iii) अवार्ड भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत् दिनांक 06.08.2007 को पारित किया गया – न तो भूमि का भौतिक आधिपत्य लिया गया था न ही प्रतिकर भुगतान किया गया था – 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था – भूमि अधिग्रहण कार्यवाही धारा 24 (2) अधिनियम, 2013 के अर्थो में समाप्त या लेप्स हो जाना मानी जायेगी।

171 **310**

Section 24 (2) – See sections 4, 6 and 11 of the Land Acquisition Act, 1894.

धारा 24 (2) – देखें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4, 6 और 11।

163 **296**

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

Section 2(j) – See section 65 (f) of the Evidence Act, 1872

धारा 2 (जे) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 (एफ)। **201** **364**

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Section 3(1)(x) – Mere utterance of word "kuriawale" without any intention shall not make out the offence under section 3(1)(x) of the SC/ST Act.

धारा 3(1)(10) – शब्द ''कुरिया वाले'' का बिना किसी आशय के उच्चारण करने मात्र से धारा 3 (1)(10) अधिनियम, 1989 का अपराध नहीं बनेगा। **275** **491**

SERVICE MATTER

सेवा संबंधी मामला

— Correction of date of birth.

– जन्म तिथि में सुधार। **172*** **313**

— Fundamental Rules:

Rule 56(3) – Compulsory retirement of a Govt. servant – All that is required for compulsorily retiring a Government servant, is the subjective satisfaction of the Government that such compulsory retirement is in the public interest.

The principles of compulsory retirement reiterated.

– मूलभूत नियमः

नियम 56 (3) – एक शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति – एक शासकीय सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए शासन का यह व्यक्तिनिष्ठ संतोष होना आवश्यक होता है कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति लोकहित में है।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सिद्धांत पुनः बतलाये गये। **276*** **491**

SICK INDUSTRIAL COMPANIES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1986

बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1986

Sections 22 and 26 – Maintainability of suit for declaration and injunction against sick company – The Civil Court was not right and justified in issuing injunction also.

धाराएं 22 और 26 – सिक कंपनी के विरूद्ध घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के वाद की पोषणीयता। व्यवहार न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करने में सही और न्याय संगत भी नहीं था। **67(ii)** **137**

SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

Sections 1(2) and 15 – Is there any bar for registration of marriage in case of inter-country marriage? Held, No.

धाराएं 1(2) और 15 – क्या अन्तर्देशीय विवाह के मामले में विवाह के पंजीकरण पर कोई बाधा होती है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **54** **119**

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Section 6 – See section 151 of the Civil Procedrue Code, 1908.

धारा 6 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151। **280*** **496**

Sections 9, 13(b), 16 (b) and 17 – (i) Suit for specific performance of agreement for sale of immovable property.

(ii) Discretionary relief of specific performance, entitlement of – He who seeks such relief must approach court with clean hands and there must not be any breach of the contract on his part.

धाराएं 9, 13 (बी), 16 (बी) और 17 – (i) अचल संपत्ति के विक्रय के अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद।

(ii) विनिर्दिष्ट पालन के वैवेकिय अनुतोष का अधिकार – वह जो ऐसा अनुतोष चाहता है उसे न्यायालय में स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और उसके भाग पर संविदा का कोई भंग नहीं होना चाहिए।

220 **413**

Section 10 – See sections 33 and 35 of the Stamp Act, 1899.

धारा 10 – देखें स्टाम्प अधिनिम, 1899 की धारा 33 और 35। **60*** **129**

Sections 10, 19(b), 20 and 38 – See section 96 and Order 2 Rule 2 of Civil Procedure Code, 1908, section 55 of the Contract Act, 1872 and Article 54 of the Limitation Act, 1963.

धाराएं 10, 19 (बी), 20 और 38 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 और आदेश 2 नियम 2, संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 55 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 54।

176 **316**

Sections 16 and 38 – See Order 39 Rules 1 and 2 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 16 और 38 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 39 नियम 1 और 2।

55* **120**

Sections 16 (c) and 20 – See Section 15 of the Contract Act, 1872.

धाराएं 16 (सी) और 20 – देखें संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15। **56*** **121**

Section 19 (b) – (i) Specific performance of agreement to sale – Failure of plaintiff to perform is part of contract, effect of.

(ii) section 19 (b) of Specific Relief Act – Protection to bonafide purchaser, availability of.

धारा 19(बी) – (i) विक्रय का विनिर्दिष्ट पालन – वादी द्वारा संविदा के उसके भाग का पालन करने में असफल रहने का प्रभाव।

(ii) धारा 19 (बी) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम – सदभावी क्रेता को संरक्षण उपलब्ध होना। **334 589**

Section 20 – (i) Subsequent rise in price of property – Will not be treated as a hardship entailing refusal of the decree for specific performance – The court may take notice of the above fact.

(ii) Looking to all the facts and circumstances of the case, the Court may impose any reasonable condition including payment of an additional amount by one party to the other while granting or refusing decree for specific performance.

धारा 20 – (i) संपत्ति की कीमत बाद में बढ़ गई – इसे ऐसा तकलीफदेह (या अपरिहार्य) नहीं समझा जाएगा कि इसके कारण विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया जाए। न्यायालय उक्त तथ्य को ध्यान में रख सकती है।

(ii) मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय कोई युक्तियुक्त शर्त अधिरोपित कर सकती है जिसमें अतिरिक्त राशि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति देते समय या उससे इंकार करते समय, देने की शर्त शामिल है। **114 210**

Section 20 – Plaintiff should not be denied specific performance only on account of phenomenal increase in price during the pendency of litigation – The court may impose reasonable conditions including payment of additional amount to the vendor.

धारा 20 – वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन से केवल इस कारण इंकार नहीं कर सकता कि विवाद लंबित रहने के दौरान संपत्ति की कीमतों में वृद्धि हुई है – न्यायालय क्रेता पर युक्तियुक्त शर्ते लगा सकती है जिसमें अतिरिक्त भुगतान की शर्त भी हो सकती है। **115 (iii) 211**

Section 34 – See section 27 and Articles 64 to 66 of the Limitation Act, 1963.

धारा 34 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 और अनुच्छेद 64 से 66। **57 122**

Section 34 – See Section 96 and Order 1 Rule 9 of the Civil Procedure Code, 1908 and Section 7 of the Hindu Marriage Act, 1955.

धारा 34 – देखे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 और आदेश 1 नियम 9 और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7। **28 60**

Sections 34 and 38 – Suit for declaration of title and perpetual injunction in respect of ancestral property – Absence of relief of possession, effect of.

धाराएं 34 और 38 – पैतृक सम्पत्ति के संबंध में स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद – आधिपत्य की सहायता के अभाव का प्रभाव। **58 124**

Section 38 – See Order 7 Rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 38 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 3। **124 221**

Section 41(b) – Injunction, non-issuance of – Injunction against institution of legal proceeding in a court not subordinate to that from which injunction is sought, cannot be granted.

धारा 41(बी) – निषेधाज्ञा जारी न किया जाना – उस न्यायालय में विधिक कार्यवाही संस्थित करने से रोकने की निषेधाज्ञा, जो उस न्यायालय का अधिनस्थ नहीं है जिससे निषेधाज्ञा चाही गई है, ऐसी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। **129** **231**

Section 53-A – Limitation for suit for specific performance of contract.

धारा 53–ए – संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद के लिए परिसीमा। **335*** **592**

STAMP ACT, 1899

स्टाम्प अधिनियम, 1899

Sections 33 and 35 – Insufficiently or unstamped documents – Court or authority receiving such documents in evidence, role of.

धाराएं 33 और 35 – अपर्याप्त रूप से या बिना स्टाम्प के दस्तावेज – न्यायालय या प्राधिकारी जो साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज प्राप्त करते है, उनकी भूमिका। **59** **126**

Sections 33 and 35 – Insufficiently stamped agreement to sale – Duty of Court – Law explained.

धाराएं 33 और 35 – विक्रय करार का अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित होना – न्यायालय का कर्त्तव्य – विधि स्पष्ट की गयी। **60*** **129**

STATE FINANCIAL CORPORATIONS ACT, 1951

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951

Section 29 – See Article 55 of the Limitation Act, 1963.

धारा 29 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 55। **212** **389**

SUCCESSION ACT, 1925

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

Section 63 – (i) Execution of Will – Suspicious and unnatural circumstances – How to appreciate?

धारा 63 – (i) विल का निष्पादन – संदेहास्पद व अस्वाभाविक परिस्थितियाँ – कैसे मूल्यांकन किया जाये। **116** **213**

Section 63 – Will – Execution and attestation, proof of.

धारा 65 – इच्छा पत्र (या विल) का निष्पादन और अनुप्रमाणन का प्रमाण। **336** **592**

Sections 371 and 372 – Jurisdiction of the Succession Court.

धाराएं 371 और 372 – उत्तराधिकार (प्रमाण पत्र देने वाले) न्यायालय का क्षेत्राधिकार । **221** **416**

TORTS :

दुष्कृति विधिः

– (i) Maxim res ipsa loquitor, applicability of.

(ii) Maxim res ipsa loquitor, objective of.

(i) सुक्ति रेस इप्सा लोकिटर का लागू होना।

(ii) सुक्ति रेस इप्सा लोकिटर का उद्देश्य। **173** **313**

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

Sections 5, 105 and 107 – Lease, renewal of – Renewal clause in lease deed, prospective nature and effect of.

धाराएं 5, 105 और 107 – पट्टे का नवीनीकरण – पट्टा विलेख में नवीनीकरण के अनुच्छेद की प्रकृति और उसका प्रभाव भविष्यलक्षी होना। **337** **594**

Sections 7, 8, 58, 60, 62, 72, 76(a) and 111(c) – (i) Lease by mortgagee – Redemption of mortgage, effect of – Law explained.

(ii) Doctrine of Bar against Clogs on Redemption, connotation and applicability of – Law explained.

धाराएं 7, 8, 58, 60, 62, 72, 76(ए) और 111 (सी) – (i) बंधक ग्रहिता द्वारा पट्टा – बंधक के विमोचन हो जाने पर प्रभाव – विधि समझाई गई।

(ii) विमोचन में अवरोध के बारे में – विधि समझाई गई। **219** **405**

Section 43 – Doctrine of feeding grant by estoppel, applicability of.

धारा 43 – फिडिंग ग्रांट बाय स्टोपल के सिद्धांत का लागू होना । **338** **596**

Section 52 – Doctrine of lis pendens, applicability of.

धारा 52 – वाद लंबन के सिद्धांत का लागू होना। **339** **598**

Section 53-A – See Section 12 (2) of the Land Acquisition Act, 1894 and Section 23 of the Contract Act, 1872.

धारा 53–ए – देखें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12(2) और संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23। **321** **571**

WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

Sections 2(12-A) and 50 (1)(c) – (i) Whether a forest guard is a forest officer?

(ii) Whether chemical examination of seized articles is necessary?

धाराएं 2 (12–ए) और 50 (1)(सी) – (i) क्या एक वनरक्षक वन अधिकारी होता है?

(ii) क्या जप्त सामग्री का रासायनिक परीक्षण आवश्यक होता है ? **61(ii)*** **131**

PART-III
(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1. Notification of Ministry of Finance regarding manner of disposal of seized Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Controlled Substances and Conveyances and officer authorized for disposal under the N.D.P.S. Act, 1985. 1

2. Important notifications of State Government under Indian Penal Code declaring offences cognizable & non-bailable & thereafter amendments in those notifications. 9

3. Notification dated 20.03.2015 of Ministry of Law and Justice (Department of Justice) regarding increase in the limit of value of the property in dispute for the purpose of determining jurisdiction of Permanent Lok Adalat. 11

4. Notification dated 13.04.2015 of Ministry of Law and Justice (Department of Justice) regarding the date of enforcement of the National Judicial Appointments Commission Act, 2014. 11

5. Notification dated 02.01.2015 regarding reduction/remitting Stamp duty on document. 12

6. Regarding referral of criminal cases in mediation process in the light of the Resolution of Main Mediation Monitoring Committee, State of M.P., dated 25.07.2015 33

I

PART-IV
(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1. Madhya Pradesh Dowry Prohibition Rules, 2004 1

2. Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme, 2015 9

3. The Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015 25

4. The Registration (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2014 27

5. The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Second Amendment) Ordinance, 2015 31

•

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Abdul Razzaq v. State of U.P.	AIR 2015 SC 1770	208*	386
Agricultural Produce Marketing Committee v. Bannamma (dead) by Legal Representatives	(2015) 5 SCC 691	338	596
Ahmed Shah and another v. State of Rajasthan	(2015) 3 SCC 93	147	257
Amrutlal Liladharbhai Kotak & ors. v. State of Gujarat	2015 (1) Crime 251 (SC)	156	286
Anand Sood v. Kanak Devi and others	2015 (2) MPLJ 317	203	366
Anand Trust v. Bar Council of India and another	2015 (3) MPLJ 677 (DB)	277	493
Anil Jain v. Shilpa Jain	2014 (IV) MPJR 185	133*	234
Anvar P. V. v. P. K. Basheer and others	AIR 2015 SC 180 (3 Judge Bench)	83	166
Arvind Kumar Jain v. Awnish Saxena and another	2014 (4) MPLJ 350 (DB)	60*	129
Ashish Kumar Mazumdar v. Aishi Ram Batra Charitable Hospital Trust and others	2015 (1) MPLJ 280 (SC) (3 Judge Bench)	173	313
Ashok Singh v. State of M.P. and another	2015 (1) MPHT 29	81*	163
Ashok v. State of Maharashtra	(2015) 4 SCC 393	205	375
Ashvinbhai Jayantilal Modi v. Ramkaran Ramchandra Sharma and another	2014 ACJ 2648 (SC)	50	107
Associate Builders v. Delhi Development Authority	(2015) 3 SCC 49	117*	215
Aadesh Singh Tomar and others v. State of M.P. and others	2015 (2) JLJ 274 (DB)	232	427
B. D. Khunte v. Union of India and others	(2015) 1 SCC 286 (3 Judge Bench)	89	177
Bablu Kumar and others v. State of Bihar and another	2015 AIR SCW 4655	298	530
Babulal & ors. v. State of M.P.	ILR (2014) MP 2481	192	346
Bachhulal Sharma & ors. v. State of Madhya Pradesh	2014 (IV) MPJR 148 (DB)	135	236
Bal Manohar Jalan v. Sunil Paswan and another	(2014) 9 SCC 640	20	38
Balu & ors. v. The state of Maharashtra	2015 (1) Crimes 181 SC	149	261
Baluram v. P. Chellathangam and others	AIR 2015 SC 1264	122*	221
Bane singh v. Bharat singh and others	2014 ACJ 2499	48	106
Banwari Singh Gurjar v. State of M.P. & anr.	ILR (2014) MP 3064	240*	444

Basappa v. T. Ramesh and another	2014 ACJ 2743 (SC)	49	106
Bhanushali Housing Co-operative Society Ltd. v. Mangilal and ors.	2015 AIR SCW 4479 (3 Judge Bench)	290*	512
Bharat Singh and another v. Madankunwar and others	2015 ACJ 43	100	193
Bholaram v. State of M.P.	2014 (5) MPHT 279	61*	130
Bivash Chandra Debnath @ Bivash D & others v. State of West Bengal	2015 (2) Crimes 317 (SC)	248*	455
C. Chandrasekaraiah v. State of Karnataka	2015 (2) Crimes 330 (SC)	273*	489
Central Bank of India v. Jagbir Singh	2015 ACJ 1513 (SC)	255	467
Chaitanya Prakash Audichya v. C.B.I.	2015 (3) Crimes 72 (SC)	271	487
Chaman Lal v. State of Punjab and others	AIR 2014 SC 3640	6	15
Chandaram v. Swapnil and others	2014 ACJ 2665	42	95
Chanderi Devi and anr. v. Jaspal Singh and ors.	2015 ACJ 1612 (SC)	256	469
Chandra Babu alias Moses v. State, Through Inspector of Police & others	2015 AIR SCW 4976	293	518
Chandrakant & ors. v. Tikam Das & ors.	ILR (2015) MP 181	285	509
Common Cause and others v. Union of India and others	2015 CriLJ 2935 (SC) (3 Judge Bench)	301*	535
D.T. Virupakshappa v. C. Subash	AIR 2015 SC 2022	236	438
Dabbal and others v. Oriental Insurance Co. Ltd. & anr.	2015 ACJ 1815	326*	582
Damayanti Devi (Smt.) and others v. Munna Shah and others	2014 (3) JLJ 145 (DB)	12	24
Darga Ram @ Gunga v. State of Rajasthan	AIR 2015 SC 1016	160	291
Dashrath and another v. Deceased Raju Bai and another	2014 (5) MPHT 158	9*	20
Daulatram v. Rameshwar Sharma and others	2014 ACJ 2525	46	102
Deepak Bhandari v. Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Limited	(2015) 5 SCC 518	212	389
Deepak v. State of Haryana	(2015) 4 SCC 762	189*	340
Deepak Vishwakarma v. State of M.P.	2014 (IV) MPJR SN 29	136*	237
Devidas Ramachandra Tuljapurkar v. State of Maharashtra and others	(2015) 6 SCC 1	288*	512
Dharam Das Rai v. Chief Municipal Officer & anr.	ILR (2014) MP 1794	128	229
Dharmendra Singh and anr. v. Naggaji	2015 (II) MPWN 50	227*	421

Dilip Sagorkar (Dead) Through L.R. v. State of M.P.	ILR (2014) MP 2694 (DB)	270*	486
Dilip v. State of Madhya Pradesh	ILR (2014) MP 1465 (SC)	96	186
Dinesh Tiwari v. State of U.P. and another	AIR 2014 SC 3502	18	36
Dipanwita Roy v. Ronobroto Roy	AIR 205 SC 418	84	167
Enercon (India) Ltd. & ors. v. Enercon GMBH & anr.	AIR 2014 SC 3152	3	5
Fatehji and Company and another v. L. M. Nagpal and others	(2015) 8 SCC 390	335*	592
Firoz v. State of M.P.	2015 (1) MPWN 111	138	239
G. Manikyamma & others v. Roudri Co-operative Housing Society Ltd. and others	AIR 2015 SC 720	112*	208
Gariba alias Naresh alias Ramnaresh and others v. State of Madhya Pradesh	2014 CriLJ 4383	19	37
Gendalal and anr. v. Chagganlal and anr.	2015 (3) MPHT 89	230*	425
Ghanshyam Chandil v. Ramkatori Agrawal	2015 (3) MPLJ 181	224	418
Ghanshyam Sarda v. M/s. Shiv Shankar Trading Co. and others	AIR 2015 SC 403	67	137
Ghusabhai Raisangbhai Chorasiya and others v. State of Gujarat	2015 CriLJ 3613 (SC)	315	563
Gulab Bai and others v. State of M.P. and another	2015 RN 350 (HC)	323	574
Guman Singh v. State of M.P.	ILR (2014) MP 3059 (DB)	235*	437
Gurjant Singh v. State of Punjab	(2015) 8 SCC 650	330	584
Gurudwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala and another	2014 (4) MPHT 389 (SC)	57	122
Gyanesh v. Central Bureau of Investigation and anr.	ILR (2015) MP 3274	309	548
H. Dohil Constructions Company Private Limited v. Nahar Exports Limited and another	(2015) 1 SCC 680	68	140
Habib Khan v. Shahjad Bi	ILR (2014) MP 1517	105	199
Hakkim v. State Represented by Deputy Superitendent of Police	2015 (1) Crimes 205 (SC)	162	295
Hari Singh & ors. v. Kailash & anr.	ILR (2014) MP 2168	211	388
Haribabu and anr. v. Himmat Singh and ors.	ILR 2014 MP 3160 (DB)	325	580
HDFC Bank Ltd. v. Kumari Reshma and ors.	AIR 2015 SC 290 (3 Judge Bench)	101	194
Himmat Singh v. CBN through Ashish Chakrawarti	2015 (II) MPWN 66	241	444

Inayat v. Adarsh Vyapari Sakh Sahkarita Myd.	2015 (1) MPWN 113	137	238
Inspector of Police and another v. Battenapatla Venkata Ratnam and another	2015 CriLJ 2942 (SC)	246	450
J.V. Baharuni and another v. State of Gujarat and another	2015 (2) MPLJ 490 (SC)	217	397
Jag Mohan Tripathi v. Babaannapurna Das Katthiya Baba	ILR (2014) MP 2311	221	416
Jagdish Chand Sharma v. Narain Singh Saini (dead) thru LRs. & others	AIR 2015 SC 2149	336	592
Jai Krishan (d) through L.Rs. v. State of Uttarakhand & others	AIR 2014 SC 3578	39	86
Jaiminiben Hirenbhai Vyas and another v. Hirenbhai Rameshchandra Vyas and another	AIR 2015 SC 300	75	152
Jakir Hussein and others v. Dinesh and others	2015 ACJ 961 (MP)	215	394
Jakir Hussein v. Sabir and others	2015 ACJ 721	216	396
Jamuna Prasad v. Balkishan & ors.	2014 (IV) MPJR SN 19	126*	223
Jasbir Singh @ Javri @ Jabbar Singh v. State of Haryana	(2015) 5 SCC 762	254*	465
Jeevanlal Rathore v. Deepchand & ors.	ILR (2014) MP 3263	287*	511
Jitendra @ Jeetu and others v. State of M.P.	2014 (5) MPHT 45 (DB)	92*	181
Jitendra Khimshankar Trivedi and others v. Kasam Daud Kumbhar and others	2015 ACJ 708 (SC)	102	195
Jogendra Yadav & others v. State of Bihar	2015 AIR SCW 4517	295	520
Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori and anr.	(2014) 10 SCC 736	165	300
K. Prakash v. B.R. Sampath Kumar	AIR 2015 SC 9	114	210
Kadarilal v. State of M.P. and others	2015 (2) JLJ 171 (SC)	274	489
Kallappa Mallappa Kamble v. State of Karnataka	2015 (1) Crimes 294 (SC)	170	309
Kanaklata v. State (NCT of Delhi) and others	(2015) 6 SCC 617 (3 Judge Bench)	299	531
Kanchanben Purshottambhai Bhanderi v.State of Gujarat	2015 (1) Crimes 177 (SC)	152	275
Kanhsingh and another v. Tukaram and others	2015 ACJ 594 (SC)	104	197
Karan Lal v. Charan Lal	ILR (2015) MP 164	328*	583
Karanveer Rana v. State of M.P.	ILR (2014) MP 2418 (DB)	218*	404
Karedla Parthasaradhi v. Gangula Ramanama (d) through LRs. and others	AIR 2015 SC 891	71	146

Karnail Kaur and others v. State of Punjab and others	(2015) 3 SCC 206	171	310
Kedarnath Neekhra and another v. Suprabhat Grih Niraman Sahkari Sanstha Marayadit, Shivpuri and another	2014 (4) MPLJ 192	11*	23
Kedarilal v. State of M.P. and others	2015 (2) JLJ 171 (SC)	274	489
Keshav Chouhan v. Kiran Singh	ILR (2014) MP 2744	269	484
Khenyei v. New India Assurance Co. Ltd.and others	2015 ACJ 1441 (SC) (3 Judge Bench)	259*	472
Kiran v. Sajjan Singh and others	2014 ACJ 2550 (SC)	51	108
Kirti Pal and ors. v. State of West Bengal and ors.	2015 (3) Crimes 11 (SC)	249	456
Kishanlal v. Ashok Kumar and another	2014 (4) MPLJ 392	56*	121
Kodar Singh v. State of M.P. & anr.	ILR (2014) MP 3190	322	573
Komal Tyagi and another v. State of M.P. another	2015 (II) MPWN 140	275	491
Krishna Texport & Capital Markets Ltd. v. Ila A. Agrawal and others	AIR 2015 SC 2091	268	483
Krishnanand and ors. v. State of M.P. and ors.	2015 (1) MPLJ 347 (DB)	164	298
Kuldeep Kumar Dubey and others v. Ramesh Chandra Goyal (dead) through Legal Representatives	(2015) 3 SCC 525	120*	219
Kulwant Singh and others v. Oriental Insurance Co. Ltd.	2014 ACJ 2873 (SC)	47	104
Kulwant Singh v. State of M.P. & ors.	ILR (2014) MP 3153	339	598
Kulwinder Singh and another v. State of Punjab	(2015) 6 SCC 674	260	473
Kunwarpal @ Surajpal & ors. v. State of Uttarakhand and anr.	2015 (1) Crime 217 (SC)	134	235
Lalitha Theresa Sequeria (since died) by L.Rs v. Dolfy A Pias alias Adolphys Joseph Pais and anr.	(2014) 10 SCC 731	140	245
Laxmikant v. State of M.P.	2014 (5) MPHT 143 (DB)	110	206
Laxminarayan v. Munnibai	2015 (3) MPLJ 401	226*	420
Leela Rajagopal & ors. v. Kamala Menon Cocharan & ors.	AIR 2015 SC 107	116	213
M.P. Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. v. Kalyan Singh Chauhan and others	2015 (1) MPLJ 589	141	247
M.P. Veneer and Plywood Ltd. v. State of M.P. and another	2015 (3) MPLJ 299	223*	417

M/s Bhandari Udyog Limited v. Industrial Facilitation Council and another	AIR 2015 SC 1320	175*	316
M/s Hyder Consulting (UK) Ltd. v. Governor, State of Orissa through Chief Engineer	AIR 2015 SC 856 (3 Judge Bench)	66	136
M/s Sherali Khan Mohamed Manekia v. The State of Maharashtra and ors.	AIR 2015 SC 1394	182	330
M/s. Bhagwati Vanaspati Traders v. SeniorSuperintendent of Post Offices, Meerut.	AIR 2015 SC 901	73*	150
M/s. Harsha Construction v. Union of India & ors.	AIR 2015 SC 270	64	132
M/s. MSP Infrastructure Ltd. v. M.P. Road Devl. Corp. Ltd.	AIR 2015 SC 710	65	133
M/s. Sundram Finance Limited and another v. T.Thankam	AIR 2015 SC 1303	174*	315
Madhya Pradesh State Legal Services Authority v. Prateek Jain and another	2014 (3) JLJ 243 (SC)	40	87
Madras Bar Association v. Union of India and another	AIR 2015 SC 1571 (5 Judge Bench)	186	334
Mahendra Gupta v. Mohd. Yunus	ILR 2014 MP 2284	177	326
Mahesh Chandra v. Anokhilal & ors.	ILR (2014) MP 2156	213	391
Mahesh v. Harisingh and others	2015 (2) MPLJ 101	179	327
Mahipal Singh Bhati v. Nisar Mohd. & ors	ILR (2014) MP 2125	214	392
Mainuddin Abdul Sattar Shaikh v. Vijay D. Salvi	2015 (II) MPWN 139 (SC)	266	481
Major Singh &another v. State of Punjab	2015 CriLJ 2593 (SC) (3 Judge Bench)	250	459
Mallella Shyamsunder v. State of A. P.	(2015) 2 SCC 486	90	179
Manik Taneja & anr. v. State of Karnataka & anr.	2015 (1) Crime 221 (SC)	157	287
Manish v. K.G. Sharma	2015 (2) MPHT 137	167*	305
Manoj Jain v. Smt. Suman Goyal	2014 RN 410	8*	19
Meera Bai v. Ramesh Guru and another	2014 (4) MPLJ 516	28	60
Mofil Khan and another v. State of Jharkhand	(2015) 1 SCC 67 (3 Judge Bench)	139	240
Mohammad Juned @ Zaved v. State of M.P.	Criminal Revision No.645 of 2013 (Unreported Order)	196	352
Mohan Lal v. State of Rajasthan	AIR 2015 SC 2098	261	476
Mount Mary Enterprises v. Jivratna Medi Treat Pvt. Ltd.	2015 (3) MPLJ 494 (SC)	284*	508

Mr. Robert John D'Souza and others v. Mr. Stephen V. Gomes and another	2015 (3) Crimes 160 (SC)	319	570
Mrs. Priyanka Srivastava and another v. State of U.P.and others	2015 (2) Crimes 209 (SC)	190	342
Mukesh Kumar and others v. State of M.P. and another	2015 (2) JLJ 49	195	350
Mukesh v. State of Chhattisgarh	(2014) 10 SCC 327	24	47
Municipal Corporation, Dewas v. Sagarmal and others	2015 (2) MPLJ 274	180*	328
Munna Lal Jain and another v. Vipin Kumar sharma and others	(2015) 6 SCC 347 (3 Judge Bench)	258	470
Munni Devi (Smt.) v. Shanti Kumar and others	2014 RN 428	58	124
Murarilal v. Ram Kumar Ojha & anr.	ILR (2014) MP 2162	183	332
Nagaraja Rao v. Central Bureau of Investigation	(2015) 4 SCC 302	188*	339
Nagraj v. State Represented by Inspector of Police, Salem Town, Tamil Nadu	(2015) 4 SCC 739	194	348
Nand Kumar and others v. State of Chhattisgarh and others	2014 (5) MPHT 365 (SC)	93*	182
Nanda Gopalan v. State of Kerala	2015 (3) Crimes 55 (SC)	253	465
Nandlal & 2 ors. v. State of M.P. & anr.	2014 (IV) MPJR 159	121	219
Nanjappa v. State of Karnataka	2015 AIR SCW 4432	332	586
Nar Singh v. State of Haryana	AIR 2015 SC 310	79	159
Narayan Singh v. Kallaram @ Kalluram Kushwaha & ors.	2015 (2) MPLJ 337	201	364
Narendra v. State of Rajasthan	2014 CriLJ 4396 (SC)	32	68
Naresh Kumar v. State of Haryana and others	(2015) 1 SCC 797	94	184
Narsingh and others v. Shripat Singh and others	2014 (5) MPHT 203	25	49
National Insurance Co. Ltd. v. Harpal Singh & ors.	ILR (2015) MP 168	327*	582
Naveen Gupta v. State of M.P.	ILR (2014) MP 2701	252*	464
Navodaya Mass Entertainment Limited v. J. M. Combines	(2015) 5 SCC 698	278	494
Nayankumar Shivappa Waghmare v. State of Maharashtra	2015 CriLJ 3422 (SC)	272*	488
Nirmal Singh etc. v. State of Haryana	AIR 2015 SC 453	99	190
Nitin Khandelwal v. Manjul & others	2015 (3) MPLJ 354	262*	478

O.M. Cherian alias Thankachan v. State of Kerala and others	AIR 2015 SC 303 (3 Judge Bench)	74	150
Oil and Natural Gas Corporation Limited v. Official Liquidator of Ambica Mills Company Limited and others	(2015) 5 SCC 300	184*	333
Oil and Natural Gas Corporation Limited v.Western GECO International Limited	(2014) 9 SCC 263	4	10
Om Aggarwal v. Haryana Financial Corporation and others	(2015) 4 SCC 371	178*	327
Om Prakash (Dead) Th. his LRs. v. Shanti Devi and others	AIR 2015 SC 976	144	253
Om Prakash Chautala v. Kanwar Bhan and others	2014 (4) MPLJ 46	2	3
Oriental Insurance Co. Ltd. v. Kalawati and others	2014 ACJ 2772	43	96
Padmakumari and others v. Dasayyan and others	(2015) 8 SCC 695	334	589
Pargan Singh v. State of Panjab and another	2014 (4) Crimes 10 (SC)	23	46
Parhlad and another v. State of Haryana	2015 AIR SCW 4512	316	565
Pathubha Govindji Rathod and another v. State of Gujarat	(2015) 4 SCC 363	204	373
Pawan Kumar Pathak v. Mohan Prasad	2015 (3) MPLJ 148	228	421
Pemmada Prabhakar and others v. Youngmen's Vysya association and others	(2015) 5 SCC 355	220	413
Phool Patti and another v. Ram Singh (Dead) through LR's and another	(2015) 3 SCC 164	113	209
Pooja Ravinder Devidasani v. State of Maharashtra & anr.	AIR 2015 SC 675	108	202
Pradumna v. State of M.P.	2015 (2) MPHT 166	161	293
Pramod Kumar v. Saiyad Rajiy Sultan and others	2015 (3) MPHT 112	225*	420
Praveen Dubey v. Ravishankar and others	2014 (5) MPHT 259	21*	40
Preetam Lodhi v. State of M.P.	2015 (2) MPHT 163	146	256
Prem Kumar Gulati & another v. State of Haryana & another	2015 (2) Crimes 247 (SC)	200*	363
Prempal v. State of Haryana	2014 CriLJ 4420	34	70
Pulsive Technologies P.Ltd. v. State of Gujarat & ors.	2015 CriLJ 283 (SC)	107	201
Purushottam Dashrath Borate & anr. v. State of Maharashtra	2015 CriLJ 2862 (SC) (3 Judge Bench)	296*	521

R. Dineshkumar alias Deena v. State Rep. by Inspector of Police & ors.	AIR 2015 SC 1816	202	365
R. Rajanna v. S.R. Venkataswamy and others	AIR 2015 SC 706	72	149
R.N. Agarwal v. R.C. Bansal and others	(2015) 1 SCC 48	169	307
Radhey Shyam and another v. Chhabi Nath and others	(2015) 5 SCC 423	185*	334
Raghuvendra v. State of M.P..	AIR 2015 SC 704	91*	180
Raj Singh v. State of Haryana Etc.	2015 CriLJ 2803 (SC) (3 Judge bench)	245*	450
Rajasthan Housing Board v. New Pink City Nirman Sahkari Samiti Limited and another	(2015) 7 SCC 601 (3 Judge Bench)	321	571
Rajeev Lochan Singh v. State of MP	2014 (3) JLJ 130 (DB)	26	51
Rajendra Singh & anr. v. State of M.P.	ILR (2014) MP 2709	238	440
Rajesh Kumar Tripathi and another v. State of M.P. and others	2014 (3) JLJ 446	54	119
Rajesh Mishra v. Ram Villas Singh Kushwaha	2015 (2) JLJ 101	181	329
Rajib Ranjan and others v. R. Vijay Kumar	(2015) 1 SCC 513	76	153
Rajinder Singh v. State of Punjab	(2015) 6 SCC 477 (3 Judge Bench)	251	461
Rajiv Chowdhrie HUF v. Union of India and others	(2015) 3 SCC 541 (3 Judge Bench)	163	296
Rajmal Agarwal v. Dinesh Sahu	2015 (3) MPLJ 69	263	478
Raju alias Devendra Choubey v. State of Chhattisgarh	(2014) 9 SCC 299	30	64
Rakesh and another v. State of U.P. and another	AIR 2014 SC 3509	17	34
Ramaiah alias Rama v. State of Karnataka	(2014) 9 SCC 365	37	82
Ramakant Mishra alias Lalu and others v. State of Uttar Pradesh	(2015) 8 SCC 299	314	557
Ramanlal & anr. v. State of Haryana	2015 CrLR (SC) 780	310	550
Ramdev Food Products Pvt. Ltd. v. State of Gujarat	AIR 2015 SC 1742 (3 Judge Bench)	233	429
Ramjivan and others v. Satyanarayan and others	2015 RN 322	229*	425
Ramkali Devi (Mahila) and others v. Nandram (D) through LRs. and others	2015 (2) JLJ 326 (SC)	324	576
Ramnarayan & ors. v. Arvind & ors.	2014 (IV) MPJR 161	129	231
Ramraj Patel and another v. Hiralal Patel and others	2015(3) MPLJ 606	308	547

Ramshankar v. Guru Singh Sabha	ILR (2014) MP 1541	62*	131
Ramvilash and another v. Omprakash and others	2014 (5) MPHT 177	14	29
Ranjeet Kumar Ram alias Ranjit Kumar Das v. State of Bihar	2015 CriLJ 2944	305	543
Ranjit Singh v. Sugan Bai	2014 (IV) MPJR 176 (DB)	145	254
Rathnavathi and another v. Kavita Ganashamdas	(2015) 5 SCC 223	176	316
Ratnesh Kumar Pandey v. State of Uttar Pradesh	(2015) 3 SCC 536	148	259
Raveesh Chand Jain v. Raj Rani Jain	(2015) 8 SCC 428	279*	495
Ravi Prakash Singh alias Arvind Singh v. State of Bihar	AIR 2015 SC 1294	191*	345
Roxann Sharma v. Arun Sharma	AIR 2015 SC 2232	307	545
Ruaab Ahmed v. State of M.P.	2014 (5) MPHT 129	82	164
S.M. Asif v. Virender Kumar Bajaj	2015 AIR SCW 4936 (3 Judge Bench)	286*	511
S.R. Sukumar v S. Sunaad Raghuram	2015 CrLR (SC) 769	294	518
Sachin v. State of H.P.	2015 CriLJ (NOC) 157 (H.P.)	95*	185
Safal Investment Ltd. Mumbai and others v. Vibgyor Laminates Pvt. Ltd. Indore	2014 (4) MPLJ 466	52*	111
Sameer Singh and another v. Abdul Rab and others	(2015) 1 SCC 379	127	224
Sandhya and others v. Guddu and others	2015 ACJ 168	103	196
Sanjaysinh Ramrao Chavan v. Dattatray Gulabrao Phalke and others	(2015) 3 SCC 123	143	250
Santosh v. State of Maharashtra	(2015) 7 SCC 641 (3 Judge Bench)	312*	555
Saqib Khan v. Ravindra Suri	2014 (4) MPLJ 606	1	1
Saraswatibai (Smt.) & two ors. v. Asha (Smt.)	2014 (IV) MPJR 158	125	223
Saroj Garg (Smt.) & anr. v. Aparna Gupta & anr.	ILR (2015) MP 64	282	501
Satish Kumar Khandelwal v. Rajendra Jain and others	2014 RN 415 (DB)	55*	120
Satwantin Bai v. Sunil Kumar & anr.	2015 (2) Crimes 234 (SC)	197	358
Satya Pal Anand v. Bal Niketan Nyas, Bhopal and others	2015 (3) MPLJ 83 (DB)	231	426

Saya Jeet v. Balle Singh and others	2014 (5) MPHT 339	13*	28
Shabnam Hashmi v. Union of India and others	2014 (5) MPHT 244 (SC) (3 Judge Bench)	38	85
Shabnam v. State of Uttar Pradesh	(2015) 6 SCC 632 (3 Judge Bench)	303*	540
Shalini v. Kishor and others	2015 CriLJ 3610 (SC)	333*	589
Shambhu Singh v. Totaram (Dead) through LRs. and others	2015 RN 488 (HC)	281	496
Shamima Farooqui v. Shahid Khan	(2015) 5 SCC 705	242	445
Shanti Lal Meena v. State (NCT of Delhi), Central Bureau of Investigation	(2015) 6 SCC 185	302	536
Sharad Kumar Sanghi v. Sangita Rane	2015 (1) Crime 271 (SC)	159	290
Shashi Mohan Dwivedi and another v. Ganesh and others	2014 ACJ 2725	44	99
Shashikala Bai (Smt.) v. Mahendra Singh	2014 (IV) MPJR 164	132*	234
Shasidhar and others v. Smt. Ashwini Uma Mathad and another	AIR 2015 SC 1139	131	233
Sher Singh alias Partapa v. State of Haryana	2015 CriLJ 1118 (SC)	153*	276
Shiv Kumari Gulhani (Smt.) & ors. v. District and Sessions Judge, Mandla	2015 (II) MPJR 279 (DB)	276*	491
Shivdayal v. Meenabai and others	2014 (5) MPHT 306	7	17
Shreya Singhal v. Union of India	AIR 2015 SC 1523	207	378
Shruti Gupta v. United India Insurance Co. Ltd. & anr.	2015 ACJ 1755	329*	583
Shyambabu Kirar v. State of M.P. & others	2015 (III) MPWN 10	306	545
Siva Vallabhaneni v. State of Karnataka and another	(2015) 2 SCC 90	97*	188
Siyaram v. Devkuwar and others	2014 ACJ 2473	45	101
Smt. Manisha Lalwani v. Dr. D. V. Paul	AIR 2015 MP 20	70	145
Smt. Shakuntala Bai v. Rajendra Kumar and others	2014 (5) MPHT 417	10	21
Sneh Farms and Agro Products Ltd., Indore and another v. Pankaj Agrawal and another	2014 (3) JLJ 200	59	126
Sonali Thanawala (Smt.) v. M/s. Rahul Ginning Industries & ors.	ILR (2014) MP 2739	267	482
Sri Gangai Vinayagar Temple and another v. Meenakshi ammal and others	(2015) 3 SCC 624 (3 Judge Bench)	118*	216

Srihari (Dead) through Legal Representative Ch. Niveditha Reddy v. Syed Maqdoom Shah and others	(2015) 1 SCC 607	69	143
State (NCT of Delhi) v. Sanjay	(2014) 9 SCC 772	36	76
State of Haryana v. Asha Devi and another	(2015) 8 SCC 39	304	541
State of Karnataka v. Suvarnamma and another	(2015) 1 SCC 323	155	281
State of M.P. v. Maharani Ushadevi	2015 RN 461 (SC)	289*	512
State of M.P. and others v. Satish Shrivastava	2014 (5) MPHT 133 (DB)	98*	189
State of M.P. v. Mehtaab	(2015) 2 SCC (Cri) 764	297*	529
State of M.P. & ors. v. Rajendra Kumar Goyal& anr.	2015 (II) MPJR 34	210	387
State of M.P. v. Rakesh Mishra	2015 (2) JLJ 283 (SC)	237	439
State of M.P. v. Shivshankar	(2014) 10 SCC 366	31	65
State of M.P. v. Yogenda alias Jogendra Singh	2015 (2) MPHT 102 (DB)	150	264
State of Madhya Pradesh v. Madanlal	2015 CrLR (SC) 792	318*	569
State of Madhya Pradesh v. Anoop Singh	2015 CrLR (SC) 788	317*	567
State of Madhya Pradesh v. Bablu	(2014) 9 SCC 281	22	42
State of Madhya Pradesh v. Deepak and others	2014 CriLJ 4509	35	73
State of Madhya Pradesh v. Maiyadeen & ors.	ILR (2015) MP 200	311*	554
State of Madhya Pradesh v. Surendra Singh	AIR 2015 SC 398	87	170
State of Madhya Pradesh v. Vipin Goyal	M.Cr.C.No. 10945 of of 2015 (DB) (Unreported Order)	234*	436
State of Punjab v. Saurabh Bakshi	(2015) 5 SCC 182	206*	377
State of Rajasthan v. Chandgi Ram and others	2014 (4) Crimes 42 (SC)	16	32
State of West Bengal & others v. Associated Contractors	AIR 2015 SC 260 (3 Judge Bench)	63*	131
State of West Bengal and others v. Calcutta Mineral Supply Company Private Limited and another	(2015) 8 SCC 655	337	594
State Throught Inspector of Police v. A. Arun Kumar and another	(2015) 2 SCC 417	111	208
Sukhjit Singh v. State of Panjab	2015 (2) Crimes 265 (SC)	193*	347
Sukra Bai v. Makhan Gir Mahant	2015 (2) MPLJ 113 (DB)	209*	386
Suku v. Jagdish and another	AIR 2015 SC 1006 (3 Judge Bench)	168*	306

Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation	AIR 2015 SC 923	88	171
Sunita Dubey v. Hukum Singh Ahirwar	2015 (1) MPLJ 574	166	304
Sunita Kachwaha and others v. Anil Kachwaha	2014 (3) JLJ 404	15*	31
Surajmal & ors. v. Harinarayan & ors.	2014 (IV) MPJR SN 15	130	232
Surendra Patel and another v. Ritu @ Vandana Patel	2014 (4) MPHT 334 (DB)	29	63
Suresh & anr. v. State of Haryana	AIR 2015 SC 518	80	5
Surinder Pal Kaur and another v. Satpal and another	2015 CriLJ 3821 (SC)	291	514
Sushil Kumar Dey Biswas and another v. Anil Kumar Dey Biswas and another	2015 (3) MPLJ 533 (SC) (3 Judge Bench)	280*	496
Swan Gold Mining Limited v. Hindustan Copper Limited	(2015) 5 SCC 739	222	417
Swatantra Tripathi v. State of M.P. & anr.	2015 (II) MPJR SN 22	239	442
T. Vasanthakumar v. Vijayakumari	2015 CriLJ 2853 (SC)	265	480
Tajender Singh Ghambhir and anr. v. Gurpreet Singh and ors.	(2014) 10 SCC 702 (3 Judge Bench)	119*	218
Tanua Rabidas v. State of Assam	2014 CriLJ 4514	33	70
Tarabai v. State of Maharashtra	(2015) 3 SCC 530	154	279
Tarun Kadam and another v. State of M.P. and another	2014 (5) MPHT 310 (DB)	27	58
Tejram Patil v. State of Maharashtra	2015 (1) Crime 275 (SC)	142	249
Thakar Singh (Dead) by Legal Representatives and another v. Mula Singh (Dead) Through Legal Representative and others	(2015) 5 SCC 209	219	405
United India Insurance Co. Ltd. v. Veereshwar Singh and others	2015 (3) MPLJ 117	257	470
Usha Ajay Singh (Smt.) v. Shri J.L. Mishra	ILR (2015) MP 260	320*	571
Uttam v. Saubhag Singh & ors.	ILR (2014) MP 1593	86*	170
V. Sreeramachandra Avadhani (D) v. by L.Rs. Shaik Abdul Rahim and another	AIR 2014 SC 3464	41	94
V.K. Mishra & another v. State of Uttarakhand and another	2015 AIR SCW 4443 (3 Judge Bench)	292*	515
Vasanta Sampat Dupare v. State of Maharashtra	(2015) 1 SCC 253	151	267
Veenita Bai v. Dinesh Kumar	2015 (2) MPLJ 576	243	447

Vidhya Viswanathan v. Kartik Balakrishnan	AIR 2015 SC 285	85	169
Vijay Kumar Gupta v. Pankaj Sharma	2015 (2) JLJ 289	264	479
Vijay Pal Singh and others v. State of Uttarakhand	AIR 2015 SC 684	77	155
Vijay Pal v. State (GNCT) of Delhi	AIR 2015 SC 1495	198	360
Vijay Thakur v. State of Himachal Pradesh	2015 (2) Crimes 254 (SC)	199*	362
Vikash Raghuvanshi v. State of M.P. & anr.	ILR (2015) MP 268	300	533
Vikram Singh alias Vicky and another v. Union of India and others	2015 AIR SCW 4940 (3 Judge Bench)	313*	556
Vinay Kumar Shailendra v. Delhi High Court Legal Services Committee and anr.	2015 CriLJ 166 (SC) (3 Judge Bench)	106	200
Vinita S. Rao v. Essen Corporate Sevices Private Limited and another	(2015) 1 SCC 527	109	203
Vinod Chandra Semwal v. Special Police Establishment, Ujjain	2015 CriLJ 3606 (SC)	331	586
Vinod Kumar Subbiah v. Saraswathi Palaniappan	2015 (2) MPWN 44 (SC)	244*	449
Vinod Kumar v. State of Haryana	(2015) 3 SCC 138	158	288
Vinod Kumar v. State of Punjab	(2015) 3 SCC 220	78	157
Vishwa Lochan Madan v. Union of India and others	AIR 2014 SC 2957	5	13
Vutukuru Lakshmaiah v. State of Andhra Pradesh	2015 (2) Crimes 349 (SC)	247	252
Western Coalifields Ltd. (The) & anr. v. Faggulal	2014 (IV) MPJR SN 16 (DB)	172*	313
Y. Sleebachen and others v. State of Tamil Nadu through Superintending Engineer Water Resources Organization/ Public Works Department and another	(2015) 5 SCC 747	283	502
Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey and another	2014 (5) MPHT 208 (SC) (3 Judge Bench)	53	112
Yunus Zia v. State of Karnataka & anr.	2015 (2) Crimes 219 (SC)	187	338
Zarif Ahmad (D) Thr. LRs. & anr. v. Mohd. Farooq	AIR 2015 SC 1236	124	221
Zarina Siddiqui v. A. Ramalingam alias R. Amarnathan	AIR 2015 SC 580	115	211